हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.05 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

13.3.2015/1105/jt/av/1

प्रश्न संख्या : 1475

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 1475, श्री बिक्रम सिंह जरयाल।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 1517

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 1517, श्री महेन्द्र सिंह।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 1518

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 1518, श्री गोविन्द सिंह ठाकुर।
(अनुपस्थित)

13.3.2015/1105/jt/av/2

प्रश्न संख्या : 1519

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के मुताबिक ऐग्जैक्टिव ऑफिसर 1, क्लर्क 1, सेनिटरी सुपरवाइजर 1, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर 1, चौकीदार 1 और सफाई कर्मचारी की 2 पोस्टें खाली है। मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि ये पोस्टें अभी से खाली नहीं है बल्कि यह काफी अर्से से खाली पड़ी है और ये फिलअप नहीं हुई। मेरा यह आग्रह रहेगा कि इन पोस्टों को प्रायोरिटी बेसिज पर भरने के आदेश दिए जाएं। दूसरी ,जो अनस्पैंट मनी दर्शाई गई है। खासकर पार्किंग के लिए 29 लाख के करीब और सुलभ शौचालय तथा पार्किंग के लिए लगभग 31 लाख रुपये के करीब राशि दर्शाई गई है। यह पैसा भी मेरी सूचना के मुताबिक काफी अर्से से अनस्पैंट पड़ा है। हमारे वहां पार्किंग की बहुत दिक्कत है इसलिए आप पार्किंग बनाने हेतु आदेश दें। जहां के लिए सुलभ शौचालय और

पार्किंग बनानी निश्चित की गई है वहां के लिए आप जल्दी से यह राशि व्यय करने के आदेश दें। मेरा आपसे यही आग्रह है।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पार्किंग के फण्ड्ज की बात की है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि रोहड़ू की पार्किंग एच.पी.आई.डी.बी. के माध्यम से पी.पी.पी. के अंतर्गत बनाई जा रही है। जहां तक आपने पुरानी धनराशि की बात की है तो उसको उस पार्किंग के अतिरिक्त रोहड़ू में डिसैंटरेलाइज पार्किंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जायेगा। इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। यह राशि इसीलिए खर्च नहीं हो पाई क्योंकि जो यह प्रोजैक्ट बनेगा उसमें यह धनराशि व्यय होनी थी। दूसरे, आपने जो रिक्त पदों की बात की है तो अभी आपके ई.ऑ. का चार्ज तहसीलदार के पास है। केवल आपकी रोहड़ू नगर परिषद की ही बात नहीं है बल्कि प्रदेश में काफी जगह पर कुछ पद रिक्त पड़े हैं। इनके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी सहमति दी है कि इनको भरने के लिए हम शीघ्र प्रयास करेंगे। मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि इनको जल्दी ही भर दिया जायेगा।

समाप्त

13.3.2015/1105/jt/av/3

प्रश्न संख्या : 1520

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 1520, श्री सतपाल सिंह सत्ती।

(अनुपस्थित)
श्री गुलाब सिंह ठाकुर।
(अनुपस्थित)
श्री जय राम ठाकुर।
(अनुपस्थित)
श्री हंस राज।
(अनुपस्थित)
श्री इन्द्र सिंह।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या : 1521

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 1521, श्री सतपाल सिंह सत्ती।
(अनुपस्थित)

अगला प्रश्न श्री बी.जे.द्वारा जारी

13.3.2015/1110/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः 1522.

श्री बम्बर ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जानना चाहा था कि हमारी सरकारों ने भाखड़ा-बांध विस्थापितों के जो ऋण थे, वो कितनों के माफ किये और किस सरकार ने उन ऋणों को माफ किया? और जब-जब प्रदेश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो क्या उन्होंने भी भाखड़ा बांध विस्थापितों को कोई प्लॉट्स दिए या उनके कोई ऋण माफ किये या केवल मात्र वे जिलों के अन्दर जा करके प्रदेश की जनता को बेवकूफ ही बनाते रहे?

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में यह भी पूछा था कि 150 वर्गमीटर भूमि तक किए गए कब्ज़ों को नियमित करने के फैसले के अन्तर्गत दिनांक 15.2.2015तक कितने कब्ज़ों को नियमित किया गया ? मैं माननीय मंत्री के माध्यम से इसका पूरा ब्यौरा जानना चाहता हूं कि कितने लोगों की ज़मीन नियमित कर दी गई जो मजबूरीवश लोगों ने 150वर्ग मीटर तक कब्ज़े किए थे और कितने लोग अभी तक कब्जे नियमित करने के लिए शेष बचे हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब भाखड़ा डैम 1960 के दशक में तैयार हुआ तो उसके निर्माण के लिए 20514.60 एकड़ सरकारी और 10666 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहण की गई और उसमें बिलासपुर के 256 गांव के 11777 लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार ने लघु आय आवास योजना के अन्तर्गत कुछ ऋण उन लोगों को दिए गए ताकि वे अपने घर बना सकें। उसमें 628 विस्थापितों को जो ऋण दिए थे वो कांग्रेस सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 32,28,383

रूपये 80 पैसे के ऋण माफ उनके किए । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही शहर के विस्थापितों को जो प्लॉट दिए गए थे वो प्लॉट 99 वर्ष के लीज़ पर दिए गए थे । पीछे कैबिनेट मीटिंग हुई थी, राजस्व विभाग यह मामला कैबिनेट में ले कर गया और मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उनको लीज़ होल्ड से फ्री-होल्ड किया जाए। उन विस्थापितों को हमारी सरकार ने उन प्लॉट्स का मालिक बना दिया है। किन्तु नगर-पालिका को वे लोग हाऊस टैक्स नहीं देते थे और वे कहते थे कि हम तो लीज़

13.3.2015/1110/negi/jt/2

होल्डर हैं, हम मालिक नहीं हैं इसलिए सरकार ने उनको मालिक बनाया।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा कि जो भूमिहीन हैं, जिनको प्लॉट नहीं मिले हैं, वे 15.8.1999 तक अपनी दरख्वास्त दे दें, उसमें 420 पात्र व्यक्ति पाये गए । हमारी सरकार ने एक फैसला लिया था और 246 विस्थापितों के बारे जिलाधीश को कहा गया कि उनको पुनर्वास योजना के प्रावधानों के अनुसार प्लॉट या भूमि आवंटित करने बारे पत्र जारी किया जाए। इसमें एक मामला जिला मण्डी का था उसको जिलाधीश मण्डी को लिखा गया कि आप मण्डी में कोई प्लॉट देख करके उसको वहां पर प्लॉट उपलब्ध करवायें। 245 भाखड़ा डैम विस्थापितों को प्लॉट आवंटन हेतु भूमि चयन करने संबंधी प्रक्रिया जारी है। किन्तु बिलासपुर शहर में भूमि की उपलब्धता कम होने के कारण डी.सी. साहब को कहा है कि शहर के साथ लगते गांव में भूमि उपलब्ध करवायी जाए ताकि उनको प्लॉट बना करके उन विस्थापितों को प्लॉट दे सके। एक और जो महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने अध्यक्ष महोदय लिया है , हमने उनके लिए एक नई नीति बनाई है। भाखड़ा विस्थापित जो बिलासपुर शहर में बसे थे उन्होंने कुछ इन्क्रोचमैन्ट कर रखी है । कई लोगों ने ज्यादा इन्क्रोचमैन्ट की है और कई लोगों ने कम इन्क्रोचमैन्ट की है। उसमें भी सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया कि 125 स्क्वैयर मीटर ज़मीन जिन्होंने अपने मकान साथ एडज्वॉइनिंग एरिया में इन्क्रोच की है तो..

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

13/1115/03.2015.यूके/एजी/1

प्रश्न संख्या----1522 :जारी----

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री-----जारी----

जमीन अगर उनके मकान के साथ, एडज्वाइनिंग एरिया में ऐन्क्रोच की है, उन जमीनों को भी 125 स्क्वेयर मीटर तक उनके नाम कर दी जायेगी, सिर्फ 1 रुपया स्क्वेयर मीटर के हिसाब से, यह हमने फैसला किया है। इस बारे में कार्रवाई जारी है इसमें हम देखेंगे कि जिसने ज्यादा से ज्यादा किया है, यह सरकार उसकी ऐन्क्रोचमेंट को हटा कर अपने कब्जे में लेगी। इसके लिए भी प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही जो 151 रकबे में निरीक्षण किया गया है तथा कब्जा नियमित करने की प्रक्रिया जारी है और प्रयास ये किए गए कि सभी मामलों में निरीक्षण एवं निशानदेही के पश्चात् एक साथ ही निपटाया जाए। बाकी 125 स्क्वेयर मीटर को रेगुलर कर दिया जाए। जो ऐक्स्ट्रा जमीन होगी उसको सरकार अपने कब्जे में लेकर के नगरपालिका को हैंड-ओवर कर देगी। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय 150 स्क्वेयर मीटर की जो ऐन्क्रोचमैंट होगी उसको रेगुलर कर देंगे।

श्री बम्बर ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो एक एतिहासिक फैसला माननीय राजा साहब के नेतृत्व में माननीय मंत्री महोदय ने बिलासपुर के विस्थापितों के लिए किया है उसके लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि इसके ऊपर पहले कोरी-मात्र राजनीति हुई है, केवलमात्र घोषणा हुई हैं। आपने अमली जामा पहनाया है, इसके लिए बिलासपुर की जनता की ओर से मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

Speaker: Hon'ble Minister, would you like to answer this?

13/1115/03.2015.यूके/एजी/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमने यह एक महत्वपूर्ण और नीतिगत फैसला किया है । जिससे भाखड़ा विस्थापितों को बहुत फायदा हुआ है । उनके ऋण हमने माफ किए हैं, उनके कब्जे, जो जमीन लीज़ होल्ड पर दी गयी थी, उसको फ्री-होल्ड कर के उनको मालिक बना दिया । उसके साथ ही जो 150 स्क्वेयर मीटर की ऐन्क्रोचमैंट है, उसको भी हम ऋणमुक्त कर रहे हैं, 1 रुपए प्रति स्क्वेयर मीटर पर कर रहे हैं । निश्चित तौर पर यह एतिहासिक फैसला इस सरकार का है ।

13/1115/03.2015.यूके/एजी/3

प्रश्न संख्या 1523

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद से इस स्वास्थ्य संस्थान को बनाने के लिए काफी धन राशि इन्होंने उपलब्ध करवाई है । मगर 60 लाख रुपए जो बकाया है, कब तक यह धनराशि उपलब्ध करवा देंगे । दूसरा अध्यक्ष महोदय, जब इस भवन का नक्शा ऐप्रूव हुआ था उस वक्त हालांकि माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने स्वयं इसके आदेश दिए थे, इसका फाऊंडेशन भी इन्होंने ही किया है और मुझे लगता है कि इसका उद्घाटन भी इन्हीं के हाथों होगा । तो इसके जो ऑपरेशन थिएटर हैं उसमें अनफार्चुनेटली उस वक्त नक्शे में चिस्प डालने का प्रावधान रख दिया गया था । आप भी जानते हैं कि हास्पिटलों में ऑपरेशन थिएटर में आजकल टाईल्स लगाने का चलन हैं, सफाई तथा स्टरलाईजेशन के हिसाब से भी यह ठीक रहता है । तो माननीय मंत्री जी क्या आप आदेश देंगे कि चिप्स के बदले टाईल्स लगायी जाएं । इसी वजह से काम रुका हुआ है । क्या आप 60 लाख रुपए की बकाया राशि का प्रावधान करने और टाईल्स लगाने का प्रावधान आप करेंगे ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो टाईल्स की बात कही है यह ठीक है कि चिप्स आउटडेटिड है । स्पेशियली ऑपरेशन थियेटर में लेटेस्ट टाईल्स लगायी जाती है ताकि इन्फैक्शन आदि का खतरा न हो ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अब जो सारे अस्पताल बन रहे हैं उनमें टाईल्स ही लगाई जाती है जिससे इन्फैक्शन इत्यादि होने का खतरा कम रहता है ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी---

13.03.2015/1120/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 1523...क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वह लोक निर्माण विभाग डिजाईन करता है। लेकिन, जैसे कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिए हैं, हमने कहा है कि सभी अस्पतालों में अंदर की कंस्ट्रक्शन के लिए टायलों का ही प्रावधान किया जाएगा। मैंने लोक निर्माण विभाग से पता किया था, इनके अस्पताल को कंपलीट करने के लिए 60 लाख रुपये की आवश्यकता है। वह कहते हैं कि 31 मार्च तक 20 लाख रुपये की हमारी और लायबिलिटी है। हमने आदेश कर दिए हैं कि 20 लाख रुपया डलहौजी अस्पताल को दे दिया जाए। इसके अलावा हमने 40 लाख रुपया डिपोजिट कर दिया है। सिविल अस्पताल में कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो काम करने हैं, उनके लिए यह पैसा हमने जमा करवा दिया है। आवासीय विंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 98.37 लाख रुपये है। जैसे ही इसमें और आवश्यकता होगी, उस पैसे को भी हम दे देंगे। उन्होंने कहा है कि हमें 15-16 में 10 लाख रुपये की जरूरत है। वह पैसा भी हम उनको दे देंगे। अस्पताल को कंपलीट करने के लिए 31 मार्च तक की जो 20 लाख रुपये की लायबिलिटी है, उसको भी विभाग लोक निर्माण विभाग को दे देगा।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद कि आप 31 मार्च तक 20 लाख रुपया दे देंगे। मैं इनसे यह भी जानना चाहूंगी कि लोक निर्माण विभाग के पास पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग का कितना पैसा डिपोजिट है और वह काम क्यों नहीं हो रहे हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के पास इस समय स्वास्थ्य विभाग की 150 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि पड़ी है। हमने कहा कि जिन-जिन भवनों का काम 80% हो चुका है ,पैसा डाइवर्ट करके पहले उन भवनों को पूरा करने का प्रयास करें। जिन भवनों का काम नहीं हुआ है लेकिन हमने पैसा दे दिया है , उस पैसे को

13.03.2015/1120/sls-ag-2

यूटिलाईज कर सकते हैं with the permission of the department. चम्बा जिले में यह राशि निश्चित तौर पर लगभग 10-15 करोड़ रुपये के बीच में होगी।

प्रश्न समाप्त

13.03.2015/1120/sls-ag-3

प्रश्न संख्या : 1524

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि पहले इस प्रकार की स्थानीय निकाय लगभग 52 थीं including Shimla Nagar Nigam, जिनके ऊपर बहुत भारी राशि व्यय होती थी। लेकिन जो स्टैप्स मंत्री जी ने उठाए ,उनके फलस्वरूप अब यह राशि घटकर 2,94,57,790 रुपये रह गई है। इसमें सर्वाधिक पैसा बिलासपुर नगर परिषद् के नाम देय है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपके अनथक प्रयासों से यह सुधार हुआ है। इसी प्रकार का प्रश्न संख्या 329 मैंने 4 अप्रैल, 2013 में पूछा था। आपने यह कदम उठाए हैं जिनसे सुधार हुआ है। लेकिन इसमें यह कहा गया था कि स्टेट फाइनैंश कमीशन जो वार्षिक अनुदान राशि देता है उसकी 10 प्रतिशत् राशि कटौती करके बिजली के बिलों के लिए दी जाएगी। मुझे लगता है कि इसी का यह परिणाम है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसा करने से क्या जो विकासात्मक कार्य हैं, उनमें धन का अभाव नहीं हुआ? क्योंकि इस बात से आप अच्छी तरह अवगत हैं ,इस प्रकार के जो अनेकों स्थानीय निकाय हैं उन्होंने कई

जगह धन का मिसयूज भी किया है, मिस एप्रोप्रियेशन भी किया है। इस प्रकार के कार्य से कहीं ऐसा तो नहीं कि, जैसे कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला हो गया। एक तरफ तो यह भरपाई हो गई लेकिन विकास कार्यों पर इसका असर निश्चित रूप से पड़ा होगा। दूसरी बात आपने कही थी कि जो सरचार्ज है ,उसको एडजस्ट करने के लिए आप एचo पीo एसo ईo बीo एलo को कहेंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस कदम के उठाने से कितनी धनराशि माफ हुई और जहां तक ईo डीo चार्जिज हैं, उसको माफ करने का अधिकार केवल सरकार को था ,क्या इस धनराशि के अंतर्गत जो इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटि चार्जिज बने थे ,उनको भी माफ किया गया है?

जारी ..गर्ग जी

13/03/2015/1125/RG/JT/1

प्रश्न सं. 1524----क्रमागत

श्री महेश्वर सिंह के पश्चात

शहरी विकास मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय सदस्य ने जानना चाहा है और जैसा इन्होंने कहा है कि बहुत सारी धनराशि अर्बन लोकल बॉडीज़ में शेष थी इसमें जो बहुत सारे शेष बचे हैं उनमें कोई भी टैक्स कलैक्शन अधिकतर में नहीं हो रही है और जो बाकी हैं उनमें किसी प्रकार का जो विकासात्मक कार्यों के लिए पैसा दिया गया था उसमें कोई भी धनराशि बिजली के बिलों के भुगतान के लिए नहीं ली गई है जो आपने 10 प्रतिशत की बात की है। जो उनसे बिजली के बिलों की वसूली की गई है यह निरन्तर प्रयास से और यू.एल.बीज़. ने कुछ अपने साधन भी बढ़ाए हैं। हमारा यह प्रयास है कि इस विषय में जहां तक बिजली के बिलों का भुगतान है या अर्बन लोकल बॉडीज़ की अन्य बातें हैं ,हम लोग इनको गाइड भी कर रहे हैं और जागरुक भी कर रहे हैं कि ये अपने संसाधन किस प्रकार से बढ़ाएं। क्योंकि यदि शहरों में मूलभूत सुविधाएं देनी हैं अगर हम इस तरह से करेंगे या सारी चीजों में कटौती करते जाएंगे ,तो उनके पास अपने संसाधन नहीं

होंगे और ये पूरी तरह से सरकारों पर निर्भर रहेंगे। इसलिए हमारा प्रयास यह है कि जो बाकी 10 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं ,अब जैसे बिलासपुर है वहां कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा यह प्रयास है कि उनके ऊपर भी फोकस करके जो दो करोड़, 94 लाख रुपये के लगभग धनराशि शेष है ,इसको भी पूरा करके इनका भुगतान समय पर कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने 'ख' भाग में पूछा था कि स्ट्रीट लाइट्स के बिलों के लिए क्या कोई कॉमर्शियल रेट नोटिफाई किया हुआ है ,तो वह कॉमर्शियल रेट नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स के लिए रैग्युलेट्री कमीशन ने अलग से दर तय की है जो 4 रुपये 70 पैसे प्रति यूनिट है और कॉमर्शियल रेट 4 रुपये 95 पैसे प्रति यूनिट है ,तो इस प्रकार 25 पैसे का फर्क इसमें रखा गया है। **यह बात सही है कि जैसा आपने सुझाव दिया है कि हम रैग्युलेट्री कमीशन को लिखेंगे कि इसके लिए कोई बीच की दर तय करे ताकि उसका फायदा उपभोक्ता को हो और अर्बन लोकल बॉडीज़ को हो।**

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से ई.डी. चार्जिज के बारे में जानना चाहा था और जो सरचार्ज है। आप देखेंगे कि जो बिजली के बिल हैं ,खपत का बिल

13/03/2015/1125/RG/JT/2

कम है ,सरचार्ज और ई.डी. भी न जोड़ें, तो यह 50प्रतिशत भी नहीं रह जाता। तो क्या इस ओर भी कदम उठाए गए हैं? दूसरा, जो अभी-अभी 'ख' भाग के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा, रैग्युलैट्री कमीशन के फॉरमेशन से पहले इसके लिए डोमैस्टिक रेट ही लगता था। क्योंकि नगर निकायों को स्ट्रीट लाइट्स से कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। कॉमर्शियल रेट वहां लगता है जहां बिजनैस होता है। यह तो समाज सेवा है और स्ट्रीट लाइट्स देना उनका दायित्व है। इसलिए जैसा स्वयं अभी कहा कि जो इन्होंने टैरिफ लगाए हैं वह भी हायर हैं। यही नहीं हर साल रैग्युलैट्री कमीशन इसको और बढ़ाता है। अब फिर समय आया है 31 मार्च से पहले रैग्युलैट्री कमीशन के पास यदि आप समय रहते आग्रह नहीं करेंगे, तो अगली साल यह रेट और बढ़ा देंगे। एक तरफ आप इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं , रैग्युलैट्री कमीशन का काम है कि आय कैसे बढ़ाएं। आप आय निश्चित रूप से

बढ़ाइए। लेकिन इनको इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाए और इस प्रकार इसको न बढ़ाया जाए, जो रेट है जैसा आपने स्वयं कहा, इसको और कम कर दिया जाए और हो सके, तो इनसे डोमेस्टिक रेट ही चार्ज करने चाहिए क्योंकि ये लोगों की सुविधा के लिए है।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने ई.डी. चार्जिज के बारे में सुझाव दिया है उस पर सरकार विचार करेगी। इसके अतिरिक्त जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि रैग्युलेट्री कमीशन से इस मामले को दुबारा से उठाया जाए , तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और हमारा यह मानना है कि इसके ऊपर रैग्युलैट्री कमीशन गंभीरता से विचार करेगा।

प्रश्न समाप्त

3-/

13/03/2015/1125/RG/JT/3

प्रश्न सं. 1525

श्री गोबिन्द सिंह ठाकुर अनुपस्थित।

अगला प्रश्न एम.एस. द्वारा आरम्भ

13/3/2015/1130/MS/JT/1

प्रश्न संख्याः 1526

श्री मोहन लाल ब्राक्टा:अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसके मुताबिक मल निकासी योजना रोहडू का कार्य वर्ष 1995-96 में आरंभ किया गया था तथा इस योजना का कार्य इनके मुताबिक पूर्ण हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी भी रोहडू बाजार में पूरी तरह से इसकी सुविधा सभी लोगों को उपलब्ध नहीं है। जो अभी तक इस सुविधा से वंचित हैं क्या उनके लिए भी आगे इसका प्रावधान है या आगे आप कब तक इसका कार्य शुरू करेंगे क्योंकि मेरी सूचना के मुताबिक अभी तक 50 प्रतिशत रोहडू की जनसंख्या इससे वंचित है? मेरा निवेदन है कि इसके लिए शीघ्रातिशीघ्र आदेश दिए जाएं। मैं साथ ही यह आश्वासन भी चाहता हूं कि कब तक इसका कार्य आरंभ होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो रोहडू की सीवरेज स्कीम है, उसमें शुरू में जब इस योजना ने बनना था तो तीन जोन निर्धारित किए थे। जोन-तीन में एक सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट बनना था जोकि स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से नहीं बन पाया क्योंकि वह रिहायशी इलाके के साथ था। लेकिन जो एक एरिया उसके अन्दर कवर होना था ,उसको जो पहले दो जोन थे, उनके साथ जोड़करके ,क्योंकि सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग इस सीवरेज स्कीम पर काम करता है तो उसने इस काम को मुकम्मल किया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मेन लाइन के साथ आगे हाउस-टू-हाउस कनैक्टिविटी होनी होती है, वह नहीं हो पाई होगी क्योंकि उसको सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग नहीं करता। हालांकि फण्डिंग सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को की जाती थी। अब हमने यह भी निर्णय लिया है कि यह सारा पैसा स्थानीय निकाय को दिया जाएगा ताकि वे हाउस-टू-हाउस कनैक्टिविटी अपने आप करे। मैं आपको यह आश्वासन ही नहीं बल्कि विश्वास देता हूं कि इसके लिए जो भी निर्धारित धनराशि की आवश्यकता होगी, वह आपको इसी वित्तीय वर्ष में दे दी जाएगी।

प्रश्न समाप्त/

13/3/2015/1130/MS/JT/2

प्रश्न संख्याः 1527

अध्यक्षः श्री सतपाल सिंह सत्ती। अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः 1528

अध्यक्षः श्री हंस राज। अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः 1529

अध्यक्षः श्री विनोद कुमार। अनुपस्थित।

13/3/2015/1130/MS/JT/3

प्रश्न संख्याः 1530

श्री बम्बर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से जानना चाहा था कि जब प्रदेश के अन्दर कहीं पर भी हैंडपम्प की ड्रिलिंग का काम चलता है, उस वक्त हाइड्रोलोजिस्ट हर जगह पर मौजूद नहीं होता क्योंकि जिला में एक हाइड्रोलोजिस्ट होता है। उत्तर में भी इस बात को माना गया है कि वह हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। परन्तु जब एम0बी0 भरने की बात आती है तो हाइड्रोलोजिस्ट जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देगा, लॉगशीट नहीं देगा, तब तक जे0ई0 एंट्री नहीं कर सकता। क्योंकि आमतौर पर यह देखने में आया है कि ज्योलोजिस्ट के खाते में जब कुछ जाएगा, तब वह ठेकेदार की एम0बी0 को भरने के लिए लॉगशीट जारी करेगा अदरवाइज नहीं करेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब जे0ई0 के सामने बोरिंग होती है तो जे0ई0 ही एम0बी0 भरने के लिए अधिकृत होना चाहिए। उसको ज्योलोजिस्ट के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, जो वहां पर मौजूद ही नहीं होता है। मैं मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि क्या आप इसमें तरमीम करेंगे कि जब वहां

पर हाइड्रोजोजिस्ट मौजूद ही नहीं होता तो उसकी गैर-मौजूदगी को लेकर के उसकी लॉगशीट दी जा सकती है। उसका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि वहां पर पानी है या नहीं। यदि पानी है तो फिजिबिल्टी रिपोर्ट दे और वहां जाकर जे0ई0 बोरिंग करवाए। बोरिंग करवाकर वह देखे कि कितनी बोरिंग हुई और उसके मुताबिक एम0बी0 भर दे। यही मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

मंत्री जी का जवाब श्री जे0के0 द्वारा----------

13.03.2015/1135/जेके/ऐजी/1

प्रश्न संख्याः ----1530जारी----

Irrigation & Public Health Minister: Hon'ble Member, I would like to explain to you. You have already explained to me. There are two distinct steps involved in drilling of hand pumps i.e. (i) Selection of sites is done by the Hydrologist on the recommendation of Senior Technical Assistant (STA) and (ii) Drilling of hand pumps, is carried out in the supervision of Senior Technical Assistant and Junior Engineers. I would like to explain to you thoroughly. There is no problem. It is true that during drilling operation of hand pumps, the presence of STAs is necessary but if the boring is carried out simultaneously at different places, it is not possible for STA to be present at all drilling locations. However, if the distance is not far away then the Hydrologist/STA will visit the sites and give instructions after observing the drilling parameters/strata and pass suitable directions accordingly. But when the drilling sites are far away from each other then minimum two aquifer parameters viz. development of hand pumps and measurement of discharge are carried out in presence of STAs. So, I hope you will understand what I am trying to explain to you. The log sheets are prepared by the STAs from the soil samples which are kept by drillers during drilling of hand pumps.

I would also like to explain to you that generally the record entry of hand pumps is made based on log sheets prepared by the STAs on the basis of groundwater parameters which are site specific. This however does not bar the Junior Engineer from preparing log sheets from the soil samples, if the STAs are not available due to unavoidable circumstances. Only Junior Engineers are authorized to make the record entry of hand

13.03.2015/1135/जेके/ऐजी/2

pumps in the MBs independently and Hydrologist/STA has no role in this matter at all.

In order to supplement the drinking water demand of the people, hand pumps are being installed in the Pradesh. A total 31678 hand pumps have been installed in the Pradesh upto 31.01.2015, during our time, out of which 700 hand pumps have been installed during the current financial year 2014-2015. So, I hope you will understand what I am trying to explain to you. Thank you.

श्री बम्बर ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मेरा बिल्कुल सिम्पल प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदया ने लम्बा-चौड़ा ज़वाब दिया है और मैं उससे सहमत हूं। आपने पूरे प्रदेश में हेंड पम्प लगा दिए हैं यह बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सिम्पली यह पूछ रहा हूं कि जब हाईड्रोलोजिस्ट ड्रिलिंग के समय वहां पर मौजूद ही नहीं होता है फिर जे.ई. को क्यों बाध्य किया जाता है कि उसकी वह रिपोर्ट लें कि कितना बोर हुआ है? बोर के बारे में हाईड्रोलोजिस्ट कैसे नकार सकता है जब वह वहां पर मौजूद ही नहीं होता है? बोर कितना हुआ है वह तो जे.ई. बताएगा या सर्वेयर बताएगा। एम.बी. भेजने के लिए जे.ई. को हाईड्रोलोजिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हाईड्रोलोजिस्ट का सिर्फ इतना ही काम होना चाहिए कि उस साईट पर पानी है या नहीं है। वह तो साईट को सलैक्ट करेगा। लेकिन यहां पर एम.बी. को दर्ज़ करने के लिए हाईड्रोलोजिस्ट को लिख करके देगा। हाईड्रोलोजिस्ट लिख रहा है कि 400 फुट बोर हुआ है और जे.ई. कहता है कि 300

फुट बोर हुआ है। इसमें कन्ट्राडिक्शन है। बोरिंग के समय में जो अधिकारी मौजूद है वहीं एम.बी. के लिए अधिकृत होना चाहिए।

Speaker: This is a matter of procedure. यह तो प्रोसिज़र एडॉप्ट किया गया है।

13.03.2015/1135/जेके/ऐजी/3

श्री बम्बर ठाकुरः जो हाईड्रोलोजिस्ट इनके ऊपर बिठाया गया है, क्रप्शन का एक अड्डा है। पिछली सरकार ने यह काम किया है। इसको अमैंड करने की जरूरत है। मेरे साथ भी यह हुआ है कि जब मैं यह काम 8-10 साल पहले करता था तब मैंने 45 हजार रूपये हाईड्रोलोजिस्ट को दिए। उसके बाद उसने एल.एम. शीट दी तब एम.बी. दर्ज़ हुई। पिछली सरकार ने यह काम चलाया हुआ था आज यहां पर पूर्व मंत्री नहीं है फिर मैं उनको इस बारे में पूछता ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदया इसका कोई हल ढूंढिए।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

13.03.2015/1140/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1530 क्रमागत

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमने इनको बात समझाने की कोशिश की है, I hope he did not understand my point. So, I am trying to ask you one thing. The STAs are authorized to prepare the log sheets. However, JE can also prepare the log sheets. Why not? What is the problem there? Log sheets are there. In the absence of the STAs, why cannot you do that? I am sure you will understand my problem.

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जब पम्प लगाने की बात आती है तो हाइड्रोलोजिस्ट को यह मालूम करने के लिए पहले जाना चाहिए कि वहां पानी है या नहीं। That is his duty. That's all. एक दफा जब वह सर्टिफाई करता है कि क्या पम्प लगाने से पानी आयेगा तो उसके बाद जे0ई0 का काम है या एस0डी0ओ0 का है कि वह पम्प को लगाए। उसके बाद जो हाइड्रोलोजिस्ट है उसमें और कोई दूसरी दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। Certificate from the JE or SDO is enough.

प्रश्न समाप्त

13.03.2015/1140/SS-AG/2

प्रश्न संख्याः 1531

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है उसके अनुसार ये कहा गया है कि 6.10.2009 को एफ0सी0ए0 के अन्तर्गत केस निपटाने के लिए कोई नीति निर्धारित की गई थी। उसकी प्रतिलिपि भी साथ लगी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि क्या 7 वर्ष पहले बनाई गई नीति आज भी प्रासंगिक है? अगर है तो चलने दीजिए अन्यथा बदले हुए हालात में क्या आप इसको रिव्यू करने का प्रयास करेंगे या रिव्यू करेंगे?

दूसरा, जो आपने यहां कुल्लू जिला में एफ0सी0ए0 के पैंडिंग केसिज़ की संख्या बताई है वह बहुत बड़ी है। उसमें आपने कहा है कि एफ0सी0ए0 क्लीयरैंस के लिए 94 केसिज़ पैंडिंग हैं। उसको मैंने ध्यान से पढ़ा है। इसके अन्तर्गत एक केस 2005 का है और 2007 के दो केसिज़ हैं। 2009 के 6 केसिज़ हैं। 2012 के 6 केसिज़ हैं और 2013 के 32 केसिज़ हैं। इस प्रकार काफी पैंडेंसी है। अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से आपके माध्यम से यह भी जानना चाहा था कि क्या ये जो केसिज़ पैंडिंग हैं इनके लिए कोई स्टेट लेवल कमेटी बनी है? मुझे लगता है कि यह उत्तर ठीक नहीं है। आपने "जी हां" कहा है और कमेटी किसकी अध्यक्षता में है? रीजनल जो एफ0सी0 बैठता है। फॉरैस्ट कंजरवेटर चंडीगढ़ बैठता था। वह कमेटी स्टेट लेवल की कहां से हो गई? मेरा पूछने का तात्पर्य यह था कि क्या अपने यहां पर स्टेट लेवल में कोई कमेटी रिव्यू के लिए बनाई है ताकि इसका फोलो अप हो? दूसरा, महोदय

चंडीगढ़ हमारे लिए नज़दीक था। अब तो यह दफ्तर ही देहरादून चला गया है। तो क्या इससे प्रदेश को असुविधा नहीं हुई है? अगर हुई है तो क्या इस मामले को आपने केन्द्रीय सरकार से टेक अप किया है कि इस ऑफिस को पुनः चंडीगढ़ से जोड़ा जाए? हमें देहरादून दूर पड़ता है और चंडीगढ़ नज़दीक पड़ता है।

तीसरा, मंत्री महोदय ने कहा है कि एफ0सी0ए0 के अन्तर्गत शीघ्र केस निपटाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई कमेटी नहीं है और ये जो अधिकांश केसिज़ हैं वे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही पैंडिंग हैं या कंजरवेटर लेवल पर पैंडिंग हैं। क्योंकि कुल्लू के दो भाग हैं। एक रामपुर कंजरवेटर, सराज का क्षेत्र वहां आता है और कुल्लू सर्कल में लाहौल तथा कुल्लू के दूसरे क्षेत्र आते हैं इसलिए क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में विलम्ब न हो। वहां पर भी

13.03.2015/1140/SS-AG/3

कंजरवेटर बैठें। कंजरवेटर की अध्यक्षता में इस प्रकार की मीटिंग हो और उसकी प्रोसिडिंग स्थानीय विधायकों को भी मिलनी चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हमारी योजना है किस स्तर पर। उसमें मुझे लगता है कि अगर ये कॉपी हमको मिले या हम भी कभी उस बैठक में चले जाएं ,बैठक की सूचना हो तो वहीं रिव्यू होगा तो वह सार्थक सिद्ध होगा। तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर करेंगे और क्या इनको समयबद्ध बनायेंगे?

जारी श्रीमती के0एस0

/1145/13.03.2015केएस/जेटी/1

प्रश्न संख्याः 1531 जारी-----

श्री महेश्वर सिंह जारी---
और क्या इनको समयबद्ध बनाएंगें कि कितने दिन में केस आता है? मैं मानता हूं कि केस तो जो विभाग है वे ही नोडल एजैंसी होती है उसको तैयार करके केस भजना

होता है परन्तु जब एक बार केस आ जाता है तो उसको कितने दिन में निपटाया जाए, इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए, उसके लिए कुछ नियम बनने चाहिए। क्या इस बात पर मंत्री जी विचार करेंगें?

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री महेश्वर सिंह जी की चिन्ता जो 94 केसिज़ वन विभाग की वजह से पैंडिंग पड़े हैं, उसके बारे में हैं लेकिन ये केसिज़ वन विभाग की वजह से पैंडिंग नहीं है । पैंडेंसी इस वजह से हैं कि जैसे आपने बताया कि नोडल एजैंसी जो है, पी.डब्ल्यू.डी. है या आई.पी.एच. है या अदर डिपार्टमैंट है, वह केस पुटअप करते हैं । वे सब- डिविज़न लैवल पर केस पुटअप करते हैं फिर डी.एफ.ओ. उसको रीव्यू करते हैं उसके बाद सर्कल लैवल पर कमेटी बनी है कंज़र्वेटर जिसकी अध्यक्षता करते हैं उसमें सब ऑफिसर्ज़ को नोडल वाले बुलाते हैं और बाकायदा मीटिंग होती है और हर महीने की पांच तारीख को स्टेट लैवल पर भी जो फोरैस्ट सैक्रेटरी हैं, वे मीटिंग करते हैं । एडिशनल पी.सी.सी. एफ. एफ.सी. केसिज़ के लिए बिठाया हुआ है। वह उसको स्क्रीन करता है। जब केस नीचे से आएगा तब स्क्रीन करेगा । अब दो बातें हैं अब मुझे यह नहीं पता कि आप इसको एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट से कन्फ्यूज़ कर रहे हैं या दूसरी कमेटी से एफ.सी.ए. केस से कन्फ्यूज़ कर

/1145/13.03.2015केएस/जेटी/2

रहे हैं। मेरे ख्याल में आप पूछना चाहते हैं कि जो एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट हैं, वह क्यों डीले हो रहा है। उसमें जो नोडल एजैंसी हैं वह ट्राईबल है लेकिन केन्द्र सरकार ने जब 2006 में एक्ट बनाया था तो आदेश किए थे कि इसको वन विभाग देखेगा और उनके जरिए ही यह काम होगा लेकिन जो ग्राऊंड लैवल पर एफ.आर.ए. कमेटी बनती है उसमें 10 मैम्बर होते हैं। उसका एक अध्यक्ष होता है। ग्राम सभा की मीटिंग होती है, कभी यह मीटिंग नहीं हो पाती, डीले हो जाती है , तीन-तीन महीने के लिए डीले हो जाती है । डी.सी. को तीन महीने के आदेश हैं कि एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट तीन महीने के अन्दर-अन्दर देना पड़ेगा। तो वह जो ग्राऊंड लैवल की कमेटी है उसमें हमें भी परस्यु करना पड़ता है। एम.एल.ए., मंत्री को भी परस्यु करना पड़ेगा यह कमेटी तब बनेगी और उसके बाद वह सब डिविजनल लैवल की कमेटी में आएगा फिर डिस्ट्रिक्ट लैवल की कमेटी में आएगा तब जाकर एफ.आर.ए.

सर्टिफिकेट इश्यू होगा वरन् केन्द्र सरकार उस पन्ने को खोलती ही नहीं है । जब हम यहां से फाईल बनाकर भेजते हैं तो वहां पर वह केस खुलता ही नहीं है । इसलिए जहां तक आपने सुझाव दिया कि क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के साथ ही हमें रखा जाए, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी परस्यू किया है, इन्होने भी चिट्ठी लिखी, मैंने भी चिट्ठी लिखी । पर्सनल लैवल पर भी परस्यू किया। जो हमारे केन्द्र में नए वन मंत्री बने हैं , मैं पर्सनली भी उनसे मिला था उन्होंने आदेश दिए थे कि हम यह मीटिंग करके बड़ी जल्दी इसका रीविज़न करेंगें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने डी.ओ. नोट लिखा प्रधानमंत्री जी को कि हमारे जो एफ.सी. केसिज़ हैं, डीले हो जाते हैं और हमारा दफ्तर चण्डीगढ़ में ही रहना चाहिए न कि देहरादून में क्योंकि देहरादून बहुत दूर पड़ता है।

/1145/13.03.2015केएस/जेटी/3

देहरादून में भी हमारे हिमाचल के अब ऑफिसर हैं वे वहां डैपुटेशन पर गए हैं केस वहां से भी डीले नहीं होता । डीले नोडल एजैंसीज़ की वजह से होता है और हमें और आप सब को मिल कर कोशिश करनी पड़ेगी तब जा कर यह बात बनेगी। जहां तक तीसरी बात आपने कहा कि वर्तमान नीति संतोषजनक नहीं है। मैं तो समझता हूं कि यह संतोषजनक है लेकिन यदि आप कोई ऐसा सुझाव देंगें तो उसको हम कंसीडर करेंगें I There is no problem at all.

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बिल्कुल सिम्पल था कि विभिन्न एजैंसियों के पास कितने केसिज़ पैंडिंग है? आपने जो उत्तर दिया, निश्चित रूप से स्वभाविक है कि जो वन विभाग के पास लम्बित पड़े हैं जब ये लम्बित पड़े हैं तो नैचुरली नोडल एजैंसिज़ ने दे दिए उसमें कहीं ऑब्जैक्शन लग सकता है, उसके निराकरण के लिए। तभी मैं कह रहा हूं कि टाईम फिक्स करें ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी-

13.3.2015/1150/jt/av/1

प्रश्न संख्या : ----------1531क्रमागत

श्री महेश्वर सिंह ----------जारी

उसका निराकरण करने के लिए तभी मैं कह रहा हूं कि टाइम फिक्स करें। साथ में, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब भी मीटिंग होगी तो क्या उसकी कॉपी विधायकों को भी भेज दी जायेगी ताकि हम उनके साथ लिंक्ड रहें और हमारे से जो भी सहयोग चाहिए हम उनको दे सकें। दूसरी, आपने जो ग्राम सभा की बात कही है, यह बात पुरानी हो चुकी है। शायद आपकी जानकारी में नहीं है मगर बाद में इसमें अमैंडमैंट हो गई है। अब वहां पर अलग से एक कमेटी बनाई है। वह कमेटी विधान सभा की नहीं है, वह डी.सी. द्वारा बनाई गई है। उसमें पंचायतों के कुछ लोग होते हैं और उसके अध्यक्ष कनजर्वेटर है। आपकी सूचना बहुत पुरानी है। दूसरा, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि कल मेरा प्रश्न संख्या 752 लगा था। जिसमें मैंने यह जानना चाहा था कि शिक्षा विभाग के कितने भवन फॉरैस्ट कनजर्वेशन ऐक्ट के तहत फॉरैस्ट लैण्ड में है। उनको विभाग के नाम करने के लिए क्या किया जा रहा है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। इस प्रश्न के संदर्भ में आए लिखित उत्तर को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जो केसिज भूमि स्थानांतरण हेतु आए हैं उनमें से अभी तक केवल 27 केसिज को क्लीयरैंस मिली है और विभाग के नाम हो गये हैं। इन केसों की कुल संख्या 683 हैं। सम्भवतया इसमें ज्यादातर केसिज कुल्लू के हैं। कुल्लू जिला की एक विचित्र स्थिति है और वहां पर हर जगह घर से बाहर निकलते ही फॉरैस्ट लैण्ड है। इस प्रकार से 683 केसिज ऐसे हैं जिसमें भवन आज भी वन भूमि पर खड़े हैं और इनका स्थानांतरण होना चाहिए। आपको कुल 245 केसिज भेजे गए हैं जिनमें से 27 क्लीयर है। ये शिक्षा विभाग से सम्बंधित है। जब बिल्डिंग रेनोवेट करनी होती है या एडिशनल कोई कनस्ट्रक्शन करनी हो तो यहां से क्वैरी यह लगती है कि क्या यह भूमि शिक्षा विभाग के नाम पर है या नहीं है? मेरे हिसाब से तो शिक्षा विभाग के लिए यह क्वैरी लगानी ही नहीं चाहिए क्योंकि यह तो आपकी नोलेज में है कि कितनी जगह पर नहीं है। मगर इसमें क्या होता है कि बजट का प्रावधान भी कर दिया जाता

है उसके बाद पूछा जाता है कि विभाग के नाम है या नहीं है। जिस कारण से वहां पैसा खर्च करने को पैंडिंग पड़ा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो केसिज आपके पास आ चुके हैं क्या उनके लिए कोई समयसीमा निश्चित करेंगे? स्कूल की बिल्डिंग के साथ एडिशनल कनस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। यहां तक कि स्कूल ग्राउंड भी वन विभाग की भूमि पर ही है तथा उसमें भी कोई डिवैल्पमैंट नहीं हो सकती। अगर आप इनको समयसीमा के अंदर निपटाने की बात करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। अभी 50 प्रतिशत केसिज तो भेजे ही नहीं है ,ये आराम से फाइल पर बैठे हैं। यह मामला शिक्षा से सम्बंधित है और वे जल्दी जाने चाहिए ताकि वहां भवन निर्माण हो सके। इसलिए ये केसिज जल्दी से जल्दी निपटाये जाएं।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने बात की है कि मीटिंग्ज में हमें भी बुलाया जाए। यह सूचना आपको भी कनजर्वेटर के जरिए दे दी जायेगी। अगर आप जाना चाहे तो जा सकते हैं इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है। इस बारे में सभी विधायकों को सूचना दे देंगे। आप सबको कॉपी भेज दी जायेगी।

श्री महेश्वर सिंह : मंत्री जी, कॉपी तो तब आयेगी जब आप कमेटी का गठन करेंगे।
वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो कनजर्वेटर रिव्यू करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपको वह सूचना दे देंगे। इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है। शिक्षा विभाग अथवा अन्य किसी विभाग को भूमि स्थानांतरण अथवा डाइवर्शन किया जा सकता है अगर वे अप्लाई करे। वन विभाग ऐप्लिकेशन मिलने के बाद तुरंत इसका निपटारा करेगा। हमने इसके लिए तीन महीने की समयसीमा निश्चित की है कि इसको तीन महीने के अंदर-अंदर निपटाया जाएगा। अभी दो-तीन दिन पहले कैबिनैट की मीटिंग में इस बारे में बात उठी थी और यह मुद्दा माननीय कौल सिंह जी ने उठाया था ----------

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य मान्य सदन में आए।)

श्री बी.जे.द्वारा जारी

13.3.2015/1155/negi/ag/1

प्रश्न संख्याः ..1531 जारी..

माननीय वन मंत्री जारी..

आप शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले यह बात कैबिनेट में उठी थी, माननीय श्री कौल सिंह ठाकुर जी ने यह मुद्दा उठाया था। फोरेस्ट ऐक्ट 1980 में आया था लेकिन इससे पहले जो बिल्डिंग्ज़ बनी हैं या जो भी डवलपमैन्ट के काम हुए हैं उनको चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग करके निपटाया जाएगा और उनको एक क्लीयर कट आर्डर किया जा रहा है कि उससे पहले के जो केसिज़ हैं उन सबको विभाग के नाम से कर दिया जाए।

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री महेश्वर सिंह जी ने जो यहां मुद्दा उठाया है यह पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी चुनाव क्षेत्रों के लिए है। मेरे चुनाव क्षेत्र में नाबार्ड के तहत वर्ष 2008-09 में करोड़ो रूपये आए हुए हैं। लेकिन वर्ष 2008-09 के बाद आज तक एफ.सी.ए. क्लीयर नहीं हुए और आने वाले एक साल के बाद वो सारा पैसा लैप्स होने वाला है । फिर वो पैसा दोबारा लाने के लिए 3-4 साल और लग जाएंगे। माननीय मंत्री महोदय से मेरी यह विनती है कि जो सड़क अप्रूवड हो गई है जिसका बजट आ गया है उसका एफ.सी.ए. केस प्रायोरिटी में क्लीयर किया जाए। मेरे क्षेत्र में 2008में पैसा आया है और 7 साल में भी एफ.सी.ए. केस क्लीयर नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें और कितना समय लगेगा क्योंकि अगले साल के बाद वह पैसा लैप्स हो जाएगा ।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह ठीक चिन्ता है । हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई केसिज़ हैं । नाबार्ड में और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कुछ केसिज़ थे जो बिना इज़ाजत के पहले किए गए थे, जिनमें वॉयलेशन हुआ था। उसके बाद फिर केन्द्र सरकार का आदेश आया था । इनको हम प्रायोरिटी में कर देंगे। लेकिन जो नोडल एजैंसी है वो केस फोरेस्ट के पास भेजेगा तभी केस क्लीयर होगा। अगर नोडल एजैंसी पैसा जमा नहीं करवाएगी तो क्लीयरेंस कहां से मिलेगी और

सड़कें कहां से बनेगी ? It is not the fault of the forest department. They should send the cases.

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सड़कों की बात कर रहा हूं जिनमें कोई वॉयलेशन नहीं हुई है । जिन सड़कों का कार्य शुरू नहीं हुआ है, मैं उन सड़कों की बात कर रहा हूं । 8-7 साल से जो भी एजैंसीज़ हैं, चाहे वो एस.डी.एम. लेवल की कमेटी है और चाहे डी.एफ.ओ. लेवल की कमेटी है इन्होंने अभी तक उनके एफ.सी.ए. क्लीयरेंस नहीं दी है । अभी सड़क का कार्य शुरू नहीं हुआ है और इसमें कोई वॉयलेशन नहीं हुई है । ये सड़कें नाबार्ड से 7 साल पहले अप्रूवड हो चुकी हैं और अगले साल पैसा लैप्स होने वाला है । अगर 6 महीने या एक साल में एफ.सी.ए. क्लीयर नहीं मिलेगा तो सारा पैसा लैप्स हो जाएगा।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई पर्टिकुलर केस हैं तो आप मेरे नोटिस में लायें उसको प्रोयोरिटी दी जाएगी । एफ.सी.ए. केसिज़ को रिव्यु करने के लिए सर्कल लेवल पर कंजर्वेटर की मीटिंग हर माह 5 तारीख को होती है । ए.पी.सी.सी.एफ. हर महीने 15 तारीख को एफ.सी.ए. केसिज़ के बारे मीटिंग करते हैं। उसके बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 3 महीने में एक बार उनको रिव्यु करते हैं और केसिज़ डिसपॉज-ऑफ करते हैं। अगर आपके पर्टिकुलर केसिज़ हैं तो आप मेरे नॉलेज़ में लाइये, मुझे लिख करके दीजिए हम उनको इमिडिएटली डिसपॉज-ऑफ कर देंगे।

प्रश्नकाल समाप्त

13.3.2015/1155/negi/ag/3

कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे

अध्यक्षः अब कागज़ात सभापटल पर रखे जाएंगे। अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

सदन की समिति के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। अब श्री रविन्द्र सिंह रवि, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

13/1200/03.2015.यूके/एजी/1

श्री रविन्द्र सिंह :माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लोखा समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

(i) समिति का **82वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष

2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **83वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **84वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का **85वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **वित्त विभाग (आधिक्य)** से सम्बन्धित है।

श्री सुरेश भारद्वाजः सर मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं।

अध्यक्षः बोलिए।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, कल हमने नियम 67के अर्न्तगत प्रस्ताव दिय थे। आपने उन प्रस्तावों को को स्वीकार नहीं किया। लेकिन महत्वपूर्ण

13/1200/03.2015.यूके/एजी/2

विषय था हमारे पार्टी कार्यालय पर आक्रमण हुआ था। इसलिए हमने राज्यपाल महोदय को पहले भी निवेदन किया था क्योंकि वे संवैधानिक मुखिया हैं प्रदेश के, उनको हमने अपना मैमोरेंडम दिया है, उन्होंने हमको आज 11.30बजे का समय दे रखा था। हमने अपना प्रोटैस्ट दर्ज किया है। अगर 31 मार्च, 2015 तक इस विषय पर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती,

केसिज़ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, तो हम 31 मार्च के बाद अपना आंदोलन जारी रखेंगे और अब हम सदन की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं ।

अध्यक्षः मैने आपको पहले भी बताया था कि आपके इस विषय पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन स्थगन प्रस्ताव के लिए मैं अनुमति नहीं दूंगा । कोई चीज़ डिसकस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव की जरूरत नहीं है । यह इतना इम्पार्टैंट नहीं है कि सारा काम छोड़ कर इस पर चर्चा करें । (व्यवधान) इसमें कोई बुराई नहीं है । यह दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी । लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्थगन प्रस्ताव का कभी-कभार किसी नैश्नल लैवल पर इस्तेमाल होता है । इस विषय पर आप किसी अन्य नियम के तहत भी चर्चा कर सकते हैं । उसके लिए हम तैयार हैं । मैने आपको कल भी कहा था उसी पर मेरा स्टैंड है ,वही मैं आज भी कह रहा हूं कि यदि आप इस पर डिसकशन करना चाहते हैं तो किसी अन्य नियम के अर्न्तगत चर्चा कर लें । लेकिन आपका स्थगन प्रस्ताव मैने रिजैक्ट कर दिया है ,उसको मैं अलाऊड नहीं करूंगा ।

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मेरे ध्यान में आपके तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय के माध्यम से एक बात आयी है कि पिछले कल जब मैं यहां अपना वक्त्व्य दे रहा था तो शायद मेरे शब्द माननीय मुख्य मंत्री

13/1200/03.2015.यूके/एजी/3

महोदय को या अन्य सदस्यों को अच्छे नहीं लगे । कांगड़ी शब्द में मैने कुछ कहा था जिसके लिए यदि आपके मन को ठेस पहूंची है तो मैं उन शब्दों को वापिस लेता हूं । धन्यवाद ।

अध्यक्षः अब इस विषय पर बहुत चर्चा हो गयी है । जिस पर माननीय धूमल जी ने भी कहा और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी जवाब दे दिया था । तो इस मामले को किसी और तरीके से निपटाया जाए । अब स्थगन प्रस्ताव की जरुरत नहीं है ।

13/1200/03.2015.यूके/एजी/4

<u>राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चाः</u>

अध्यक्षः अब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी । मैं विपक्ष के नेता माननीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं ।

श्री प्रेम कुमार धूमलः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 11 मार्च, 2015 को इस सदन में सम्बोधित किया और उनके अभिभाषण के लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में लाया गया है, मैं उस चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष महोदय, जब राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण के केवल प्रारम्भ का

एस0**एल0एस0 द्वारा जारी**---

13.03.2015/1205/sls-jt-1

प्रो० प्रेम कुमार धूमल...क्रमागत

अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने केवल प्रारंभ का पैराग्राफ पड़ा और अंतिम पैराग्राफ पढ़कर अभिभाषण खत्म कर दिया तो हमें भी आश्चर्य हुआ था कि यह क्या हुआ। लेकिन जब अब हमने यह सारा अभिभाषण पढ़ा तो मैं इसके लिए राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छा किया जो नहीं पढ़ा क्योंकि इसमें पढ़ने लायक कुछ था ही नहीं।...(व्यवधान)...

(**श्रीमती आशा कुमारी ,सभापति, अध्यक्ष पीठ पर पीठासीन हुई।**)

मुख्य मंत्री : यह जो आप कह रहे हैं, यह राज्यपाल महोदय के ऊपर आक्षेप है। जो पार्लियामैंट्री प्रथा है, उसके अनुसार कई बार लोकसभा में भी होता है कि पहला पृष्ठ पढ़ा जाता है, फिर आखिरी पृष्ठ पढ़ा जाता है and it is considered as read. इसलिए आप इस किसम की बातें मत कीजिएगा। आप गवर्नर साहब को बीच में मत लाइए। गवर्नर साहब को बीच में न लाकर आपने जो कहना है, अपनी तरफ से कहिए।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : सभापति महोदय, संसदीय परंपरा की चर्चा माननीय मुख्य मंत्री ने की है। मैं परंपरा को भली प्रकार से जानता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति ने पहला पैरा पढ़ा हो और लॉस्ट पैरा पढ़कर कहा हो कि मैंने पढ़ दिया जो पढ़ना था। लोकतंत्र में आलोचना सुनने की क्षमता रखिए। आप बहुत वरिष्ठ हैं।

...(व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : आप सरकार की आलोचना कीजिए, गवर्नर की आलोचना मत कीजए।
प्रो० प्रेम कुमार धूमल : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री को मुझे संसदीय परंपरा बोलने से पहले यह समझना चाहिए कि उनको आपको रैफर करना चाहिए था कि मैंने यह प्वायंट उठाना है। आपकी अनुमति होती और अगर मैं यील्ड करता तो वह बोलते। संसदीय परंपरा यह भी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बात क्या है। आप शुरू में ही इतना उछल रहे हैं, अभी तो मैंने प्रारंभ ही

नहीं किया। जो उन्होंने पढ़ा, मैं उसमें सभापति महोदय डिटेल में आऊंगा। उन्होंने कहा कि जो चुनाव घोषणा-पत्र था, उसको हमने नीतिगत दस्तावेज मान लिया और अधिकांश वायदों को पूरा कर दिया है। मैं चुनाव घोषणा-पत्र की बातें बाद में करूंगा। तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने पढ़ा नहीं लेकिन आपने यह लिखा था। मैं राज्यपाल महोदय का तो सम्मान करता हूं कि उन्होंने इस घोषणा-पत्र में हमें याद दिला दी। इसमें काफी लंबा

लिखा है कि हमने यह किया, वह किया, इतने स्कूल स्तरोन्नत कर दिए। जिन माध्यमिक और उच्च पाठशालाओं को स्तरोन्नत किया है, यह कुल 459 बनते हैं जिनमें 234 मिडल स्कूल और 225 हाई स्कूल अपग्रेड किए हैं। आपके ध्यान में एक रिपोर्ट भी आई होगी। नए स्कूलों और नई संस्थाओं की घोषणा आप ऐसे कर रहे हैं जैसे टाफियां बांटते हैं। लेकिन जब हमारे समय में कालेज खुले थे तो आपने वह अधिसूचना रद्द कर दी थी। आपने हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में ऐफिडेविट दिया था कि कोई भी कालेज खोलने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ता है, स्टॉफ का प्रावधान करना पड़ता है। क्योंकि इसके लिए नहीं था और हमारे संसाधन इतने नहीं हैं इसलिए आपने उच्च न्यायालय में यह अपील की थी। क्या अब संसाधन आ गए हैं? क्या अब इंफ्रास्ट्रक्चर बगैरहः तैयार है? क्या वहां पर प्रोफ़ेसर्ज़ लग गए हैं?

जारी ..गर्ग जी

13/03/2015/1210/RG/JT/1

प्रो. प्रेम कुमार धूमल----क्रमागत

क्या वहां प्रोफैसर्ज लग गए हैं, क्या वहां टीचिंग स्टाफ पूरा है ,क्या वहां लैबोरैट्रीज़ बन गई हैं? ये सवाल हैं ,जो आप एक-एक और दो-दो किलोमीटर पर शिक्षा संस्थान खोलने की घोषणाएं करते जा रहे हैं। इसी प्रकार मेरे चुनाव क्षेत्र में एक स्कूल है जिसमें 17 बच्चे हैं और 7 अध्यापक हैं।

सभापति महोदया(श्रीमती आशा कुमारी) ,एक रिपोर्ट के मुताबिक 1117, स्कूल इस प्रदेश में ऐसे चल रहे हैं जहां केवल एक अध्यापक है 6,786 ,स्कूल ऐसे चल रहे हैं जहां केवल दो अध्यापक हैं और 510 स्कूल ऐसे हैं जहां स्कूल की बिल्डिंग का केवल एक कमरा है। अगर कोई कहे कि शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है और रिपोर्ट्ज आ रही हैं कि 5वीं और छठी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा पहली-दूसरी कक्षा की किताब भी नहीं पढ़ सकता और आप अंग्रेजी को पहली कक्षा से इन्ट्रोडियुज करने की बात कर रहे हैं। शिक्षा के स्तर का गिरने का मुख्य कारण अध्यापक नहीं है , मुख्य कारण सरकार है। जब स्टाफ पूरा नहीं होगा ,इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं होगा

और सुविधाएं पूरी नहीं होंगी ,तो क्या होगा? जहां 1,117 स्कूल ऐसे चल रहे हैं जिनमें एक ही टीचर हो ,तो वह किस क्लास में कब जाता होगा और किस क्लास को क्या पढ़ाता होगा? जहां 6,786 स्कूल ऐसे हैं जिनमें दो अध्यापक हैं ,तो वे क्या-क्या विषय पढ़ाते होंगे! आपने तो महामहिम को लिखकर दिया है कि 'प्रदेश में शैक्षणिक स्तर में सुधार की वचनबद्धता के अनुरूप', आगे लिखते मेरी सरकार 1,117 स्कूलों में एक ही अध्यापक देगी। वचनबद्धता तो यह हुई। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियों की अपेक्षा घोषणाएं हुई हैं। जहां विद्यार्थी नहीं हैं वहां अध्यापक हैं, जहां विद्यार्थी हैं वहां अध्यापक नहीं हैं। इसको आप रेशनलाइज करिए। मुख्य मंत्री महोदय, शिक्षा विभाग आपके पास है और यह एक बहुत बड़ा विभाग है। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री को कई और काम भी देखने होते हैं ,कई अन्य महत्वपूर्ण विभाग आपके पास हैं , लेकिन अधिकारी तो आपके अधीन हैं ,आप नीतिगत डायरैक्शन दे सकते हैं। इसलिए इसको आप रैशनलाइज करिए और जहां विद्यार्थी हैं वहां अध्यापक भेजिए और जहां विद्यार्थी नहीं हैं वहां से अध्यापकों को हटाइए। रेशनलाइजेशन से यह ठीक होगा।

सभापति महोदय, जब वर्ष 1998 में पहली बार हमारी सरकार बनी थी ,तो हमने भी एक सर्वे कराया था ,उस समय एक हजार में से 64 स्कूल ऐसे थे जहां

13/03/2015/1210/RG/JT/2

प्राइमरी स्कूल में एक भी कमरा नहीं था। आप उस समय इधर (विपक्ष) बैठते थे और आपने भी उस समय यह स्वीकार किया था। हमने सरस्वती बाल विद्या संकल्प योजना लागू की और 126 करोड़ रुपये का ऋण नाबार्ड से लिया और 13,672 कमरे तीन वर्षों में बनाए गए थे। आप भी कोई ऐसी योजना सोचिए 510 ,स्कूलों में तो संख्या कम है, कमरे ज्यादा बनाए जा सकते हैं ,ऐसी संभावना इसमें है।

सभापति महोदया, मैं इनका चुनाव घोषणा-पत्र देख रहा था। जैसा महामहिम के अभिभाषण में लिखा गया कि हमने चुनाव घोषणा-पत्र के अपने वायदे पूरे कर दिए। इसके पेज-5 पर यह है कि 'संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन' और आपने इसमें दूसरे नंबर पर लिखा है कि 'हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में गुणवत्तापूरक सुधार हेतु खाली पदों पर निष्पक्ष चयन लोक सेवा आयोग एवं

अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के द्वारा किया जाएगा अर्थात ट्रांसपैरेंसी हो ,निष्पक्ष चयन हो। आपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वायदा किया था कि सारी नियुक्तियां आप अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के माध्यम से और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से करेंगे।----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

13/3/2015/1215/MS/AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी------

आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में एक वायदा किया था कि सारी भर्तियां सुबोर्डिनेट सर्विसिज सिलैक्शन बोर्ड के माध्यम से और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से करेंगे। कल ही मामला यहां इस बारे में उठ रहा था और कन्डक्टर्ज की भर्ती का मामला पहले ही कोर्ट में गया है। नर्सों के मामले में भी यही रिपोर्ट आ रही है। अलग-अलग डिपार्टमैंट्स को कोपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से, युनियन के माध्यम से और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे समय में जब जे0पी0 नड्डा जी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे तो तीन अस्पतालों में सिक्योरिटी को ओपन टैण्डर के माध्यम से आउटसोर्स किया गया था। पांच साल आपने हमारी इन्क्वायरी करवाई थी। एक पुलिस अफसर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने फाइल पर लिख दिया "look into the aspect of the involvement of the then Chief Minister, Prof. Prem Kumar Dhumal and the then Health Minister, Shri J.P. Nadda" और उसको आपने विजीलैंस को मार्क किया। आपने आरोप लगाया था कि आउटसोर्सिंग करना गलत है और होमगाड्र्ज के जो नौजवान हमारे होते हैं उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। अब चर्चा यह शुरू हो गई है कि इन होमगाड्र्ज को वहां से हटा रहे हैं और अब आउटसोर्स कर रहे हैं। जो बात वर्ष 1998-2003 में गलत थी ,वह आज ठीक कैसे हो गई ?आपके चुनाव घोषणा पत्र का यह वायदा कि निष्पक्ष सिलैक्शन के लिए हम पब्लिक सर्विस कमीशन और सुबोर्डिनेट सर्विसिज सिलैक्शन बोर्ड के माध्यम से सिलैक्शन करेंगे, उसका क्या हुआ? राज्य में उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं समस्याओं के निवारण हेतु उपभोक्ता मंच की संभाग

स्तर पर सर्किट बैंचों की स्थापना की जाएगी तो कितने नये सर्किट बैंच बने? किस-किस संभाग में बने हैं? इसका जिक्र, क्योंकि जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है ,उसमें सरकार की एक साल की उपलब्धियों का जिक्र होता है। वह एक तरह से इतिहास होता है जो आपने पहली अप्रैल से लेकर अब तक किया है। जब आप बजट भाषण पढ़ेंगे तो प्रदेश के सामने अगले एक साल का नक्शा प्रदेश और विधान सभा के सामने रखेंगे कि बजट के माध्यम से अगले साल में हम यह-यह कार्य करेंगे। अभिभाषण में वह आना चाहिए था कि कितनी जगह आपने स्थापना कर दिए।

13/3/2015/1215/MS/AG/2

जन-समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना की जाएगी। यह कौन सी प्रणाली बनी है, इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है कि आपने प्रणाली स्थापित कर दी। इसी तरह से राज्य स्तर पर सशक्त पब्लिक ग्रिवेंस कमीश्नर नियुक्त किए जाएंगे ताकि जनता की शिकायतें सरकारी लाल फीताशाही में महीनों और सालों न दब जाएं। हर शिकायत का निश्चित समय के भीतर जवाब न देने पर सरकारी मंत्रालय और अफसर की पूर्ण जवाबदेही तय की जाएगी और ग्रिवेंस कमीश्नर को एक हक प्राप्त होगा कि दोषियों को सजा दे सके। यह कहां बना है और कौन है गिवेंस कमीश्नर?

सभापति महोदया, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि आम आदमी की ग्रिवेंस कितनी रिड्रेस होती है परन्तु हमने जो पत्र आज तक आपको लिखे हैं, उन पर की गई कार्रवाई का जवाब क्या आना, हमें पावती तक नहीं आती। उदाहरण के तौर पर, मेरे जिला से एक शूटर विजय कुमार है। उन्होंने कॉमनवैल्थ में गोल्ड मैडल जीते हैं। एशियन गेम्ज में भी मेडल जीते और जब नेशनल गेम्ज हो रही थीं तो उनको दो गोल्ड मेडल वहां मिले। लगातार उनको अर्जुन अवार्ड और पदमश्री अवार्ड मिल चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत कुछ मिला है।

श्री जे0के0 द्वारा जारी----------

13.03.2015/1220/जेके/ऐजी/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः----जारी------

केन्द्र सरकार ने उन्हें बहुत सम्मानित किया है। प्रदेश में खेल रत्न अवार्ड, राजीव अवार्ड यदि है उसके लिए उसने एप्लाई किया है और मैंने भी आपको पत्र लिखा है। जब केन्द्र उसे पदमश्री अवार्ड से सम्मानित कर सकता है और उसे अर्जुन अवार्ड मिल सकता है तो हम भी उसे स्टेट में कोई सम्मान दे सकते हैं। वह भी कहेगा कि मेरी स्टेट ने मेरा सम्मान किया है। वह सेना में है। लेकिन मेरा लैटर भी एक्नोलेज़ नहीं हुआ है, जो पत्र मैंने आपके विभाग को भेजा है।

आपने लिखा है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। पारदर्शी एवं स्वच्छ प्रशासन। धर्मशाला में केबिनैट फैसला करती है कि इस बार ज्यादा इन्कम हो इसलिए शराब के ठेकों की नीलामी होगी। हफ्ते के बाद शिमला की केबिनैट में निर्णय लिया जाता है और पता नहीं कि एक सप्ताह में क्या डवैल्पमैंट हुई और सरकार का विचार बदल गया। पिछले दिनों समाचार-पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि चण्डीगढ़ की शराब में हिमाचल के एक्साईज डिपार्टमैंट की मोहर लगी थी जिसको पकड़ा गया। कुछ शर्तें लग रही है कि उनका कोटा बढ़ाया जा रहा है या नहीं। अगर ज्यादा कन्जम्पशन होगी तो क्या अन्देशा है कि स्मगलिंग बाहर से होगी। अगर आप यह पारदर्शिता यहां पर जाहिर कर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। समाचार पत्र भरे पड़े हैं।

सभापति महोदया, लाहौल स्पिति में, श्री रवि ठाकुर जी आज बैठे नहीं है उनका भी बयान आया था कि लाहौल वालों का ख्याल करो। लाहौल में 5 माह पहले साढ़े चार करोड़ रूपये से बना पुल ध्वस्त। घटिया सामग्री से बना था घपले का पुल। जांच के आदेश। आज मैंने खबर देखी कि रिर्पोट बनाने में लीपापोती की जा रही है। यदि उसी विभाग के लोग इन्क्वायरी करेंगे तो सच्चाई सामने क्या आएगी? 11मार्च को खबर लग रही है कि अभी बन्द है कुल्लू, किन्नौर की 36 सड़कें। ठियोग-हाटकोटी सड़क का मुद्दा हमारे चुनाव के समय में भी था। उस समय तो आपने कहा था कि हम इस काम को बड़ी तीव्रता से करवाएंगे। परसों की खबर है कि हाटकोटी

13.03.2015/1220/जेके/ऐजी/2

सड़क पर लग रहा है डबल टाईम। यह काम क्यों नहीं हो रहा है? अब तो दोबारा से टेंडर हो गए हैं, अवार्ड हो गया है। अंधेरे में कट रही है चौपाल की सर्द रातें। 24 घण्टे के अन्दर बिजली बहाल नहीं हुई तो करेंगे प्रदर्शन। "10 days on, Chopal sub-division reels in darkness" कल 12 मार्च की खबर, चौपाल में 10 दिन से बत्ती गुल। सभापति महोदया ऐसी जन समस्याओं के प्रति कौन जागरूक होगा? विशेष उड़ान से कुल्लू पहुंचाया झुलसा व्यक्ति। मिसाल बन कर खुद की जिन्दगी दाव लगा कर जान बचाई। सरकार के भरोसे रहता तो जिन्दा न रहता। यह संवेदनशील प्रशासन का कोई सबूत नहीं है।

श्री एस.एस.द्वारा जारी-------

13.03.2015/1225/SS-AG/1

प्रो प्रेम कुमार धूमल क्रमागतः

मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में हमीरपुर शहर में अदित्य नाम का पांच साल का बच्चा शहर के नज़दीक से घुम हुआ है। उसका कोई निशान नहीं है। कोई पता नहीं लग रहा है। कानून-व्यवस्था की स्थिति का भी आपने अपने अभिभाषण में राज्यपाल महोदय से दावा करवाया कि बहुत ठीक रही है। उसी कानून-व्यवस्था पर हम चर्चा मांग रहे हैं। घटनाएं प्रदेश की राजधानी में हो रही हैं। आप कांगड़ा प्रवास पर थे। बलात्कार के मामले हो रहे हैं। एक 10-11 साल की बच्ची शादी में आई हुई थी, उसे उठाकर ले गए। उसके साथ बलात्कार हुआ। क्या बलात्कारी आज तक पकड़े गए। चोरी, डकैती, बलात्कार के मामले हो रहे हैं और सभापति महोदया, चोरी, डकैती, झगड़ों और ऐसे अनैतिक व्यवहार का सबसे बड़ा कारण नशा है। अभिभाषण में उसका कोई ज़िक्र ही नहीं है। आपकी सरकार के लिए जो नशे की समस्या सारे देश में है प्रधान मंत्री उस पर अपील कर रहे हैं उसका जितना ज़िक्र होना चाहिए था, वह ज़िक्र यहां अभिभाषण में कहीं नहीं है। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमारे प्रदेश में लोग नशे के कारण मरे हैं। हम पड़ोसी प्रदेश पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां से नशे का सामान आ रहा है। पड़ोसी हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि हिमाचल से आ रहा है। नौजवान हमारे भी मर रहे हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसका ज़िक्र ही नहीं है। आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? नशाखोरों को और नशा बेचने वालों को

कोई पकड़ने वाला नहीं है। चोर-डकैतों को पकड़ने वाला नहीं, बलात्कारियों को पकड़ने वाला कोई नहीं। एक काम की मैं आपको बधाई देता हूं जो लगातार हो रहा है। डी0ओ0 नोट पर टीचर के धड़ाधड़ हो रहे ट्रांसफर। बैन के बावजूद रोज़ 50 से ज्यादा तबादले। मई में आपने बैन लगा दिया था। ये संडे की बिग स्टोरी अखबार में लगी है और इसमें गिन कर उन्होंने कहा कि 50 तो कम-से-कम डेली तबादले होते हैं और बैन में रिलैक्सेशन तो मुख्य मंत्री महोदय आप ही देते होंगे? आप यह क्यूं कर रहे हैं, कहां से शिक्षा का स्तर ठीक होगा जब मिड सैशन ट्रांसफर होती रहेंगी? इसीलिए तो बैन लगता है कि ट्रांसफर न हों। हां आपका अधिकार है, मान लो जब कोई गम्भीर तौर से बीमार है अगर समस्या है तो ट्रांसफर करिये। उसको कोई रोकेगा नहीं। बल्कि उसके लिए आपको लोग एप्रोच करेंगे कि इसको ट्रांसफर कर दो क्योंकि बड़ा जैनुअन केस है। लेकिन डेली ऐसे 50 केस नहीं हो सकते जहां रिलैक्सेशन हो। इसकी ज़रा जांच करवाईये। वैसे तो आपको पता होगा, आपकी

13.03.2015/1225/SS-AG/2

जानकारी के बगैर हो नहीं सकता। जिन लोगों के डी0ओ0 चलते हैं वे इलाके में सब जगह आम मशहूर हैं कि फलां आदमी का डी0ओ0 लो रेट इतना है। इस ट्रांसफर को रूकवाने का इतना रेट है और इसको करवाने का इतना रेट है। यह कुछ लोगों का धंधा बन गया है।

मुख्य मंत्रीः मुझे आप यह लिखकर दीजिए कि ट्रांसफर के लिए कौन पैसे ले रहा है, किसका क्या रेट है। अगर आप मुझे गुप्त रूप से सूचना भेजेंगे तो उससे मेरी मदद होगी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः एक तो मैं अभी सिरमौर गया था, पांवटा में कोई बैठते हैं आपका नाम लेकर। लोगों में आम चर्चा है। हमारे विधायक आपको सूचना दे देंगे लेकिन मैंने पहले ही कहा कि आपको सब जानकारी है। ऐसा है, आप सर्वव्यापी मुख्य मंत्री हैं। 6 बार का मुख्य मंत्री और आपको जानकारी नहीं है। सदन में तो सच बोलना चाहिए। --(व्यवधान)-- आपके पूर्व मित्र माननीय विधायक बिक्रम ठाकुर ने आपको नाम बताया भी हुआ है। फिर आपको बता देंगे। ये बहुत चर्चा है। इसलिए मैंने पूर्व ही कहा। --(व्यवधान)—

जारी श्रीमती के0एस0

/1230/03.2015..13केएस/जेटी/1

श्री प्रेम कुमार धूमल जारी---

सभापति महोदया, प्रशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुलिस और रेवन्यू विभाग के अधिकारी है। मुख्य मंत्री जी, आप सब -डिविज़न, सिविल की अनाऊंसमैंट पर अनाऊंसमैंट करते जा रहे है। ऐसे तहसील व सब-तहसील दे रहे हैं जैसे जेब में टॉफी डाली है और किसी ने मांग ली तो दे देते हैं कि ले यार तू भी चूस ले। मेरी तहसील टौणी देवी में आप गए, आपका धन्यवाद आप आए, निमंत्रण तो दिया नहीं था। आपने वहां भवन का शिलान्यास किया। वहां पहले से ही नायब तहसीलदार नहीं था और जिस दिन आपके वहां चरण पड़े तहसीलदार भी ट्रांसफर हो गया। अब वहां न तहसीलदार है और न नायब तहसीलदार है। नदौन में दो महीने से उप-मण्डलाधिकारी नदारद, यह दो मार्च की खबर है और इस तरह की जब मैं बात करता हूं तो हमारे विधायक बताते हैं कि उनके क्षेत्रों में भी यही स्थिति है और आपके प्रश्नों के जो उत्तर आते हैं उनमें भी आप स्वयं मानते हैं कि इतनी पोस्टें खाली है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सब-डिविज़नल ऑफिसर्ज़, सिविल इनसे लोगों का दिन प्रतिदिन बहुत काम होता है। वह भी जिक्र आना चाहिए था कि उनकी कमी को दूर करने के लिए आप क्या करेंगें? अवैध खनन के बारे में आपने कहा है कि हम खनन नीति बनाएंगें। अब यह हमीरपुर केसरी पहली मार्च ---घण्टी-- मैडम अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है, अभी घण्टी नहीं बजनी चाहिए।

श्रीमती आशा कुमारी, सभापतिः सर, 30 मिनट आपको अलॉटिड थे और 29 मिनट हो गए हैं।

/1230/03.2015..13केएस/जेटी/2

श्री प्रेम कुमार धूमलः सभापति महोदया, हमीरपुर केसरी पहली मार्च की खबर "सी.एम. के दरबार पहुंचा अवैध खनन" आपके पास भी शिकायत पहुंची ग्राम सुधार सभा की तरफ से और खनन एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है । आपने अपने चुनाव घोषणापत्र में कहा कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत कुछ करेंगें। आपके चुनाव

घोषणापत्र में भी है और महामहिम के अभिभाषण में भी लिखा है । आप उत्तर दें तो अच्छा होगा, मंत्री महोदय दें तो भी ठीक है ।

मुख्य मंत्रीः सभापति महोदय, अगर मैं चाहूं तो जो धूमल जी कह रहे हैं मैं इनका उत्तर दे सकता हूं लेकिन मैं इनके भाषण में खलल नहीं डालना चाहता। आप कहते जाइए, जब हमारा वक्त आएगा हम उसका उत्तर देंगें। आप ये नहीं समझें कि हमारे पास उत्तर नहीं है । आप जो बातें कह रहे हैं, it is not based on facts. But I don't want to intervene while you are speaking.

श्री प्रेम कुमार धूमल :आपके पास उत्तर है और हम यही चाहते हैं कि ठीक उत्तर दें और मैं फैक्ट्स ही ला रहा हूं। हर बार पोलिटैक्निक कॉलेजिज़ की ऐडमिशन के समय ,टैक्निकल इंस्टीट्यूशन्ज़ की एडमिशन के समय आप एक रीस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि 65 प्रतिशत से कम नम्बर वालों को एडमिट नहीं करेंगें और यह क्या होता है, लगातार दो साल हो गए चुनाव से एक दिन पहले लोग आपको मिलते हैं, कैसे मिलते हैं वह आप जानते हैं और वह रीलैक्सेशन एक दिन के लिए एक रात के लिए हटती है, उसमें एडमिशन्ज़ होती है और मैं विधान सभा में चैलेंज़ करता हूं, यह फैक्ट्स है लास्ट डे पर कितनी एडमिशन्ज़ हुई और

/1230/03.2015..13केएस/जेटी/3

पहले दिन कितनी एडमिशन्ज़ हुई और हमने मामला उठाया था कि जिन बच्चों को आप कह रहे हैं कि मैरिट में नहीं है, इनको हम यहां दाखिला नहीं देंगें वे पड़ौस के राज्यों में दाखिल हो गए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी-

श्री प्रेम कुमार धूमल ----------**जारी**

वे पड़ौस के राज्यों में दाखिल हो गए। मैंने पूछा था कि अगर कल को पॉलीटैक्नीक का डिप्लोमा करके या बी.टेक. करके वहां से आयेंगे तो क्या आप उनकी जॉब के लिए एंट्री बैन करेंगे? जब वे किसी युनिवर्सिटी से बी.टैक. करके या क्वालीफाई होकर आते हैं तो क्या वे अप्लाई करने के लिए कम्पिटैंट होंगे? ऐसा क्यों होता है कि लास्ट डे तक ऐडमिशन पर पाबंदी रहती है। आपका स्टैंडर्ड पंजाब/हरियाणा से ज्यादा ऊंचा होता है। लास्ट नाइट या लास्ट डे वह स्टैंडर्ड डाउन क्यों कर दिया जाता है?(---व्यवधान---) यह बात तथ्यहीन नहीं है। मैं तथ्य पर बात कर रहा हूं। आप जब जवाब देंगे तो बताना कि कब-कब हुआ है। हम भी बता देंगे कि क्या-क्या हुआ है। (---व्यवधान---) सबको मुट्ठी में कर दिया है।

वन एवं पर्यावरण पर कहना चाहता हूं। जितने अवैध कटान के मामले हुए हैं, उस बारे में आपने क्या कार्रवाई की है? आज ट्रिब्यून में फिर से नादौन के बारे में खबर लगी है कि 49 दरख्त काटे गए। आपके चुनाव घोषणा पत्र में आपने किसानों/बागवानों के लिए पॉली-हाउस लगाने के लिए 90 प्रतिशत सबसिडी देने की बात की है और अभिभाषण में 85 प्रतिशत का जिक्र है, जो पहले भी मिलती थी।

बंदरों के आंतक से बचाव हेतु कारगर कदम उठायेंगे। आपने क्या कदम उठाये हैं? दूध व इसके प्रोडक्ट को बाजार तक ले जाने के लिए हम चीलिंग प्लांट लगायेंगे। पिछले दो वर्षों में प्रदेश में कितने चीलिंग प्लांट लगे हैं? इसके अतिरिक्त कितने चारा बैंक बने हैं?

सभी स्कूली बच्चों को; विशेषकर बालिकाओं के लिए। मैंने पहले भी जिक्र किया कि स्कूलों में शौचालयों की कमी है। वर्तमान में डिफरैंटली डिसेबल बच्चों के लिए लगभग 90 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय नहीं है।

13.3.2015/1235/ag/av/2

आपने सारे प्रदेश में कौशल विकास भत्ता के संदर्भ में बहुत बोर्ड लगाये। शायद इतना पैसा लोगों को नहीं मिला जितना आपने बोर्ड लगाने पर खर्च कर दिया। इसमें आपके ही केबिनैट मंत्री ने डिमाण्ड की है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। कितने लोगों को कौशल विकास भत्ता मिला? जहां उनके कौशल को विकसित किया जा रहा है क्या उन इनस्टिच्यूशन में कोई इनस्पैक्शन होती है? कांग्रेस पार्टी एक कौशल विकास ऑथोरिटी का गठन करेगी और अगले 5 वर्षों में लगभग 5 लाख रोजगार सृजित करने की कोशिश करेगी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन दो वर्षों में कितने हुए? मेरे हिसाब से दो लाख रोजगार तो सृजित हो जाने चाहिए थे। आप कहते हैं कि पंजाब से डी-लिंक करना है। आप अपना चुनाव घोषणा पत्र पढ़िए। आपने लिखा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भत्ता पंजाब की तर्ज पर निश्चित चिकित्सा पूर्ति को प्रति माह 5 सौ रुपये कर दिया जायेगा। मैं कल-परसों अखबार में पढ़ रहा था, वे तो अब इसकी मांग कर रहे हैं कि 5 सौ रुपये करो। कौन-कौन से वायदे पूरे हुए हैं? डॉक्टरों और नर्सों के सभी पद भर दिए जायेंगे। आपने कितने भर दिए?

शिमला, हमीरपुर, पठानकोट के लिए वर्ष 2016 तक फोरलेन राष्ट्रीय उच्च मार्ग पूरा कर लिया जायेगा। फोरलेन कहां बना? मैडम, मैं ----------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

13.3.2015/1240/negi/ag/1

माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ... जारी..

मैं आपके प्वाइंट्स पर ही आ रहा हूं। आपने पर्यटन पर बहुत कुछ लिखा है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। विश्व में शायद एक मात्र स्टेट आपकी है जिसने जब पीछे भारी बर्फबारी हुई तो कुल्लू-मनाली जैसे स्थान पर एक सप्ताह तक लोगों ने बर्फ पिघला करके पानी पिया है । और आप पर्यटन को विकसित करेंगे। आपके अधिकारियों ने ब्यान दिया कि कोई न आए कुल्लू-मनाली हम आपका ध्यान नहीं रख सकेंगे। यह

महकमा आपके (मुख्य मंत्री) पास ही होगा। मैं अब सिलेक्टिड पैरों पर ही आ रहा हूं, आपने एक और कहा , बन्दरों की समस्या का उचित समाधान निकाला जाएगा। यह दो बार आ गया है। जंगलों में वानर शरण्य स्थल, प्राइवेट पार्क्स बनाए जाएंगे ,आपने लिखा है। मुझे लगता है यह वही होगा। आवारा पशुओं, कुत्तों और जंगली जानवरों के लिए भी नीति बनाई जाएगी । आपने कितने शरण्य स्थल बनाएं हैं ? कहां-कहां बन्दरों के लिए बनें वो ?उनके खाने का क्या प्रावधान किया है? आवारा पशुओं और आवारा कुत्तों के लिए आपने कोर्ट में एक एफिडेविट दे दिया कि हम पंचायतों को फंड देते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायतों के प्रधानों के गले में फांसी का फंदा डाल दिया कि 31 मार्च तक गौशाला बनाओ। श्री अनिल शर्मा जी को पता चलेगा जब पंचायत प्रधान इसके लिए फंड मांगेगा। जहां सरकार नहीं बना सकती, अगर सब जगह आप चाहें तो नहीं बन सकती, मैं मानता हूं कि यह प्रेक्टिकली डिफिकल्ट है तो पंचायत कहां से बनाएगी ?

आपने मज़दूर की दिहाड़ी 200 रूपये करने का वायदा किया था, वो नहीं हुई। ।अब तो मनरेगा के अन्तर्गत जो पैसे मिलेंगे उसमें भी कनैक्शन यही होगा कि जितना प्रदेश सरकार देती है उस हिसाब से केन्द्र देगा। यह सबसे कम हमारे है मनरेगा की दिहाड़ी, उसको बढ़ाइये। आपने रेल के हेड के अन्दर कहा कि रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम परिवहन की तर्ज़ पर हिमाचल राज्य परिवहन खान-पान निगम की स्थापना की जाएगी । ...(व्यवधान) ..वो हमने ही बनाया था जो अपना घोषणा-पत्र था। मेरे पास भी सुझाव आया था कि आपको बेरोज़गारी भत्ते की घोषणा कर देनी

13.3.2015/1240/negi/ag/2

चाहिए। यहां बैठे हैं कई माननीय सदस्य। मैंने उन्हें कहा था कि यह प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें प्रेक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा किया आपने याद दिलाया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, महौल और ज्यादा भारी हो जाए, कौल सिंह जी बैठे-बैठे टिप्पणी कर रहे हो आप, मैं आपको कहना चाहूंगा :-

शोहरत की बुलन्दी भी दो दिन का तमाशा है,
जिस शाख पर बैठे हो, वो टूट भी सकती है।

राज्य के ऐसे बेरोज़गार, 10+2 व स्नातक युवाओं जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रूपये तक है, को 1000 रूपये प्रतिमाह की दर से बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। विक्लांग बेरोज़गार स्नातक युवकों को बेरोज़गारी भत्ते की दर 1500 रूपये प्रति माह होगी। जब आप जवाब देंगे तो जिन-जिन को यह दिया है उनके आंकड़े नाम व पते सहित दे देना।...(व्यवधान) ...इनको पता ही नहीं है कि मैनिफेस्टो में है कि नहीं है।

अनुबन्ध के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को 5 वर्ष के उपरान्त नियमित कर दिया जाएगा। अनुबन्ध वाले कितने कर्मचारी रेगुलर हुए 5 साल के बाद? आपने एक और बात कही।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

13/1245/03.2015.यूके/एजी/1

श्री प्रेम कुमार धूमल-----**जारी**----

और आपने एक और बात कही, सभी सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पड़े हजारों पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा । कितने भरे गए ? जिससे हजारों बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा ।

मुख्य मंत्रीः करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे ।

श्री प्रेम कुमार धूमल : तो आपने क्या मैनीफैस्टों को नीति दस्वावेज बनाया ? इसीलिए मैने पहले कह दिया कि धीरे-धीरे चलने वाली बात नहीं है, शोहरत की बुलन्दी वाली बात है, कभी भी शाख टूट सकती है । What policy has been formed? मैने पूछा है आपसे, बोर्डों, निगमों में ठेके पर जो नियुक्तियां हुई हैं, उनको भी रेगुलर करने की बात कह रहे हैं । और एक बात और कर्मचारी आ रहे हैं, बहुत सारे डेपुटेशन मिलते हैं कहते हैं कि अचानक ऐक्सटेंशन हो जाती है । कभी कुछ लोगों को 59 साल तक, कभी कहते हैं, होगी, कभी कहते हैं नहीं होगी । जो 58 साल

में रिटायर होना था, वह मुख्यमंत्री महोदय, अपने सचिवालय से पता करिए ,जिन लोगों को आपने 59 साल की ऐक्सटेंशन दी है । उनमें से कितने लोगों ने कितने दिन दफ्तर में काम किया है, कितने लोग हैं जिन्होंने मैडिकल लीव और अर्न्ड लीव जो बची हुई थी, उनको यूज़ कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन आते हैं, सोमवार को आ गए फिर छुट्टी ले लेते हैं । आपका कोई काम नहीं हो रहा है । बाकी के कर्मचारी इस कर के काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमने तो 58 साल में रिटायर हो जाना है, हम पर कृपा होनी कि नहीं होनी, हमारी प्रोमोशन ही नहीं होनी। रिटायर के समय एक स्टैप की प्रोमोशन हो जाए तो वह भी बहुत बड़ा लालच होता है, कर्मचारी के लिए । तो आपने ऐक्सटेंशन दे दी है सबको । आपकी बात का पता नहीं लगता, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कह देते हैं ।

मंदिरों के बारे में आप बड़े संवेदनशील हैं । सभापति महोदय, कल शायद आपका भी एक प्रश्न था लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में और उसकी सुरक्षा का

13/1245/03.2015.यूके/एजी/2

वायदा भी किया है । लेकिन मंदिरों में भी चोरियां हो रही हैं । "रघुनाथ जी की मूर्ति की रहस्यमयी चोरी" वह रहस्य ही रहा और उसकी बरामदगी में रहस्यमयी है । कमाल तो यह है कि टीम ने वहां एक जगह जा कर उसी जगह पर खुदाई की जहां पर मूर्ति दबी थी । वह सूचना कहां से आई ? चोर तो, आप कहते हैं कि हमारा समझौता नहीं है नेपाल के साथ, इसलिए आ नहीं रहा इंटरपोल के माध्यम से । मान लेते यदि उन्होंने उस स्पॉट पर आते-आते ,7-5 या 10-15 किलोमीटर या आधा किलोमीटर या एक फर्लांग ही खुदाई की होती, लेकिन ऐग्जैक्ट स्पॉट पर हुई । आपने बयान भी दिया कि हम एक ट्रस्ट बनाएंगे । पहले जब मूर्ति चोरी हुई तो आपने कहा कि यह प्राईवेट मकान में थी, प्रापर्टी तो सबकी प्राईवेट होती है और जान-माल की रक्षा करना प्रदेश सरकार का जिम्मा है ही सबका, चाहे वह प्राईवेट मकान है चाहे अन्य है। लेकिन जिसमें लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है उस मूर्ति की सुरक्षा और जहां उस मंदिर में 11 महीने पहले भी चोरी हुई है । कोई नहीं पूछेगा कि प्राईवेट में थी तो आपका जिम्मा नहीं था । सब यह पूछेंगे कि सरकार क्या कर रही थी ? उसी ढंग से वह चोरी हुई, जिस ढंग से पहले चोरी हुई थी, तो आपने कहा कि ट्रस्ट बनाएंगे तो फिर ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के ट्रस्ट बनाइए । जो महत्वपूर्ण और बहुमूल्य मूर्तियां हैं, दुनिया भर में और हिमाचल प्रदेश में ऐसे पहले भी मूर्तियां चोरी

हुई हैं । किन्नौर से भी हुई थी पता है बड़ा मशहूर किस्सा है । उनकी करोड़ों रूपए की कीमत होती है । तो मूर्तियों की चोरी और उनकी सुरक्षा ये सारे मामले और जिस खूनी झड़प का जिक्र भारद्वाज जी कर रहे थे, उस पर चर्चा होनी ही चाहिए ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी---

13.03.2015/1250/sls-jt-1

प्रो० प्रेम कुमार धूमल...क्रमागत

क्योंकि अगले दिन की अख़बार में छपा कि आसमान से बरसे फाहे, पहाड़ी से पत्थर, सड़क पर लात, घूंसे और लाठियां। मुद्दों को टालकर हम बच नहीं सकते। मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। 14वें वित्तायोग से प्रदेश को जो अच्छे पैसे मिले हैं, उसके लिए हम भारत सरकार के धन्यवादी हैं । लेकिन कल कहा गया कि मैंने कहा कि जो यह पैसे मिले हैं, यह मेरे कारण मिले हैं। मैंने तो कभी ऐसा क्लेम नहीं किया। मैंने प्रदेश सरकार को बधाई दी और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। कई बार जानकारी नहीं होती और सदस्य टिप्पणी कर देते हैं। मैं बुरा भी नहीं मानता।14 वें वित्तायोग की घटना एक महत्वपूर्ण घटना है, जब बजट आएगा तब उस पर चर्चा करेंगे। आप तो उस पर चर्चा करेंगे ही? जो पैसा मिल रहा है वह प्रदेश को 5 वर्षों में लगभग 75,000 करोड़ रुपया मिलेगा। उसी भाषण में कहा जा रहा था कि आपके अनुभव और योग्यता के कारण केस बहुत अच्छे ढंग से रखा गया ,इसलिए यह फल मिल रहा है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि बजट में जो कट लग गया वह धूमल के कारण लग गया। क्या यह सही है? यह आपकी योग्यता नहीं है? माननीय फाइनैंस कमीशन की रिपोर्ट हमने पढ़ी है। उसमें फार्मूला दिया हुआ है कि हर स्टेट का क्षेत्रफल क्या है ,उसकी आबादी क्या है ,वहां की वन संपदा क्या है? कई लोग कहते हैं कि हिमाचल को ग्रीन बोनस नहीं मिला।½7 % का वेटेज इस करके मिला है कि यहां पर वन संपदा ज्यादा है। दूसरी बात बता दूं कि योग्यता आपकी नहीं ,यह फ़िराकदिली श्रीमान नरेन्द्र भाई मोदी की है।13 वें वित्तायोग के बाद भी ...(व्यवधान) ...सुन लो, सुन लो।13 वें वित्तायोग में भी टैक्स का 39½% शेयर स्टेट

को देने की सिफ़ारिश थी। तब जिसका ख्वाब श्रीमान कौल सिंह जी देख रह थे , सोच रहे थे कि यू० पी० ए० सरकार आएगी तो कर देंगे ,उस सरकार ने13 वें वित्तायोग की 39½% की सिफारिश को केवल 1% माना था। मात्र 31% से 32% शेयर स्टेट्स का हुआ था। जो करंट ईयर चल रहा है, अपने फाईनैंस सैक्रेटरी से पूछ लेना ,इसमें स्टेट को जो शेयर मिलता है वह 32% है। मैंने इसीलिए नरेन्द्र भाई मोदी को और भारत सरकार को धन्यवाद दिया कि इस फाईनैंस कमीशन ने कहा

13.03.2015/1250/sls-jt-2

कि स्टेट को 42% शेयर मिलना चाहिए। जे० एन० यू० के एक प्रोफ़ेसर हैं जिन्होंने कहा था कि पहले ही साल 42% मत करो ,पहले 38% करो। लेकिन प्राईम मीनिस्टर ने कहा कि मैं मुख्य मंत्री रहा हूं और स्टेट्स की डिफीकल्टीज होती हैं। इसलिए जो मैजोरिटी रिकमँडेशन्ज हैं, उनको मानते हैं। तभी42 % का 42% ही दिया जा रहा है। इसका श्रेय श्री नरेन्द्र मोदी जी को न दें तो किसको दें? ...(व्यवधान) ...

मुख्य मंत्री : हमने इसमें बहस की थी। अपना केस सही ढंग से रखा और हिमाचल प्रदेश को, भारत के जितने भी राज्य हैं, मणिपुर, यहां तक की त्रिपुरा, उनसे भी कम एलोकेशन मिला है ,न कि यह आपकी उपलब्धि है।... (व्यवधान)...

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : क्योंकि यू० पी० ए० की सरकार थी और आपकी निक्कमी, नालायक सरकार थी ,इसलिए कम मिला था।... (व्यवधान)...

मुख्य मंत्री : हमारें वक्त में 14वें वित्तायोग में केस हमने रखा और उसी वजह से आज अच्छा devolution हो पाया है। इसका श्रेय आपको नहीं जाता।... (व्यवधान)...

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : बैठिए, बैठिए। अभी मैं खत्म कर रहा हूं।... (व्यवधान)...

Chief Minister: Who are you (Dr. Rajeev Bindal) to say that? I can intervene any time.

Prof. Prem Kumar Dhumal: You cannot intervene any time.

मुख्य मंत्री : यह बहुत ही गलत बातें हमने सुनी। आज जो यह गलत बात कर रहे हैं , फैक्ट्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं ,I must correct him on spot.

अगले वक्ता ..गर्ग जी के पास

13/03/2015/1255/RG/AG/1

मुख्य मंत्री की अंग्रेजी के पश्चात---- क्रमागत

Prof. Prem Kumar Dhumal: You cannot. आपकी यू.पी.ए. सरकार ने जो बेइन्साफी की, मैं कहना चाहूंगा कि हमें पांच सालों में रैवेन्यू डैफिसिट के अंगेन्स्ट 7,889करोड़ मिला और आपको एक ही वर्ष में मिल रहा है 8,009 करोड़ रुपये, जो पूरे पांच वर्षों से ज्यादा है। यह श्री नरेन्द्र भाई मोदी की एन.डी.ए. सरकार के कारण मिल रहा है। आप इतने लायक थे, तो जब 9वां वित्तायोग आया था, उसमें एन.के.पी. साल्वे चेयरमैन थे ,आपके साथ झगड़ गए जिसके कारण सारे डैफिसिट की समस्या उत्पन्न हुई। वह आपके कारण हुई थी और आपने उस समय जो नालायकी की थी, उसको आज सारे प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है।

सभापति(श्रीमती आशा कुमारी) : माननीय सदस्य, कृपया आप वाइन्ड अप करें।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : हां, सभापति महोदया, मैं समाप्त करता हूं। सभापति महोदया, जब कुछ उपलब्ध हो जाता है ,तो हर कोई उसका श्रेय लेना चाहता है , लेकिन अगर यह 42 प्रतिशत प्रदेश का शेयर नहीं होता 32 ,प्रतिशत ही रहता और एक प्रतिशत बढ़ाकर इसको 33 प्रतिशत ही करते और इसमें 35 प्रतिशत की कैप लग जाती ,जो सब स्टेट्ज के लिए सेलरी और पेन्शन पर लगी थी, तो आपका हाल भी वही होता जो पहले पांच सालों में हुआ है। उसके बावजूद हमने फाइनैन्स को बैटर अण्डरस्टैण्ड किया और बैटर रिजल्ट्ज दिखाए।

सभापति महोदया, मैं इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का तो समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन राज्यपाल महोदय को इसके लिए धन्यवाद जरूर देता हूं कि जो फिजूल की बातें लिखी थीं जो उपलब्धियां थीं ही नहीं ,उनको नहीं पढ़ा ,उन्होंने शॉर्ट भाषण किया, इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।

समाप्त

सभापति : धन्यवाद, धूमल जी। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

13/03/2015/1255/RG/AG/2

मुख्य मंत्री : सभापति महोदया, मुझे भी इस सदन में पक्ष या विपक्ष में बैठते हुए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण चल रही चर्चा को कई बार सुनने का मौका मिला है। जो मुख्य मंत्री की स्पीच होती है या विपक्ष के नेता की स्पीच होती है ,उसको भी सुनने या पढ़ने का मौका मिला है और मैं समझता हूं कि आज का प्रेम कुमार धूमल जी का जो भाषण था ,लगता है कि इनका मन कहीं और स्थान पर था और इन्होंने महज़ एक रस्म की अदायगी की। कई फैक्ट्ज जो इन्होंने बताए हैं वे बिल्कुल तथ्यों के विपरीत हैं।

श्री रविन्द्र सिंह : आपने मैनीफैस्टो में कहा है।

मुख्य मंत्री : हम बताएंगे ,मैनीफैस्टो की बात अलग है। मैनीफैस्टो पांच साल में पूरा करना है ,that is there. कुछ पहली साल में होगा, कुछ दूसरी साल में होगा ,कुछ तीसरी साल या चौथी साल में होगा और कुछ पांचवें साल में पूरा होगा। आपने तो अपना मैनीफैस्टो पांच साल में पूरा नहीं किया और हमारे पास तो समय है।

सभापति महोदया, मैं कह रहा था कि आज इनका मन कहीं और स्थान पर था। इनकी स्पीच में जो तथ्य होते हैं और जो ये गंभीरता के साथ बात करते हैं ,आज वह गंभीरता आपमें नहीं पाई गई है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : सभापति महोदया, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवादी हूं कि ये मान रहे हैं कि मैं गंभीरता से बात करता हूं और तथ्य देता हूं। आज मेरी गलती यह हो गई कि मैंने तथ्य तीखे और सच्चे दे दिए हैं इसलिए इनको बुरे लगे होंगे, लेकिन आप अपना चुनाव घोषणा-पत्र जाकर पढ़िएगा जरूर। मैंने यह नहीं कहा कि सैंट-परसेंट पूरे कर दिए, आपने कहा है कि अधिकांश हमने पूरे कर दिए हैं और अधिकांश में से ही मैंने कुछ चुनकर आपको बताए हैं। मेरा भाव यही है कि चर्चा हो , तो तथ्यों को सहने का भी हम दम रखें। इसलिए आगे से हिम्मत रखिएगा क्योंकि ऐसी हकीकतें अभी बाकी सदस्य भी बोलेंगे कि क्या-क्या सच्चाई है। अभी आपके सामने सारी सच्चाई आएगी। धन्यवाद, सभापति महोदया।

मुख्य मंत्री : जब गुरू ने ऐसा कहा है, तो चेले क्या करेंगे?

समाप्त

13/03/2015/1255/RG/AG/3

सभापति : अब इस माननीय सदन की बैठक अपराह्न 2. 00बजे तक भोजन के अवकाश के लिए स्थगित की जाती है।

13/3/2015/1400/MS/JT/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त श्रीमती आशा कुमारी ,सभापति की अध्यक्षता में 2.00 बजे अपराह्न पुनः आरंभ हुई)

सभापति :अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। पक्ष और विपक्ष की सहमति से दो माननीय सदस्य विपक्ष की ओर से तथा तीन माननीय सदस्य आज पक्ष की ओर से इस चर्चा में हिस्सा लेंगे।

सबसे पहले माननीय परिवहन मंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे। सभी माननीय सदस्यगण समय का ध्यान रखेंगे। प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने के लिए 10-10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। परिवहन मंत्री जी आपको 15 मिनट का समय बोलने के लिए निर्धारित है।

परिवहन मंत्रीः धन्यवाद सभापति महोदया।

It is an honour and privilege to get an opportunity to express my views on the Address given by His Excellency the Governor of Himachal Pradesh. माननीय सभापति महोदया मैं ब्रीफ और इशू के ऊपर ही बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे गर्व है कि हमारी इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ,it has a history of over 100 years and Congress Government led by our Chief Minister, Shri Virbhadra Singh believes in all round development. हम लोग सैक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं और जाति और रंगभेद के बिना प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास करने में विश्वास रखते हैं। उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसके महत्व को देखते हुए, जहां भी यह दौरे पर जाते हैं ,वहां आम नागरिक, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, प्रधान ,जिला परिषद के लोग, समितियों के लोग, विधायक साहिबान और जनरल पब्लिक के लोग जब इनसे मिलते हैं और अपने-अपने क्षेत्र की बात कहते हैं तो वहां प्राइमरी एजुकेशन और ऐलिमेंट्री एजुकेशन के लिए स्कूल आदि खोले भी जाते हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

13.03.2015/1405/जेके/जेटी/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः-------**जारी**-----

इन्स्टिच्युशन्ज जो है वह खोले भी जाते हैं और उनका संचालन भी किया जाता है। खोले जाएंगे तो माननीय सभापति जी उसमें बच्चे भी आएंगे और अध्यापक भी लगाएं जाएंगे। अगर इन्स्टिच्युशन्ज खुले ही नहीं तो न अध्यापक होंगे और न ही बच्चे होंगे।

जैसे कि हमारे विपक्ष के नेता कह रहे थे कि इनके चुनाव क्षेत्र में एक स्कूल है उसमें 17 बच्चे और 7 टीचर्ज हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी एक इंटीरियर इलाका था उसका नाम सरूट है। एक तरफ वह केरवा से मिलता है और दूसरी तरफ बड़ोह में आना पड़ता है। पहले वहां के लिए रास्ता नहीं था। जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा कि स्कूल मिडल कर दो। मैंने कहा कि बच्चे कितने है। उन्होंने कहा पांच बच्चे हैं। मैंने उनसे कहा कि पांच बच्चो की वजह से यह स्कूल मिडल कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि बच्चों ने पढ़ाई करना बन्द कर दी और लोग यहां से माईग्रेट हो गए। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से गुजारिश की और इन्होंने स्कूल को मिडल किया। अब वहां पर 40 बच्चे हो गए हैं। क्योंकि जो लोग वहां से माईग्रेट कर गए थे वे वापिस आ गए। कई जगह यह समस्या है। मगर यह बहुत अच्छी सुजैशन माननीय धूमल साहब द्वारा रैशनेलाईजेशन की दी गई है। वह आवश्यकता है। उसका सरकार को भी पता है। हम उसकी रैशनेलाईजेशन कर रहे हैं। जब रैशनेलाईजेशन होती है, माननीय मुख्य मंत्री जी करना भी चाहते हैं और फिर हम विधायक लोग इनके पास पहुंच जाते हैं कि इसको रोको। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि एम.एल.ए और आम लोग भी बोलते हैं कि इस स्कूल को यहीं पर रहने दो। पहले हमें अपने ऊपर अंकुश लगाना पड़ेगा। हमें यह सोचना पड़ेगा कि जहां पर जरूरत है वहां इसको जाने दें और इस पर यह कहना कि नये स्कूल खोलना अनुचित है। वह बात तो ठीक नहीं है। हमें स्कूल भी खोलने पड़ेंगे और इन्स्टिच्युशन्ज भी खोलने पड़ेंगे। शिक्षा में हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये सारी बातें सरकार के ज़हन में है और सरकार इन कामों को कर भी रही है। सरकार इसमें लगातार प्रयास कर रही है। इसका जो प्रमाण है वह लगातार किसी भी सेक्टर में, चाहे एजुकेशन, हैल्थ, परिवहन तथा अन्य कोई भी है उसमें हिमाचल किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। आपके समय में भी

13.03.2015/1405/जेके/जेटी/ 2

हिमाचल नम्बर-1, पर था और हमारे समय में भी हिमाचल नम्बर-1 है। माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी 6 बार मुख्य मंत्री बन चुके हैं। कितने सालों से कांग्रेस सरकारें यहां पर काम कर रही है। आज हिमाचल का इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्वरूप जो आप देख रहे हैं उसका श्रेय कम से कम आप कांग्रेस सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी को दीजिए। हमने कहा कि जो लगातार विकास हो रहा है उसमें आपकी भी भागीदारी रही है। आपकी भी दो बार सरकार रही है। एक बार शांता कुमार के समय में आधे

समय तक ही रही है। यह जो लगातार विकास का प्रोसैस है उसमें हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है। कठिनाइयां होते हुए भी हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है। भौगोलिक परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी आगे बढ़ा है। यह कहना उचित नहीं होगा कि इसे एकदम से रोक देना चाहिए। मगर रैशनेलाईजेशन के ऊपर हम लोग गम्भीर है। उसके ऊपर पूरा काम करेंगे। माननीय सभापति महोदया ,यहां पर मुझे खुशी है कि महामहिम् राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भूरि-भूरि प्रशंसा की कि इस सरकार ने क्या-क्या किया है? सरकार ने वही किया जो उसमें लिखा हुआ था। काम किये और इन दो वर्षों में बहुत ज्यादा काम हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो पुल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, इन्स्टिच्युशन्ज बनाए हैं, सड़कें बनाई है उनके ऊपर कांग्रेस का रंग चढ़ा है और चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस नज़र आती है दूसरा कुछ भी नज़र नहीं आता। कृपा करके जो हमने किया है उसके लिए आप लोगों को भी बोलना चाहिए कि यह काम कांग्रेस ने किया है। जहां पर कमी है वहां पर बताएं कि यहां पर यह कमी है। उसमें हम सुधार करेंगे और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

13.03.2015/1410/SS-JT/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री क्रमागतः

माननीय सभापति महोदय, एक बात बताईये, आपने (विपक्ष) हमारा मैनिफैस्टो पढ़ा। मैं कंवीनर हूं, लिखने वाला। इन्होंने पढ़ा हुआ है। इन्होंने उसके ऊपर हर चीज़ में एडवाइज़ किया है। हमारे सीनियर नेता हैं इन्होंने एडवाइज़ किया और हमने लिखा। मगर आप एक बात बताईये कि क्या मैनिफैस्टो दो साल के लिए है? मैनिफैस्टो पांच साल के लिए है। दो साल तो हम उन्हीं को रेगुलराइज़ कर रहे हैं जो आप लोग भर्ती करके गए हैं। हम उन्हीं को ठीक कर रहे हैं। आपने कहा कि कहां से खोलेंगे। मैं भी पिछले पांच साल यहीं था, हम वहां (विपक्ष में) बैठते थे। हम भी सुनते रहे। --(व्यवधान)-- पता नहीं अगली बार किसने इस दुनिया में होना है या नहीं होना है। So, let us talk about today. माननीय सभापति महोदया, उस वक्त एक बात आती थी। चार मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में, सोलन में या फलांने में खोलेंगे। वे कहां लगे? कहां गए वे कॉलेज? ऊना के कॉलेज का इंटैंड हुआ। हमीरपुर

में कॉलेज कहां लगे? Where are those colleges? मैनिफैस्टो में लिखते हैं। इंटैंशन होती है कि ये काम हमने करना है। उसके लिए समय होता है। समय के बीच में करेंगे। आज मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी को मुबारकवाद देनी है कि आज चम्बा में मेडिकल कॉलेज आ रहा है। उसके लिए 190 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आज हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज आ रहा है उसके लिए 190 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आज सिरमौर में मेडिकल कॉलेज आ रहा है उसके लिए 190 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। --(व्यवधान)--ये हवा में नहीं हैं। ये आपके सामने आयेंगे और वहां इलाज किया जायेगा। आपको बताएं कि ये यू0पी0ए0 सरकार की देन है। ऐम्ज़ खोलने की बात आई तो हमने दरियादली से कहा कि ऐम्ज़ बिलासपुर में खुलेगा। अब चहुंमुखी विकास हो रहा है। विकास उस कोने से शुरू हुआ और वहां तक चला गया। आई0आई0एम0 की बात हुई तो आई0आई0एम0 ने कहा कि सिरमौर में खुलेगा। मैं और माननीय मुख्य मंत्री इकट्ठे हैलीकॉप्टर में थे। अभी हम आए ही थे और पता लगा था तो हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा कि ऐसे एरिया में खोलिये जहां पर हम लोग थोड़ा कमजोर हैं। --(व्यवधान)-- हम ज्यादा इकट्ठे हैं आप अपनी तसल्ली करो। हम बिल्कुल इकट्ठे हैं। माननीय सभापति महोदय, आई0आई0एम0, तीन-तीन मेडिकल कॉलेज और वे भी अलग-अलग इलाकों में, क्या ये डिवैल्पमैंट का प्रतीक नहीं हैं। क्या यह डिवैल्पमैंट नज़र नहीं आ

13.03.2015/1410/SS-JT/2

रही। इस पर काम होगा क्या वह नज़र नहीं आयेगा? माननीय सभापति जी, मुझे इस माननीय सदन को बताते हुए प्रसन्नता है और मैं इस सदन को इंफोर्म करना चाहता हूं कि पिछले कल ही हमने आई0आई0एम0 की इंस्पैक्शन करवा दी। साइट सिलैक्ट करवा दी। कल ही कमेटी आई थी और मैंने डिपार्टमैंट को आदेश दिए कि एंश्योर करें कि हम जुलाई में फर्स्ट सैशन सिरमौर में शुरू कर देंगे। इस चीज़ का पूरा प्रयास किया जायेगा। यह सरकार काम करने में विश्वास करती है। इंजीनियरिंग कॉलेज सुन्दरनगर में है, शिमला में है, नगरोटा में है। नगरोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है क्लासिज़ बिठा दीं। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे मैं इस हाउस को एंश्योर करूंगा कि हम उसका फाउंडेशन स्टोन इसी वर्ष के अंदर करवा कर के उसका काम चालू करवायेंगे। ये मैं इस सदन को एंश्योर करता हूं। माननीय सभापति महोदया, दिल्ली में कई बैठकें हो गईं। --(व्यवधान)--वह आपकी मर्जी है। यहां भी कई बार आप झुरलू चलाने की कोशिश करते हो। माननीय सभापति

महोदया, यहां पर जो बात डिवैल्पमैंट की बात चली थी, विकास की जब गाथा लिखी जायेगी तो माननीय मुख्य मंत्री जी का नाम उसमें सबसे ऊपर लिखा जायेगा। काम किया है। अभी टांडा में सुपर स्पैशिलिटी हॉस्पिटल बन गया।

जारी श्रीमती के0एस0

/1415/13.03.2015केएस/एजी/1

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जारी----

टांडा में सुपरस्पैशियलिटी हॉस्पिटल बन गया। अब यह फैडरल सिस्टम है । इसमें प्रदेश में कभी कोई सरकार होगी, कभी कोई सरकार होगी। आप दोष हमारे ऊपर मढ़ते हैं और जो अच्छा काम है वह आप कहते हैं कि आपने किया। जो अच्छा काम आपने किया उसको हम मानेंगें कि आपने किया मगर जो इस सरकार ने अच्छे काम किए हैं उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। अभी बीच में लॉ एण्ड ऑर्डर की बात की गई। मुझे याद है कई बार लॉ एण्ड ऑर्डर में ऐसा समय आ जाता है, एक बार की बात है, हम लोग विपक्ष में बैठते थे ---घण्टी--- 1999-2000 में एक ही थाने के अन्तर्गत दो एस.सी .बहनों के मर्डर हो गए। उस वक्त हम वह मुद्दा बड़े जोर-शोर से उठाते थे क्योंकि यह पब्लिक प्रतिनिधि का काम है कि ऐसे मुद्दों को पूरी ताकत के साथ उठाएं और उसको हल करना उस वक्त की सरकार का काम है । सभी सरकारों का प्रयास होता है कि हम अपने अधिकारियों को डिस्क्रैडिट नहीं कर सकते। अधिकारी अपना काम करते हैं ।

माननीय सभापति महोदया, धूमल साहब ने कई इश्यू उठाए। उसमें एक जो इन्होंने सबसे बड़ा इश्यू उठाया, इन्होंने कहा कि ड्रग्ज़ के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। यह सरकार इसके लिए बड़ी सैंसिटिव है। हमने ट्रांसपोर्ट महकमे से एक बड़ी मुहिम चलाई है, आपने देखा होगा कि हर जगह होर्डिंग्ज़ लगे हैं। हमें पता है कि यह कितना घातक मामला है और इससे इस समाज को कितना नुक्सान हो सकता है। माननीय मुख्य

/1415/13.03.2015केएस/एजी/2

मंत्री जी से इस बारे में कई बार चर्चा होती है और ये एक बार नहीं अनेकों बार कहते हैं कि इसको रोकना है, इसके ऊपर काम करना है और हम काम कर रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में वर्कशॉप लग रही है, लगातार काम हो रहा है। दूसरी बात इन्होंने कंडक्टर की भर्ती की की। मैं कल भी इस बारे में बात कर रहा था और मैं सभी सदस्यों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि यह कंडक्टर की भर्ती नहीं है। यह ट्रेनिंग है और जिन्होंने ट्रेनिंग के लाईसैंस बनाए हैं, वह सिर्फ फर्स्टएड का लाईसैंस होता है मगर यह जो ट्रेनिंग है, यह कैसे बिहेवियर करना है, मोटरव्हीकल एक्ट क्या है आदि के बारे में पूरी ट्रेनिंग है । यह तीन महीने की सिर्फ ट्रेनिंग है और ट्रेंड हो कर वह कहीं पर प्राईवेट नौकरी ले सकता है, कहीं भी जा सकता है।

सभापति महोदया, श्री महेन्द्र सिंह जी को गलत आंकड़े पेश करने की आदत है । क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूं, ये भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, मैंने एक बार भी इनसे सवाल नहीं किया था मगर महकमें की वर्किंग इनको भी पता है । इन्होंने कैसे लोग रखे, इनको पता है । इनके समय में टैस्टों में इंटरव्यू हुए ही नहीं थे मगर मैं इन बातों पर नहीं जाना चाहता। जो आपने कहा यह मामला सबज्यूडिस है । माननीय अध्यक्ष महोदय, बसें चलानी है तो स्टाफ रखना पड़ेगा और जो काम माननीय प्रधान मंत्री जी के आशीर्वाद से होगा, आपकी मदद की भी कई जगह पर जरूरत पड़ेगी, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा मगर जो आज 1300 बसें आई हैं, सिर्फ हिमाचल में ही नहीं पूरे नॉर्दन इंडिया में लोग कह रहे हैं कि हिमाचल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज नम्बर-1 है। आज एक्सीडैंट रेट

/1415/13.03.2015केएस/एजी/3

बिल्कुल कम हुआ है । आज चारों तरफ 1300 नई बसें चल रही है और अगले तीन महीने में जीरो वैल्यू की कोई बस नहीं रहेगी, हम सारी नई बसें डाल देंगें। एक्सीडैंट रेट कम हुआ है, के.एम.पी.एल. बढ़ी है और हमने 25 से 40 प्रतिशत तक किराये कम किए हैं। हमने प्रयास किया है।

श्री प्रेम कुमार धूमलः बाली जी, यह तो दिल्ली वाली स्कीम है, ये बसें वहां से आई है।

मंत्री जी, अ0व0 द्वारा जारी---

13.3.2015/1420/jt/av/1

परिवहन मंत्री ----------**जारी**

वहां से आई हैं। हम तो धन्यवाद कर रहे हैं। यहां जे.एन.एन.यु.आर.एम. के तहत बसें आई। मैं कर रहा हूं, मुझे धन्यवाद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी धन्यवाद करेंगे अगर आप कुछ और दिलायेंगे।

सभापति जी, पी.डी.एस. के ऊपर माननीय धूमल जी ने कहा। Sir, I want to inform you. We have already notified the Vigilance Committees. निचले लैवल से मतलब एस.डी.एम. लैवल से लेकर स्टेट तक हमने विजिलैंस कमेटी बना दी है और इसकी नोटिफिकेशन आज या अगले कल हो जायेगी। मैंने इसकी फाइल पिछले कल ही साइन की थी। (---धन्यवाद---) बैठे, बैठे बोलने की बात नहीं है, आप (श्री रिखी राम कौंडल को कहा।) लिखकर दो। हम अभी चैक कराते हैं। जो भी होगा उसका चालान करेंगे, उसके अगेंस्ट ऐक्शन लेंगे। यह सरकार पूरी पार्दर्शिता में विश्वास करती है। अभी एक बात और कही गई कि हमने ऐक्साइज पॉलिसी में परिवर्तन कर दिया। पिछले हफ्ते हमने धर्मशाला में फैसला लिया कि हम ऑक्शन करेंगे। बाद में हमने यहां आकर फैसला ले लिया कि हम इन्हीं को रिपीट करेंगे। धर्मशाला में सोच-समझकर फैसला लिया था कि हम इसको ऑक्शन करेंगे। मगर सरकार के पास लोग आए, मिले। अपनी रिप्रैंजेंटेशन्ज दीं। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी-जल्दी ट्रांजिट करना मुश्किल होगा। जैसे कि आप अब देख रहे हैं कि हमने जो अटैम्प्ट किया नाकों को देने का ,मगर नाकों में बोली नहीं आई। अब बताओ, वह तो डिपार्टमैंट ने चला लिए मगर डिपार्टमैंट ये सारे ठेके कहां से चला पाता। आपकी सरकार के समय भी ऐसे कई फैसले हुए हैं जो आपने एक केबिनैट में लिए और अगले दिन/अगली केबिनैट में बदल दिए। सरकार को कई बार फैसले बदलने भी पड़ते हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी और यह कहना कि यह गलत हो गया; ठीक बात नहीं है।

नेचुरल केलेमिटी में; जहां बर्फ पड़ गई, वहां बर्फ पड़ने की वजह से तारें टूटी हैं। (---घंटी---)उनको रैस्टोर करने में थोड़ा समय लगता है। माननीय सभापति महोदया, मेरी बात थोड़ी बीच में ही रह गई है। मगर आप बार-बार घंटी बजा रही है

13.3.2015/1420/jt/av/2

तो मैं यह समझता हूं कि यहां पर इन्होंने वॉयलैंस की बात कही। Violence has no place in Dev Bhoomi. चाहे छोटी वॉयलैंस हो या बड़ी वॉयलैंस। मुझे भी कल बड़ी प्रसन्नता हुई जब प्रोफैसर साहब ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश की चिट्ठी पढ़ी। आपने बड़े मैच्योर तरीके से जो हुआ उसका बखान किया। यह भी कहा कि मुझे इस बात का दुख है और ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम सबको इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि भारद्वाज साहब के एक नजदीकी और हमारे एक साथी को चोट लगी। हम उसकी आंख को बचा नहीं पाये। झगड़ा नहीं होना चाहिए और चोट भी नहीं लगनी चाहिए। अब चोट लग गई है तो यह विषय जांच का था। मगर जांच में आप शामिल नहीं हुए। आप जांच में नहीं गए, आपने कहा कि हम मानते नहीं। अब यह आप डिसाईड करेंगे कि आपने क्या करना है मगर मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि उस व्यक्ति विशेष को जिसको चोट लगी है उसके लिए हम जो कर सकते हैं, करना चाहिए। मगर ऐसे मामले दोबारा न घटे उसके बारे में सोचना चाहिए,उसके बारे में विचार करना चाहिए और उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। यह बिल्कुल----

श्री बी.जे.द्वारा जारी

13.3.2015/1425/negi/ag/1

माननीय परिवहन मंत्री... जारी...

यह बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेन्ट इशु है । मगर उसके साथ-साथ day-to-day functioning of the Assembly, particularly, Question Hour is equally important.

मेरा सभापति जी आपसे भी अनुरोध है कि स्पीकर साहब और आप इस सदन को समूथ्ली चलाने का पूरा प्रयास करेंगे और इसके लिए मेरा नेता विपक्ष से भी रिक्वैस्ट रहेगी। समय-समय के ऊपर जनता हमसे पूछती है कि आप लोग गए थे, एक -डेढ़ महीना वहां लगा करके आये, क्या करके आए ? आज समय आ गया है हमारी एकॉउंटेबिलिटी का । हमने दो साल में क्या किया है, जहां यह सरकार से पूछेंगे वहां आपसे भी पूछेंगे कि आप पब्लिक की तरफ से गए थे, आपको सरकार की तरफ से जो जानकारी चाहिए थी वो क्या-क्या मिली? जहां तक डिवल्पमैन्ट का सवाल है। डिवल्पमैन्ट इस सरकार ने खूब की है और हम आगे 3 सालों में पूरी डिवल्पमैन्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

समाप्त

13.3.2015/1425/negi/ag/2

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी): धन्यवाद बाली जी, अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, डॉ0 राजीव बिन्दल जी हिस्सा लेंगे।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने हेतु आपने मुझे समय दिया, आपका आभार। बाली जी बात कह करके चले गए। मैं सोच रहा था कि अगर वह दो मिनट रूकते तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता ।

श्री सुरेश भारद्वाज़ : सभापति महोदया, संसदीय परम्परा के अन्दर जब पहला स्पीकर बोलता है तो उसको दूसरे स्पीकर को जरूर सुनना पड़ता है और यह संसदीय परम्परा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है।

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी): मैं माननीय सदस्य और मान्य सदन को यह बताना चाहती हूं कि बाली जी को फ्लॉइट पकड़नी है इसलिए वह सदन से स्पीकर की अनुमति से ही गए हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय सभापति महोदया, मैं अपने विषय पर आने से पहले एक चीज़ बाली जी की बात के साथ रहना चाहूंगा, कुछ बातें उन्होंने सच्ची कही। पहले यू.पी.ए. की सरकार दिल्ली में थी । माननीय मंत्री-गण, माननीय मुख्य मंत्री महोदय दिल्ली में जाते थे तो इनको एक-एक हफ्ता, 10-10 दिन मिलने का टाईम नहीं मिलता था। जब से मोदी जी की बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई है, मंत्री-गण धडाधड जा करके मंत्रियों को, प्रधान मंत्री जी को और फाइनैंस मिनिस्टर को मिलते हैं जिसके कारण प्रदेश को आज चाहे वो IIM हो, चाहे वो IIIMS हो और चाहे और संस्थान हो, धडाधड मिल रहे हैं। इसके लिए हम मोदी जी की सरकार का धन्यवाद करते हैं।

माननीय सभापति महोदया, महामहिम जी ने अभिभाषण थोड़ा सा पढ़ा और लिखित अभिभाषण हमें मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात इस अभिभाषण में प्रारम्भ में लिखी है कि हमारा चुनावी घोषणा-पत्र को हमने लगभग-लगभग, पूरा का पूरा

13.3.2015/1425/negi/ag/3

वायदा पूरा कर दिया है । सभापति महोदया, सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने प्रदेश के बेरोज़गारों के साथ किया । प्रदेश के बेरोज़गार ने जिस समय वोट डाला उस समय यह विचार किया कि प्रो0 प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने बेहतरीन योजनाएं चलाईं ,बहुत सारे काम किए परन्तु बेरोजगारी भत्ता नाम की एक चीज़ कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में लिखी है और उसमें एमाउन्ट लिखा है कि हर व्यक्ति को 1000 रूपये महीना मिलेगा। उसने सोचा, घर बैठे हुए 12 लाख लोगों को एक-एक हजार रूपये महीना मिलेगा, और उन्होंने टकाटक कांग्रेस के लिए वोट डाला। और जैसे ही कांग्रेस के लोग सत्ता में आए इन्होंने बेरोजगारों के साथ धोखा किया, आज 12 लाख बेरोजगार टकटकी लगा करके बैठा है । जिस दिन चुनाव होगा उस दिन वो 12 लाख बेरोजगार आपको बताएगा कि आपने चुनावी घोषणा-पत्र कैसे बनाया और उसमें किया गया वायदा कैसे पूरा किया? और कैसे आप महामहिम से असत्य बुलवाने का प्रयास कर रहे थे, जिसको महामहिम ने नहीं बोला, अपने मुखार्विन्द से नहीं बोला और अपनी वाणी को अपवित्र नहीं किया। आज मैं यहां इस सदन के अन्दर इसकी व्याख्यान करना चाहता हूं। जिस प्रकार से...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/1430/13.03.2015यूके/1

डा0 राजीव बिंदल --जारी---

जिस प्रकार से बेरोजगारों के साथ बेरोजगारी भत्ते के नाम पर धोखा हुआ वैसे ही कौशल विकास भत्ते के नाम पर धोखा हुआ । माननीय सभापति महोदया ,सिलाई सैंटर चले हैं, कहां-कहां से उठा कर के NGOs लाए हैं । एक NGO जिसके पास 10 सिलाई की मशीनें भी नहीं है, ऐसी NGO को 40-40 सिलाई केन्द्र दिए हैं, 20-20 लड़कियां उसमें पढ़ रही हैं । मैं आरोप लगा रहा हूं सदन के बीच में, मैने चिट्ठी लिखी माननीय मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, विधान सभा में प्रश्न भी किया और पिछली बार भी किया था । मैं यह आरोप लगा रहा हूं कि 500 रुपए लड़की को और 500 रुपए उस NGO को, हिसाब बना हुआ है कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है । नहीं तो आप बताएं कि कितनी लड़कियों ने ट्रेनिंग करके अपने बूटिक खोले, कितनी लड़कियों ने घर में जाकर सिलाई कढ़ाई की ? सिलाई-कढ़ाई के सैंटर हर पंचायत में चल रहे थे । आपने कौशल विकास भत्ता के नाम पर इस प्रकार से जनता के साथ धोखा किया है । भारी-भरकम भ्रष्टाचार हुआ है । मैं बेरोजगारों की बात कर रहा हूं । बेरोजगारों के साथ अगला धोखा सभापति महोदया, क्या किया ? आपने कहा कि 58 साल की जो रिटायरमैंट है उसके बाद हम रिटायरमैंट की उम्र को बढ़ाएंगे । एक दिन कहा कि रिटायरमैंट की उम्र बढ़ाएंगे, 59 साल करेंगे । दूसरे दिन कहा कि हम कुछ लोगों की बढ़ाएंगे कुछ की नहीं बढ़ाएंगे । तीसरे दिन कहा कि हम सब की बढ़ाएंगे । बाद में कहा कि हम किसी की नहीं बढ़ाएंगे । आपने मर्जी में आया तो किसी को ऐक्सटेंशन दे दी किसी को ऐक्सटेंशन नहीं दी । किसी को एक साल की ऐक्सटेंशन तो किसी को दो साल की ऐक्सटेंशन और किसी को ऐक्सटेंशन नहीं और वह बेरोजगार जो नौकरी की तलाश में बैठा हुआ था वह आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है । किस प्रकार से आपने धोखा किया । अखबार की रिपोर्ट है । आपके प्रश्न का उत्तर पिछले कल का, आपने 10 महीने में 478 युवाओं को नौकरी दी । यह हैड लाईन है । माननीय सभापति महोदय, किस प्रकार से बेरोजगारी को खत्म करने का वायदा करके सत्ता में आयी हुई सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया और रिटायर्ड लोगों के माध्यम से चलने वाली रिटार्यड और

टायर्ड सरकार ने किस प्रकार से बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, इसका आपको पता लगेगा। माननीय सभापति महोदया ,जहां स्कूलों की बात आई वहां पर।

मुख्य मंत्री : आप किस बात का जिक्र कर रहे हैं ? किस महकमें का जिक्र कर रहे हैं जहां ऐसी खबर आयी है कि 400 आदमियों की भर्ती हुई है ? पहले तो ये बताएं क्योंकि हमारी सरकार के समय में हजारों की तादाद में भर्तियां हुई हैं।

डा0 राजीव बिंदलः सर, बिल्कुल मैं इस बात को ऑथेंटिकेट करके यहां पर रख रहा हूं। प्रश्न का हवाला है और उस प्रश्न का उत्तर है।

मुख्य मंत्रीः नहीं, किसी महकमें की बात होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी सरकार ने 400 भर्तियां की हैं, हजारों की तादाद में भर्तियां हुई हैं।

सभापतिः (श्रीमती आशा कुमारी) माननीय सदस्य, आप इसको आँथेंटिकेट करके यहां ले कर दीजिए।

मुख्य मंत्री : आप उस अखबार का नाम बताइए वह कौन सा अखबार है ?

डा0 राजीव बिंदलः सर, "दैनिक भास्कर" और आज की डेट है और ऑथेंटिकेट करके रखूंगा।

माननीय सभापति महोदया ,SMC के माध्यम से भर्तियां हुई हैं, मैं आपके सामने यहां पर रख रहा हूं। एक लड़की एम0ए0, बी0ऐड, एम0फिल, 67% नम्बर उसको नौकरी नहीं और बी0ए0 को नौकरी। कोर्ट में केस डाल रहे हैं। दूसरा मामला बी0ए0 को नौकरी नहीं, बी0ए0 और बी0ऐड है, टैट है उसको नौकरी नहीं लेकिन नौकरी प्लस टू को नौकरी और किसके इन्स्टांस पर, हमारे यहां के प्रमुख कांग्रेस के ओहदेदारों के इन्स्टांस पर एस0एम0सी0 के अन्दर भर्तियां, बैक डोर ऐन्ट्री। युवाओं के साथ धोखा। माननीय सभापति महोदया, नर्सिंग की भर्ती।

/1430/13.03.2015यूके/एजी/3

मुख्य मंत्रीः एस0एम0सी0 के अन्दर जो भर्तियां होती हैं, it is as per the qualification prescribed for that job. और उसी की वजह से उनकी एम्पलायमैंट होती है । एम0ए0 पास रह जायेगा और 10वीं पास आ जायेगा, ऐसी बात नहीं है । Even SMC has been authorized to engage staff but the staff to be engaged should have the requisite education qualification for that.

डा0 राजीव बिंदलः माननीय मुख्य मंत्री जी, होना ऐसा ही चाहिए ।

मुख्य मंत्री : ऐसा ही हुआ है । आप गुमराह कर रहे हैं, हाऊस को ।

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी) :माननीय सदस्य, आपके पास अगर कोई इन्स्टांस हैं तो मुख्य मंत्री महोदय को लिखित में भेज दें ताकि उस पर इन्क्वायरी हो सके ।

डा0 राजीव बिंदलः सभापति महोदय, आपके आदेश का पालन करेंगे पर एक बार आप अपने चीफ सेक्रेटरी को पूछिए । मैने लैटर लिख कर के, उसकी कॉपी लगा करके ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी---

13.03.2015/1435/sls-ag-1

डॉ0 राजीव बिन्दल...क्रमागत

मैंने पत्र लिख कर और उसकी डिटेल्ज की कॉपी लगाकर उनको मेल किया है और उनका जवाब मेरे पास आया है कि मैं इसकी जांच करूंगा लेकिन आज तक इसकी जांच नहीं हुई। मैं यह कॉपी मुख्य मंत्री महोदय को भेजने वाला हूं; आज ही उसको आपके ऑफिस के अंदर भेजूंगा।...(व्यवधान)...चीफ सैक्रेटरी को चली गई है। Who is Chief Secretary? माननीय सभापति महोदय, नर्सिज की भर्ती की बात आई। मैं बेरोजगारों के साथ धोखे की बात कर रहा हूं। हम जब भर्तियां कर रहे थे, तो कहते थे कि RKS में भर्तियां हो रही हैं। RKS की लड़कियां 3 साल में रैगुलर हो रही थी।

आपने कोई कंपनी बुलाई। देश के किसी हिस्से से कंपनी बुलाकर उसके माध्यम से लड़कियों की भर्ती हो रही है। पहले कहा कि ऐक्सपीरियंस्ड लड़कियां लेंगे, अब जो लड़कियां आ रही हैं उनको ले रहे हैं। क्या कारण है कि आप आऊटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती कर रहे है, हिमाचल प्रदेश की प्रतिभा को डायरैक्टिली इस सरकार में क्यों नहीं ले रहे, कंट्रैक्ट पर क्यों नहीं ले रहे, RKS में क्यों नहीं ले रहे? RKS सेमि-गवर्नमैंट बॉडी है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप उनको प्राईवेट एजैंसी के माध्यम से ले रहे हैं?... (व्यवधान)...

सभापति : माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

डॉ० राजीव बिन्दल : बाद में दे देंगे। अभी बहुत सारी बातें आएंगी।

सभापति : आप मंत्री जी को बोलने दीजिए। आपकी बात भी सुनेंगे लेकिन आप एक मिनट के लिए उनकी बात भी शांति से सुन लीजिए।

मुख्य मंत्री : आपकी बात हम सुनते अगर उसके अंदर कोई तथ्य होता। You are speaking offline.

13.03.2015/1435/sls-ag-2

Prof. P.K. Dhumal : Point of order, madam.

सभापतिः धूमल साहब, आप बोलिए।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : सभापति महोदय, बड़ी विचित्र बात है। हम कह रहे हैं कि हम एलिगेशन लगा रहे हैं और अथैंटिकेट करके रिकॉर्ड पर रख रहे हैं। आपके मंत्री ने जो-जो बोला, क्या हम भी हर बात में बीच में इंट्रप्ट करते हैं? शराब के ठेकों के लिए क्या आपको पता नहीं था कि 31मार्च को पॉलिसी बनाकर उनकी ऑक्शन करनी है या नहीं करनी है? अचानक वह एक अर्गुमैंट यह देकर गए कि इतनी जल्दी ठेके

अरैंज नहीं होते। बॉर्डर पर जो आपके टौल टैक्स बैरियर हैं, क्या आपको पता नहीं है कि 31 मार्च को उनकी नीलामी होती है? Why not in time? इसलिए ऐलिगेशन्ज लगेंगे, आपका मंत्री जवाब दे। माननीय सदस्य अथैंटिकेट तक कर रहे हैं। इसलिए जितनी बार इंट्रप्ट हुआ है उतना समय इनके टाईम से न काटा जाए, उतना समय एक्स्ट्रा दिया जाए।

सभापति : स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

स्वास्थ्य मंत्री : माननीय सभापति महोदया, इन्होंने कहा कि किसी बाहर की कंपनी को ले आए हैं। इनको पता होना चाहिए, ये हैल्थ मीनिस्टर रहे हैं। HLL भारत सरकार की अंडरटेकिंग है। नेशनल हैल्थ मिशन के तहत वह स्टॉफ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए वह ऐसी भर्ती कर रहे हैं। लेकिन जब मुझे पता लगा कि उन्होंने ऑन लाईन ऐप्लिकेशन्ज मांगी और गांव की लड़कियां ऑन लाईन ऐप्लिकेशन नहीं दे सकती; सब लड़कियों को कार्ड नहीं गए, इसलिए मैंने इनको फिर कहा है कि आप 15-20 दिन के बाद दोबारा इंटरव्यू करें और जो लड़कियां इसमें शामिल नहीं हुई हैं, उनको भी शामिल करें और मैरिट पर लड़कियों को नियुक्त करें। RKS की आप बात करते हैं, RKS तो इन्होंने शुरू किया। जो लड़कियां RKS में थी वह 6 साल तक रहने के बाद पक्की होती थीं। इन्होंने डॉक्टर तक RKS के अंदर रखे और

13.03.2015/1435/sls-ag-3

उसमें डॉक्टर ज्वॉयन करते थे। हमने पहले दिन से सरकारी कंट्रैक्ट पर डॉक्टर रखे हैं। ये उनको 26,200 रुपये देते थे, हम 40,000 रुपये दे रहे हैं। जो इंटिरियर में डॉक्टर है, वह 55,000 रुपये ले रहा है।

डॉ० राजीव बिन्दल : माननीय सभापति महोदया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की जब जवाब देने की बारी आएगी, तब दें। HLL पूरी तरह से एक इंडिपैंडैंट आर्गनाईजेशन है। HLL से भर्ती करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? आप डायरैक्ट कंट्रैक्ट भर्ती कर लो। यह हमारा कहना है बाकी आपकी मरजी है। आपकी मैजोरिटी की सरकार है। हमको जो उचित लग रहा है, वह हम बता रहे हैं। आपको जो ठीक लगे, आप वह करें। आपने सारी-की-सारी लैबोरेट्रीज आऊटसोर्स कर दीं। अभी IGMC के अंदर

हंगामा हुआ। सरकारी लैबोरेट्री बंद कर दी और आऊटसोर्स लैबोरेट्री में सारे टैस्ट होते रहे। सभापति महोदय, मैं इस विषय पर नहीं जा रहा था। अभी माननीय बाली जी ने विषय शुरू किया था। स्वास्थ्य मंत्री जी के विषय को मैं छूना नहीं चाह रहा था।

जारी ..गर्ग जी

13/03/2015/1440/RG/JT/1

डॉ. राजीव बिन्दल------क्रमागत

मैं आपके विभाग को छूना नहीं चाह रहा था। सभापति महोदया, मैं इनको याद कराना चाहता हूं कि पिछली बार का जो अभिभाषण है और इस बार का जो अभिभाषण है, पिछली बार यह कहा गया कि एम.बी.बी.एस. की सीटें बढ़ा करके 200से 300 कर दीं, लेकिन इस बार के अभिभाषण में यह साफ हो गया कि वे 200 की 200 ही रहीं और 200 के लिए भी नाक रगड़नी पड़ी। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें वर्ष 1978 से लेकर 39 थीं, हमने बढ़ा करके उनको 149 किया और 149 सीटें 149 नहीं रहीं ,उसके अंदर भी चार सीटें आप, और अप्रूव कराने में फेल हुए। सीटें बढ़ाने की बात तो दूर रही। अख़बारों की रिपोर्टिंग और आपके प्रश्न का उत्तर है कि आप पूरी सीटें भी नहीं भर सके हैं।

सभापति महोदया, इन्होंने सुपर स्पेशलिटी की बात की। सुपर स्पेशलिटी का शिलान्यास आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने किया। श्री गुलाम नवी आजाद जी आए ,हमने यू.पी.ए. सरकार से पैसा लिया था इसमें कोई दो राय नहीं। उसका काम धूमल जी के समय में शुरू हुआ ,काम लगभग कम्पलीट हो गया था। अब काम पूरा हुआ ,लेकिन आपने उसके इनकम्पलीट काम का ही उद्घाटन कर दिया और एक भी सुपर स्पेशलिटी उसमें शुरू नहीं हुई है। क्योंकि आपके पास डी.एम. और एम.सी.एच. नहीं मिले, न वहां न्यूरो शुरू हुई है ,न वहां कैंसर की स्पेशलिटी शुरू हुई है और न ही वहां कार्डियक सर्जरी शुरू हुई है। केवल कहने के लिए वह सुपर स्पेशलिटी है और सुपर स्पेशलिटी विंग पूरी तरह से बन्द पड़ा है। सुपर स्पेशलिटी की सीटें शिमला में क्रियेट की थीं ,लेकिन उसके बाद एक भी सीट आप सुपर

स्पेशलिटी की नहीं बढ़ा पाए।----(घण्टी--(मैं इसकी चर्चा में नहीं जाना चाहता था। आपने कहा कि तीन मैडिकल कॉलेज यू.पी.ए. की सरकार ने दिए। आपके दो विरोधाभास मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपने समाचार-पत्र में स्टेटमैंट दी कि 'तीनों मैडीकल कॉलेज का पैसा जारी,' मैंने यहां प्रश्न पूछा ,तो उत्तर दिया गया कि एक भी पैसा अभी तक जारी नहीं हुआ। यह प्रश्न संख्या 1331, दिनांक 2014-12-6 को लगा था। मैंने मीडिया में भी कहा कि यू.पी.ए. सरकार ने जाते-जाते घोषणा की , चुनावों को प्रभावित करने के लिए तीनों मैडिकल कॉलेज की घोषणा की ,लेकिन एक भी पैसा जारी नहीं हुआ। आज मैं सदन में कहना चाहता हूं कि आज तक भी इसका एक भी पैसा जारी नहीं हुआ है और यह सदन को गुमराह करने का प्रयास है।

13/03/2015/1440/RG/JT/2

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी कहना है कि पैसा जारी न होने का कारण है कि वर्तमान सरकार ने अभी तक केन्द्र सरकार को पूरे कागज़ात उपलब्ध नहीं कराए हैं। मैं नाहन मैडिकल कॉलेज के बारे में कहना चाहूंगा कि मैडिकल कॉलेज के लिए भूमि देने की बात आई। पहले आपने एक दूसरी जगह चयनित की ,उसके बाद हास्पिटल की भूमि जो टुकड़ों में बंटी है और उसके ऊपर निजी लोगों के कब्जे हुए हैं ,कुछ मकान बने हुए हैं। अरे! मैडिकल कॉलेज बनाना है, इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वहां और भी जमीनें हैं, कोई अच्छी सी जमीन दे दो ,वहां बहुत अच्छा मैडिकल कॉलेज बनेगा। हम आपका धन्यवाद करेंगे। आप आएं, उसका शिलान्यास करें ,केन्द्र से माननीय श्री नड्डा जी आएं, हम साथ रहेंगे और मिलकर काम करेंगे। इसलिए कोई अच्छी सी भूमि दे दो। उसका लाभ मिलेगा। वह भूमि जो हमारे सी.एम.ओ. साहब ने सलैक्ट की, जिनको आपने ऐक्सटैंशन पर रखा था ,उन्होंने गलत भूमि आपको ऐडवाइज की है। हाई कोर्ट ने उनको बाहर किया ,नहीं तो आप उनको दुबारा से ऐक्सटैंशन देने की तैयारी कर रहे थे।

माननीय सभापति महोदया, यह जो महामहिम का अभिभाषण है ,इसमें सड़कों की बहुत चर्चा है। क्या हालत है ठियोग और हाटकोटी की सड़क की। हमारे नेता हजारों की तादाद में पैदल चले, सैंकड़ों किलोमीटर चलकर उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन आज तक उसके ऊपर एक रोड़ी का ट्रक भी नहीं गिरा। यहां तक की उसमें पैदल चलना भी मुश्किल है। वहां सड़क की जो दुर्दशा है वह किसी से छिपी

नहीं है। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, अगर कोई अधिकारी नोट कर रहा हो क्योंकि यह विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के पास है। हमारा एन.एच.-72 ,काला अंब से चलिए और पांवटा तक जाइए ,तो कमर का बाजा बज जाता है ,वह नेशनल हाईवे-72 है। मैं इससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार की बात बताना चाहूंगा कि पिछले दो साल में चार बार उसकी रिपेयर के लिए तारकोल डली।--)घण्टी--(मैंने प्लानिंग की मीटिंग में माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था। जिस दिन तारकोल डली, उसके 15दिन के पश्चात वह तारकोल गड्ढो में तब्दील हो गई। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सचिव(लोक निर्माण(को वहीं पर आदेश दिया था, लेकिन आज तक न कोई जांच हुई और न ही कोई कार्रवाई उस पर की गई। वह कौन सा भ्रष्टाचार है उसके पीछे की कहानी मैं इस सदन में बताना चाहता हूं कि केवल कांग्रेसी ठेकेदारों को ठेके देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह

13/03/2015/1440/RG/JT/3

स्थिति है। अधिकारियों के गले के ऊपर कांग्रेसी नेता दबाव डालकर उनसे ठेके दिलवा रहे हैं और ठेके किस तरह से जा रहे हैं----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

13/3/2015/1445/MS/AG/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी------

अधिकारियों के गले के ऊपर कांग्रेसी नेता दबाव डालकर उनसे ठेके दिलवा रहे हैं और ठेके किस तरह से जा रहे हैं, उसकी स्थिति सारे विभागों से छिपी नहीं है। माननीय सभापति महोदया, सड़कों की हालत के संबंध में यहां चर्चा की गई। गांव की सड़कें हों, स्टेट हाइवे हों, उनकी हालत ठीक नहीं है।

कानून और व्यवस्था की चर्चा करने से पहले, यहां माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। आपने तो करिश्मा कर दिया। हमारे क्षेत्र के अन्दर सब सेंटर्ज हैं मीरपुर , कोटला ,कोलर ,धौलाकुंआ ,मोगीनंद ,सेनवाला ,कालाअम्ब, पी0एच0सी0 बनेठी ,

पी0एच0सी0 जमटा और पी0एच0सी0 कोलांवालाभूड़, इनके पैसे उठा दिए। इनके भवन निर्माण के लिए, ग्रामीण स्वास्थ्य के विकास के लिए पैसे दिए हुए थे लेकिन वह पैसे उठाकर दूसरे संस्थानों को दे दिए। मैं ढूंढता रहा कि पैसे कहां गए और जब मैंने चिट्ठी लिखी तो मुझे सी0एम0ओ0 साहब की चिट्ठी आई कि हमने वह पैसा बदल दिया है। मैंने पूछा कि क्यों बदल दिया, तो वह बोले की वहां पर जरूरत नहीं है या वहां पर जमीन नहीं मिली। यह ग्रामीण विकास की बात है। (व्यवधान) तो इस प्रकार की स्थिति है। क्या खजाने में पैसे की कमी थी? NRHM का पैसा आपके पास पड़ा था, पैसा लोक निर्माण विभाग के पास पड़ा था लेकिन उन्होंने काम आगे बन्द कर दिया और हम आगे बढ़ने से रूक गए।

यहां पर कानून-व्यवस्था की बात बड़े अच्छे अंदाज में माननीय बाली जी ने कही। बोले हां, बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी। अरे, बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी, क्या इतना कहने से काम चल गया? अगर किसी गांव के अन्दर भी कोई छोटी सी घटना हो जाती है तो तुरन्त कार्रवाई होती है। अगर 24 घण्टे में कार्रवाई नहीं होती है आप लोग, हम लोग और पंचायत के प्रतिनिध भी थाने में जाते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। यहां तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना हुई। क्या आज तक कोई गिरफ्तारी हुई, क्या किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ या किसी के खिलाफ कोई संगीन आरोप दर्ज हुए? नहीं हुए। उसके बारे में सफाई देना कि आगे से कुछ नहीं होना चाहिए। अरे, आगे से कुछ नहीं होना चाहिए लेकिन जिसको सेक लगेगा,

13/3/2015/1445/MS/AG/2

जब कोई अंदर जाएगा तभी तो भविष्य में वह ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अब आपने खुला छोड़ दिया है कि आगे भी ऐसा ही करो, मजे करो, सब ठीक है। माननीय सभापति महोदया, मैं चन्द बातें आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा। अब मैं हैल्थ को किनारे रख देता हूं।

सभापति(श्रीमती आशा कुमारी): माननीय सदस्य कृपया समाप्त कीजिए। आपने दुगुना समय ले लिया है।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अब मैं महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आ रहा हूं। मैं यह चिट्ठी यहां ले (lay) कर रहा हूं और इसके साथ अखबारों की कटिंग भी है। डूंगी में खैर के पेड़ों के कटान के लिए विभाग द्वारा दो मृतकों के हल्फनामे दाखिल किए। मरे हुए लोगों के हल्फनामे दाखिल करके और यह इतना बड़ा डाटा रिकॉर्ड है(कागज दिखाते हुए) , यह प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी के नाम है और इन्होंने इन्हें मुझे भेजा है। मैं उस व्यक्ति से मिला। वह एक रिटायर्ड कैप्टन है। उस कैप्टन ने बहुत लड़ाई लड़ी और दुनियाभर के लोगों को पत्र भी लिखे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अवैध कटान के मामले जोरों पर हैं। बाली जी सदन से चले गए हैं, मैं उनकी बात बताना चाहता हूं। अभी कानून-व्यवस्था में क्या हो रहा है? पूरी सरकार केवल विरोधियों को सीधा करने में लगी है ताकि धूमल जी पर हररोज एक नया केस बन जाए। डॉ बिन्दल और रविन्द्र सिंह पर केस बना दो। इनके एक और मकान की इन्क्वायरी करवा दो। चार-चार बार इन्क्वायरी हो रही है। आज एक नया मामला आया कि वीरेन्द्र कश्यप पर भी केस बना दो। जब इनसे पूछते हैं कि ये मामले क्यों बना रहे हैं तो कहते हैं कि ये तो चार्जशीट में है। जब पूछा कि चार्जशीट किसने बनाई तो बोले कि मैंने नहीं बनाई, बाली ने बनाई और बाली जी ने क्या कहा, यह मैं बता रहा हूं। बाली जी बोलते हैं कि चार्जशीट में सुधीर और गंगू ने डाला मसाला। यानी हालत क्या है? मुख्य मंत्री विरोधियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि चार्जशीट किसने बनाई; बाली जी ने बनाई। बाली जी बोलते हैं कि मैंने नहीं बनाई बल्कि गंगू ने और सुधीर ने उसमें डाला मसाला। इन कागजों

13/3/2015/1445/MS/AG/3

को मैं यहां रख सकता हूं। (व्यवधान) यानी क्या स्थिति हो गई है कि पूरा पुलिस विभाग केवल और केवल एक काम पर लगा है।

सभापति महोदया, एक और जबरदस्त घटना आपके ध्यान में लाता हूं। इन लोगों को फट्टे लगाने और उद्घाटन/शिलान्यास करने का इतना फोबिया हो गया है कि कहीं प्रेम कुमार धूमल का एक फट्टा न लग जाए। अर्की विधान सभा क्षेत्र में सांसद महोदय ने पैसे दिए, वहां पर उद्घाटन होना था। तारीख निर्धारित हो गई थी

और फट्टा भी बन गया था लेकिन वहां पुलिस भेज दी गई। सैंकड़ों की संख्या में शिमला से पुलिस कर्मी वहां गए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

13.03.2015/1450/जेके/जेटी/1

डा0 राजीव बिन्दलः-----**जारी**----

सैंकड़ों की संख्या में शिमला से पुलिस कर्मी गए और उस सारी जगह को घेर लिया। वहां के एक पंचायत प्रधान को बुला करके उसका उद्घाटन करवा दिया। वे कह रहे थे कि अगले दिन धूमल जी ने आना है और किसी तरह से वहां पर फट्टा न लग जाए। खबर लगी कि पुलिस के पेहरे में हुआ सामुदायिक भवन का उद्घाटन। यह पुलिस का काम है। लॉ एण्ड ऑर्डर की हालत क्या है? यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मन्दिरों में चोरी की वारदातों ने बढ़ाई चोरी की परेशानी, गर्दन पर तलवार रख कर 3 लाख रूपये की लूट, दो घरों में सेंध मारी, 6 दुकानों के ताले टूटे ,नव-विहार कॉलोनी में दिन-दिहाड़े चोरी, महीनों में 24 चोरियों से सहमा पौंटा साहिब, लॉकर काट कर गहने लूटे। नाहन के रानीताल में लाखों की चोरी। चार महीने में 9 मन्दिरों में चोरी। आप कह रहे हैं कि मन्दिरों की सुरक्षा अब बहुत अच्छी हो गई है। धौलाकूआं में 3 महीने में आधा दर्जन डकैतियां। नाबालिक छात्रा से गैंग रेप। लाखों के गहने और 15 हजार की नगदी की चोरी। बीच सड़क में युवा का मर्डर। 29.45 लाख रूपये की लूट। अभी तो पिक्चर बाकी है। आज की खबर रेणूका की नाबालिग 30 हजार में बेची गई। मैं यहां पर प्रूफ के साथ कह रहा हूं। सिरमौर में अभी लड़कियों का बेचना जारी है। आप कह रहे हैं कि लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन इम्प्रूव कर दी गई है। हमने स्थिति को सुधारा है। माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं।

श्रीमती आशा कुमारी, सभापति : माननीय सदस्य, डॉ0 बिन्दल जी आप 15 मिनट ज्यादा बोल गए हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी रहूंगा। आप लोग कहते हैं कि हमने शिक्षा में विस्तार किया है। नाहन का डिग्री कॉलेज जो कि सबसे पुराना है, उसका भवन नहीं बना रहे हैं। माननीय धूमल जी ने वहां पर उसके लिए जमीन दी। उसके लिए 7 करोड़ रूपया दिया और उसके बाद शिलान्यास किया। सरकार बदल गई।

13.03.2015/1450/जेके/जेटी/2

उसके टेण्डर हो गए। ठेकेदार की गर्दन पर ऊंगली रख कर बोला गया कि अभी काम नहीं शुरू करना है। परन्तु लिखित ऑर्डर नहीं किये। वहां से जमीन बदल दी। जमीन बदल कर शहर से तीन किलोमीटर बाहर चले गए। अभी पीछे मैं अखबार पढ़ रहा हा था कि कांगड़ा के किसी कॉलेज के उद्घाटन के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी गए और कहा कि किस पागल ने यह कॉलेज जंगल में बना दिया और यहां पर लड़कियां कैसे पढ़ने आएगी? मैं पढ़ रहा था कि वहां की लड़कियां जब जंगल में पढ़ने जा सकती है तो क्या नाहन की लड़कियां भी जंगल में पढ़ने जा सकती है? उनके लिए जंगल में जमीन ढूंढी जा रही है, जिसमें 500 पेड़ों का कत्लेआम किया जाएगा। पहले वाली जमीन नाकाबिल हो गई, क्योंकि धूमल जी ने उसका शिलान्यास किया है। अब इससे भी ज्यादा चिन्ता की बात यह है और मेरे प्रश्न का उत्तर भी दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम उस फाऊंड्री की जमीन को किसी प्राईवेट आदमी को मॉल और मार्किट बनाने के लिए दे रहे हैं, जिसके ऊपर डिग्री कॉलेज बनाने के लिए आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने शिलान्यास किया था। उस जमीन को प्राईवेट आदमी को मॉल बनाने के लिए दे रहे हैं। मैं इस सदन के अन्दर कहना चाहूंगा कि किसी भी प्राईवेट आदमी को वह कीमती जमीन हम देने नहीं देंगे। इस बात को नोटिस किया जाए। जो अर्बन डवैल्पमैंट मिनिस्टर हैं वे भी इस बात को नोट कर लें। वह लोक निर्माण विभाग की जमीन राजस्व विभाग को ट्रांसफर करके किसी व्यक्ति के साथ साठ-गांठ करके उसे देने का जो प्रयास चल रहा है उसको किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। यहां से बाली जी चले गए। मुझे लग रहा था कि यदि दो मिनट और रुकते तो कुछ लाभ हो जाता। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे-अच्छे काम ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं। बाई चांस मेरे हाथ में खबर है कि बस अड्डा पानी-पानी, बस अड्डे में दलदल। ये खबरें सब तरफ की हैं।

13.03.2015/1450/जेके/जेटी/3

माननीय सभापति जी आपने मुझे समय दिया और मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि झूठ का पुलिंदा महामहिम् से पढ़वाने का प्रयास करवाय गया। हम महामहिम् के धन्यवादी हैं। यह सरकार बदला-बदली और भ्रष्टाचार की पर्यायवाची बन गई है। जिसने सड़कों की दुर्दशा की चिन्ता करनी बन्द कर दी है। जिसने केवल स्कूलों में फट्टे और कॉलेजों में फट्टे लगाने का काम किया है। वहां पर न अध्यापक हैं और न ही प्रोफैसर्ज़ हैं ।

श्री एस.एस.द्वारा जारी------

13.03.2015/1455/SS-JT/1

डॉ राजीव बिंदल क्रमागतः

वहां पर न मास्टर हैं, न अध्यापक हैं, न प्रोफैसर हैं, ऐसे स्कूल हैं। डॉक्टरों की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैं उस पर कभी चर्चा मांगूगा। नियम-130 में चर्चा मांगूगा। उस समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से वार्ता करूंगा। पर मेरा इतना कहना है कि जो प्रयास पिछली सरकार ने शुरू किये थे वे सारे प्रयास धराशायी कर दिए हैं। केवल बदला-बदली और अत्याचार के लिए यह सरकार जानी जायेगी। वही इनका सिद्धांत है और उसी सिद्धांत को लेकर ये चले हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करते हुए इस अभिभाषण का मैं समर्थन करने में पूरी तरह से असमर्थ हूं, धन्यवाद, जयहिन्द।

समाप्त

13.03.2015/1455/SS-JT/2

सभापतिः धन्यवाद बिंदल जी। स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है लेकिन इन्होंने एक बात कही कि नाहन का जो मेडिकल कॉलेज है वह शहर से बाहर चार-पांच किलोमीटर जमीन मिल रही थी। मैंने व्यक्तिगत तौर पर देखा कि नाहन की जो म्यूनिसिपल कमेटी है वह जमीन है। उसका 18 करोड़ रुपया बनता है। सिर्फ 7करोड़ रुपया कमेटी वाले मांग रहे थे। साढ़े 11 करोड़ रुपया वन विभाग का है, जो फॉरैस्ट प्रोड्यूस होती है उसकी वैल्यू लग रही थी। जबकि हमारे नाहन के पास ही 20 एकड़ जमीन उपलब्ध है। यह ठीक है जैसे इन्होंने कहा कि किसी ने घर बना लिये हैं, वहां लोगों ने एंक्रोचमैंट की है। हमने कहा कि इसकी डिमार्केशन करें। दिल्ली से भारत सरकार की जो हैल्थ मिनिस्ट्री की टीम है उन्होंने उस जमीन को एक्सैप्ट कर दिया कि बहुत अच्छी जमीन है और हॉस्पिटल के साथ है। मैं एक बात सदन को बताना चाहता हूं कि अगर तीन मेडिकल कॉलेज में से पहला मेडिकल कॉलेज शुरू होगा तो वह नाहन का ही मेडिकल कॉलेज होगा। क्योंकि हिमाचल के निर्माता डॉ0 यशवन्त सिंह परमार की यह जन्मभूमि है और कर्मभूमि भी रही है, इसलिए इस कॉलेज को सबसे पहले शुरू करेंगे और बाकायदा टीम इंस्पैक्शन कर गई है।

समाप्त

13.03.2015/1455/SS-JT/3

सभापतिः अब माननीय सदस्य एवं कल्याण मंत्री ,श्री धनी राम शांडिल जी चर्चा में हिस्सा लेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः माननीय सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से महामहिम राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश द्वारा 11 मार्च, 2015 को दिए गए अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने जो बोलने के लिए अवसर दिया है मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस सदन की उत्कृष्ट परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए इस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने काफी ओजस्वी विचार रखे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस अभिभाषण में तथ्यों को वर्णित किया गया है

और मैं भी तथ्यों के आधार पर ही इस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव करना चाहूंगा। 25दिसम्बर, 2012 को माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में बनी वर्तमान कांग्रेस सरकार ने कार्यभार सम्भाला। कांग्रेस पार्टी ने अपनी उच्च परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए जो वादे जनता से किये थे, चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किये गए थे, उसे राज्य सरकार का नीति दस्तावेज बनाने का निर्णय किया। पहले ही दिन से इन वादों को पूरी मुस्तैदी से कार्यान्वित करने का संकल्प भी लिया। मुझे यह बात बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा अधिकांश इन वादों और चुनावी घोषनाओं को न केवल पूरा कर लिया गया है बल्कि उससे भी अधिक कार्य सरकार द्वारा आम जन मानस के हित में किया जा रहा है। इससे न केवल प्रशासन को संवेदनशील और पारदर्शी बनाने में एक सकारात्मक भूमिका निभाई गई है बल्कि एक उत्तरदायी प्रशासन प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की आर्थिक, सामाजिक और विकासात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं। विशेष तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार का कार्य अत्यंत सराहनीय भी रहा है। माननीय महोदया, सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और रोजगार प्रदान करने को प्राथमिकता दी है।

जारी श्रीमती के0एस0

/1500/13.03.2015केएस/एजी/1

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जारी---

सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और रोज़गार प्रदान करने को प्राथमिकता दी है और विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों के पदों का सृजन किया है उससे युवाओं को गुणवर्ती शिक्षा और रोज़गार उपलब्ध करवाने में सहायता मिली है । मैं बहुत लम्बे-चौड़े आंकड़ों में नहीं जाना चाहता परन्तु जो 100 नए प्राथमिक स्कूल खोले गए और 160प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत किया गया है उसमें लगभग 23 हजार करोड़ रुपये विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं और निशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करने में भी लगे हैं। महोदया, प्रदेश में जो 14 नए

महाविद्यालय खोले गए हैं, मैं समझता हूं उससे हमारी शिक्षा के स्तर में उन्नति होगी और जैसे माननीय सदस्यों ने कहा कि केवल कॉलेज खोलने से ही शिक्षा उन्नत नहीं होती, मैं इस बात को समझता हूं। मैं समझता हूं कि हमें उसमें जो कमियां हैं, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने भी कही है, अगर कहीं कमी नज़र आती है तो उसे पूरा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि उच्च पाठशालाओं में 788 पद तथा नई स्तरोन्नत वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 1260 पद सृजित किए गए हैं, यह अपने में एक उपलब्धि है। अध्यापकों के अलावा गैर शिक्षक स्टाफ की 954रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा, 905 रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी गई है और 1733 पी.टी.ए. प्राध्यापकों/डी.पी.ई. की सेवाओं को पी.जी.टी./डी.पी.ई. के रूप में अनुबन्ध आधार पर लिया गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के 14104 लोगों को 30 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

/1500/13.03.2015केएस/एजी/2

पिछड़े वर्गों तथा आई.आर.डी.पी. श्रेणी के छात्रों को 9.93 करोड़ रु0 की पुस्तकें निशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। महात्मा गांधी वर्दी योजना के अंतर्गत नवीं तथा दसवीं कक्षा में पढ़ रहे सभी छात्रों को दो जोड़े वर्दी उपलब्ध करवाई गई है जिस पर 14 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के अन्तर्गत व्यवसायिक शिक्षा आरम्भ की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में 100वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में व्यवसायिक शिक्षा शुरू की गई है। इसके अलावा तकनीकी संस्थाओं में 36,633 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं।

माननीय सभापति महोदया, उपरोक्त कदम स्पष्टतया दर्शाते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा का राष्ट्रीय निर्माण में क्या महत्व है। प्रदेश सरकार युवाओं को गुणवर्ती तथा सतत् शिक्षा अत्यन्त सुविधाजनक रूप में उपलब्ध करवा रही है। भविष्य में भी कांग्रेस सरकार का यह प्रयास जारी रहेगा। समाज के उपेक्षित तथा कमजोर वर्गों और महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार प्रतिबद्ध है तथा वर्ष 2014-15 में महिला सशक्तिकरण व बाल कल्याण योजनाओं पर 103.24

करोड़ रुपये का खर्चा किया गया है तथा 18,916 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का 50 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय बढ़ाया गया है ।6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास, किशोरियों तथा गर्भवती धात्री माताओं के लिए सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अंतर्गत सेवाओं का एकत्रित पैकेज प्रदान किया जा रहा है जिसमें

/1500/13.03.2015केएस/एजी/3

स्कूल पूर्व शिक्षा,पूरक पोषाहार तथा स्वास्थ्य जांच शामिल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत 4 लाख 55 हजार 28 9बच्चे 1 ,लाख 2 हजार 830 गर्भवती एवं धात्री महिलाएं लाभान्वित हुई है।

डॉ0 राजीव बिन्दलः सभापति महोदया, प्वाईंट ऑफ ऑर्डर।

श्रीमती आशा कुमारी, सभापतिः माननीय मंत्री जी, एक सैकिण्ड रुकिए। बिन्दल जी, आपका क्या प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है?

डॉ0 राजीव बिन्दलः सभापति महोदया, जितनी मुझे जानकारी है, सदन में हम कागजों की सहायता तो ले सकते हैं परन्तु अपना पूरा का पूरा भाषण लिखा हुआ पढ़ें, ऐसी परम्परा नहीं है। माननीय मंत्री जी शत-प्रतिशत लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, इतना मुझे आपके ध्यान में लाना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः सभापति महोदया, ऐसा है, माननीय सदस्य भी काफी पुराने सदस्य है। सभी पढ़ सकते हैं। धूमल साहब ने हमारा जो मैनिफैस्टो था, उसकी एक-एक लाईन पढ़ी और किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। मंत्री जी भी प्वाइंट देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि पढ़ नहीं सकते। पार्लियामैंट में भी पढ़ा हुआ भाषण पढ़ा जाता है। वहां भी ऐसी कोई परम्परा नहीं है तो आप ऐसी गलत परम्परा मत डालिए।

धूमल जी अ0व0 की बारी में---

श्री प्रेम कुमार धूमल : माननीय सभापति महोदया, आज संसदीय परम्परा के बहुत सबक सीखने को मिल रहे हैं। पहले माननीय मुख्य मंत्री जी हमें उपदेश दे रहे थे लेकिन जब मैंने उनको समझाया तो वे मान गये कि ठीक है। मगर दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने इस सीट को सुशोभित किया हुआ है उससे तो आशा करते थे कि वह इस पीठ को सही सलाह देगा। पार्लियामैंट के साथ-साथ सब जगह यह नियम है कि your maiden speech can be read. आप तो कभी पार्लियामैंट में रह नहीं मगर शांडिल साहब तो पार्लियामैंट में दो बार सांसद रहे हैं। इनको पता है मेडन स्पीच पढ़ी जा सकती है मगर बाकी पेपर्ज का सहारा नहीं लिया जा सकता। आपने मुझे कोट किया। जब आपने मुझे पूछा कि क्या लिखा है तो मैंने आपको पढ़ कर बताया कि आपने क्या लिखा था। मेरी सारी स्पीच तो उसी के क्रिटिसिजम पर आधारित थी। मुझे दुख है कि आप उस पीठ पर पांच साल रहे परंतु पता नहीं क्या पढ़ते रहे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय सभापति महोदया, मैंने तो यही कहा कि ये फिगर पढ़ कर बोल रहे हैं, बाकी सारी स्पीच पढ़कर नहीं है। इस पर आपको एतराज भी नहीं करना चाहिए। कर्नल धनीराम शांडिल पार्लियामैंट के अंदर दो बार सांसद रहे हैं। इनको सारे प्रोसिजर का पता है।

श्री प्रेम कुमार धूमल : सभापति महोदया, कर्नल शांडिल के व्यक्तित्व या उनसे हमें कोई मतभेद नहीं है। हम जानते हैं कि जैसे आप यहां से वहां उधार गये हैं क्योंकि पहले आप भी हमारे साथ ही जनता पार्टी में थे; उसी तरह शांडिल साहब भी कभी हमारे साथ ही थे। इसलिए खुलकर पढ़े हमें इन पर कोई आपत्ति नहीं है, पर नियम के अनुसार नहीं है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : माननीय सभापति महोदया, (---व्यवधान---) I stand corrected.

श्रीमती आशा कुमारी, सभापति : कृपया शांति का दान दें। माननीय सदस्य आपस में बात न करें। मंत्री जी अपना वक्तव्य रख रहे हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : सभापति महोदया, मैं इनको कुछेक तथ्य इसलिए देना चाह रहा था क्योंकि शायद तथ्य पर बात चली थी। इसीलिए कुछेक चीजों को कोट कर रहा था। मुझे आपसे दस मिनट मिले हैं इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि कुछेक तथ्य पढ़ दूं। मैं केवल दो-तीन बिंदुओं पर अपनी बात करना चाहता हूं और फिर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं या काम करने की जो शैली है उस पर सवाल उठते हैं। मेरे हिसाब से विपक्ष में बैठे लोगों का काम भी यही है। लोकतंत्र की गाड़ी सुचारु रूप से तभी चलती है जब पक्ष वालों के साथ विपक्ष एकदम जागरुक रहता है। मगर मैं समझता हूं कि इसी के साथ पॉलिटिकल फिलोसिफी और पॉलिटिकल साईंस के जो टीचर बताते हैं कि कुछेक परम्पराएं निभानी पड़ती है। When I was in the Parliament, Hon'ble former Chief Minister had very kindly pointed out, I remember the applause we got for our Vidhan Sabha. इस विधान सभा का सर्वोपरि नाम है। इस विधान सभा का अनुशासन, इस विधान सभा की कार्य करने की शैली, यहां के कंडक्ट ऑफ बिजनैस has been quoted by very-very senior leaders including the President of India and the Prime Minister of India and it was a very heartening sort of experience for us to hear कि जो हिमाचल प्रदेश विधान सभा है उसमें किस प्रकार से एक-दूसरे की बात सुनी जाती है। फिर उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। ऐसा होता भी रहा है। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। वह सिखाते हैं कि when Speaker stands, nobody speaks. When Speaker stands, there is a pandemonium the House. वह प्रथा तो मुझे नजर नहीं आई। हो सकता है because they are very senior leader. It is really 'छोटा मुंह और बड़ी बात'। मुझे तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। मेरा इस माननीय ----------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

मा0 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री.. जारी...

मेरा इस मान्य सदन में इतना कहना है कि हम बड़े से बड़े चीज़ पर चर्चा करें, बड़े से बड़े गहन चिन्तन करें, डेलिब्रेशन्ज़ करें और उसमें अच्छी तरह से बड़ी वॉयबरेंट डिबेट हो परन्तु हम एक दूसरे की बात सुनने का मादा रखें। यही मेरा कहना है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो ड्रग्ज़ के बारे में बात कही गई है, यह वाकयी विचारणीय विषय है । इसमें न पक्ष का, न विपक्ष का बल्कि देश के युवाओं का, हमारे देश के भविष्य का सवाल है । क्योंकि last time I was given some responsibility in the State of Punjab, I noticed कि जिस देश में वीरों की कहानियां पढ़ी जाती है, जहां गुरूओं का सम्मान होता है । जिसके धरातल पर भारत की सेना मज़बूती से खड़ी रहती है वहां के युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसके लिए कोई एक या दो जिम्मेवार नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें हमारे परिवार, हमारे शिक्षक, हमारा समाज सबको अपनी चिन्तन में सुधार लाना होगा। मैं समझता हूं कि सबको बड़े दृढ़ता से इस विषय को देखना होगा और इसके बारे में कुछ अच्छी नीतियां बनानी होगी । यही मेरा दूसरा विचार था।

अंत में, मैं समझता हूं कि कांग्रेस सरकार की कार्य-प्रणाली और बुनियादी स्तर पर जो आम आदमी के लिए सोच रही है उसकी वजह से आज हम इतना कुछ कर सके हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी की सफल नेतृत्व में और इनके कुशल नेतृत्व में मैं समझता हूं कि हमारी सरकार दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ेगी । पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के सहारे से हम इकट्ठे मिल करके जाएं केन्द्र सरकार से पैसा लायें। जैसे माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने बात कही कि इन लोगों के इन्टरवेंशन से या अन्य कोई व्यक्ति जिनका वहां ज्यादा प्रभाव हो अगर हम अपने प्रदेश के युवाओं के लिए, बेरोज़गार युवकों के लिए, यहां की महिलाओं के लिए और यहां के अच्छे भविष्य के लिए इकट्ठे मिलकर जा कर पैसा मांगेंगे तो न केवल यह हमारे प्रदेश के लिए अच्छा होगा बल्कि एक अच्छी परम्परा, एक अच्छा संदेश और मैं समझता हूं कि एक

13.3.2015/1510/negi/ag/2

सार्थक चिन्तन वाली राजनीतिक प्रणाली भी आगे के लिए सिद्ध होगी। यही मुझे कहना था।

सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द, जय हिमाचल।

समाप्त

13.3.2015/1510/negi/ag/3

सभापति (श्रीमती आशा कुमारी): धन्यवाद शांडिल जी। अब माननीय सदस्य, कर्नल इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

Shri Inder Singh: Thank you, Madam. ...(Interruption)... It's not Colonel to Colonel.

माननीय सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा इस मान्य सदन में चल रही है उसमें हिस्सा लेने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं। इससे पहले कि मैं सब्जैक्ट पर आऊं, मैं सभापति महोदया, आपका ध्यान ऑफिसर्ज़ गैलरी की तरफ दिलाना चाहता हूं । इतनी इम्पोर्टेन्ट चर्चा चल रही है और ऑफिसर्ज़ गैलरी बिल्कुल खाली पड़ी है । It is a very sad reflexes on the functioning of this Government.

कर्नल शांडिल जी ने शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में पहली बात की । अगर हम इस डॉकुमैन्ट को पढ़ें तो पूरे 12 पैराज़ में शिक्षा किस प्रकार से इस प्रदेश में चलाई जा रही है उसपर विस्तृत ब्यौरा दिया गया है । लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वह कुछ और है। आप धडाधड स्कूल और कॉलेजिज़ खोल रहे हैं। जिस संख्या में आपके स्कूलों और कॉलेज़ों की तादाद बढ़ रही है उसी संख्या में आपके स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घट रही है । हमें यह जानकर दुःख होगा कि पिछले एक साल

में पहली से ले करके प्लस टू तक 48049 बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ करके प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लिया है। Where is your Education Policy? आपके स्कूल खाली पड़े हैं, आपको जान करके हैरानी होगी कि सन 2006 में 19 परसेन्ट बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे और आज यह संख्या बढ़ करके 36 परसेन्ट हो गई and it is continuously increasing. यह शहरों में ही नहीं गांवों में भी यह प्रथा चल चुकी है कि लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

/1515/13.03.2015यूके/एजी/1

श्री इन्द्र सिंह--जारी---

एक प्राईवेट स्कूलों में हम बच्चों को भेजेंगे । And these privates schools have taken you for a ride. पहले उन्होंने बच्चों को टाई लगाना शुरु किया तो टाई के शौक में बच्चे प्राईवेट स्कूल जाना शुरु हो गए । जब सरकारी स्कूलों में टाई लगाना एलाऊड हो गया तो प्राईवेट स्कूल वालों ने फिर उन्होंने डेडिकेटिड व्हिकल्ज़ दे दी । अब आप तो डेडिकेटिड व्हिकल्ज़ दे नहीं सकते । इसलिए आपके स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है । इसका एक कारण और है । आज आपके पास 5012 स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या जीरो से 20 है, इनमें 3 प्लस-टू स्कूल भी हैं । जिस प्लस-टू स्कूल में 20 बच्चे पढ़ते हैं, let us think on a higher side, उस स्कूल में क्या कम्पिटिशन होगा बताइए ? What are you doing? आपके प्राईमरी स्कूल में 5 क्लासिज़ में एक बच्चा है और वह बच्चा भी उसका है जो वहां पानी भरती है । आप स्कूल खोलने जा रहे हैं। सत्ता क्या मिल गई आपको आप धड़ाधड़ स्कूल खोले जा रहे हैं । Where is the infrastructure. I strongly feel you should consolidate on the ground rather than increasing your empire unnecessarily. किसको एम्पलायमैंट दे रहे हैं आप ? Your spending on one primary school child is more than Rs. 35,000/- per month.उस पैसे से तो आप उस बच्चे को दुनिया के किसी भी कोने के स्कूल में पढ़ा सकते हो । Your results are not in commensurate with the money you are putting in. और आपको इस विषय में सोचना पड़ेगा । लेकिन हमारे पास ऐजुकेशन मिनिस्ट्री ही नहीं

है । इस मिनिस्ट्री को सरकार ने ऐसी फटकार लगाई है । हमने तो आपको ऐजुकेशन स्टेट मिनिस्टर दिया था, आप उसको बना देते, अच्छा काम चलता । आपके पास मिनिस्टर ही नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर, फाईनैंस मिनिस्टर, so many Ministers and then Education Minister as well, how can he handle? किसके पास छोड़ा हुआ है यह महकमा ? इसलिए इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, आपसे मेरी विनती है । ठीक कहा, विपक्ष के नेता आदरणीय

/1515/13.03.2015यूके/एजी/2

प्रेम कुमार धूमल जी ने ,आपके पास 1117 स्कूल ऐसे हैं जहां सिंगल टीचर है । वह खिचड़ी बनायेगा या बच्चों को पढ़ाएगा ? बताइए मेरे को you have no answer. सिंगल टीचर स्कूल है। आपके पास 216 स्कूल ऐसे हैं जहां 5 से कम बच्चे हैं । Where is the competition? (व्यवधान) आप मत बोलिए प्लीज़ । खिचड़ी बनाने वाला भी वही, पढ़ाने वाला भी वही और खाने वाला भी वही है, सब वही है । there are 447 स्कूल जहां लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं हैं । Consolidate yourself. स्कूल बढ़ाने की जरूरत नहीं है । उसके बाद देखिए ,आपके पास 12669 स्कूल ऐसे हैं जहां बजट ही नहीं है । क्या कर रहे हैं आप समझ में नहीं आ रहा ?क्या पॉलिसी है आपकी? फिर बोल रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़े-बड़े नारे लग रहे हैं , "स्कूल चले हमें" कहां से स्कूल चलें हम ? There are no teachers. So, you have to reinforce your primary education structure. जहां से सब कुछ पनपता है । आपके प्राईमरी स्कूलों में कौन पढ़ते हैं ? माईग्रेटरी लेबर के बच्चे पढ़ते हैं । आपके स्कूलों में सारी फैसेलिटीज़ हैं । खाना मिलता है, वर्दी मिलती है, तकरीबन प्राईवेट स्कूलों से ठीक ही है । Play Ground and every फैसेलिटी है । लेकिन बच्चे नहीं हैं और मास्टर नहीं है । And there is no check on the teachers. I myself personally seen, 4-5टीचर्स कोने में बैठ कर के गप्पे मार रहे हैं who will check them. I have noticed lady school teacher अपने क्लास के बच्चों से 20 मीटर दूर बैठ कर के धूप में मोबाईल सुन रही हैं । Is she paid for that? Who will check it? You have to check it. That is my humble submission. पढ़ाई का माहौल बनाइए । और जब तक आप स्कूलों में प्रि-नर्सरी क्लासिज़ नहीं चलाएंगे तब तक आपके प्राईमरी स्कूलों में बच्चे नहीं जाएंगे । क्योंकि एक बार जो बच्चा प्राईवेट

स्कूल में चला जाता है वह हट कर के सरकारी स्कूल में नहीं आयेगा । Mark my words. -------

/1515/13.03.2015यूके/एजी/3

यह तो कमाल हो गया । फिर आप सैशन के बीच में बदलियां कर देते हैं । आपने ऐसे-ऐसे सलाहकार बनाए हैं जो सैशन के बीच में बदलयिां कर देते हैं । वे यह नहीं सोचते कि बच्चों की ऐजुकेशन हैल्थ पर क्या असर पड़ेगा ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी---

13.03.2015/1520/sls-jt-1

श्री इन्द्र सिंह...क्रमागत

वह नहीं सोचते कि बच्चों की ऐजुकेशन हैल्थ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जब दिसम्बर महीने में सलेबस पूरा होना होता है और रिवीजन करना होता है, उनका सलेबस पूरा नहीं होता but all of a sudden you transfer the teacher. फिर कंटिन्यूटी कहां रहेगी? मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप ऐसी बदलियां बंद कीजिए। आप सैशन-टू-सैशन बदलियां करिए। We have no objection. It is your right. यह हमारी समस्या नहीं है। जैसे-जैसे आप दवा दे रहे हैं, मर्ज़ बढ़ता जा रहा है। जैसे-जैसे स्कूल बढ़ा रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। लार्ड मैकाले ने इस देश में बाबुओं के लिए शिक्षा दी थी so that they have an army of clerks. लेकिन आप लोगों ने भी लार्ड मैकाले का ही काम किया है। सेमि-इलीट्रेट लोग आपने पैदा कर दिए हैं। पांचवीं कक्षा का बच्चा पहली कक्षा का टैक्सट नहीं पढ़ सकता। What is this? आप भी लार्ड मैकाले से कम काम नहीं कर रहे हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। There is a requirement to improve it.

मैं कृषि की बात कर रहा हूं। आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने ठीक कहा है कि पहाड़ों में जवानी व पानी नहीं ठहरते। जवानी नौकरी की तलाश में बाहर चली

जाती है और पानी बह कर नीचे चला जाता है। इनको रोकिए। जवानी को भी और पानी को भी रोकिए। जब आप जवानी और पानी को रोकेंगे तो हम समृद्धशाली होंगे। एग्रीकल्चर में कई समस्याएं हैं। जो हमारे बुजुर्गों की बनाई छोटी-छोटी कूहलें होती थीं वह बंद हो गई हैं या खत्म हो गई हैं। No attention is being paid to those kuhls. उनको रि-एनर्जाईज कीजिए, यह मेरी आपसे विनती है। हमारी उपजाऊ ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं। उनके लिए बुजुर्गों ने डैडिकेटिड कूहलें बनाई थीं। वह खत्म कर दी गईं। आप ज्यादा देर तक इस राज्य में सरकार में रहे हैं, इसलिए उनको रि-ऐनर्जाईज करिए, यह मेरी आपसे विनती है। आवारा पशुओं और जंगली जानवरों की जो perennial problem है, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है।

13.03.2015/1520/sls-jt-2

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, I am thankful that you are one of the three Ministers out here. Rest have all vanished in thin air. बलद्वाड़ा के लिए 40 लाख रुपया माननीय धूमल जी ने दिया था। कितना समय हो गया और वह 40 लाख रुपया सीoएमoओo ऑफिस में पड़ा हुआ है। ...(व्यवधान)... मैडम, आप जल्दी करने के लिए कह रही हैं, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी बोल रहा हूं। उस 40 लाख रुपये को आप ज़मीन पर लगाइए। इन्फलेशन होगी तो वह 40 लाख रुपया और कम हो जाएगा। Kindly do that. सरकाघाट के लिए बड़ी समस्याएं हैं। ...(व्यवधान)... Land is already there, Sir.

सड़कों की बात तो छोड़ ही दीजिए। मेरे चुनाव क्षेत्र में तो मैं सड़कों की बात ही नहीं करूंगा। I think, it is not worth mentioning.

इंडस्ट्री की बात करूंगा। Your total industry is on the periphery of the State. Bring it to the centre of the State. इंडस्ट्री को अंदर लाइए। आप कहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए मार्किट नहीं है; ट्रांसपोर्टेशन चार्जिज बहुत हो गए हैं। ऐसी भी इंडस्ट्री है जैसे इलैक्ट्रौनिक इंडस्ट्री है, इंस्ट्रूमैंटेशन इंडस्ट्री है जिसका एक ट्रक में ही सारा सामान आ जाएगा और उसी ट्रक में सारा सामान नीचे मार्किट में चला जाएगा। Kindly think on these lines. क्योंकि मैं समझता हूं कि you have to

take industry to the people, rather than people to the industry. यह भी आप करिए। यह भी मेरी आपसे विनती रहेगी।

अब मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूंगा। आदरणीय शांडिल जी, you had promised in this very House. एक्स सर्विसमैन को जो आप नौकरी देते हैं, you place them on contract. 45साल की उम्र में आप उसको कंट्रैक्ट पर रखोगे और 50-55 की उम्र में आप उसको रैगुलर बनाओगे; he doesn't get any pensionary benefit. You had promised me in this very House that you will not put them on contract. You will give them regular service. Kindly be generous. यह मेरी आपसे रिक्वैस्ट रहेगी। जो डिप्टी डायरैक्टर सैनिक वैलफेयर हैं,

13.03.2015/1520/sls-jt-3

in every district, we have one authorised. 10में से 8 नहीं हैं। आप क्या सैनिक वैलफेयर देख रहे है। I can question him, Sir, because he is looking after it.

जारी ..गर्ग जी

13/03/2015/1525/RG/JT/1

Social Justice & Empowerment Minister: About the 8 remaining Deputy Directors, we are now almost in the final stages and H.P. Public Service Commission will be interviewing them on the 20th March only, including Director and soon we should be having Deputy Directors also.

Shri Inder Singh: Thank you, Sir. But I don't know how long your final stage is?

यहां पर बाली जी नहीं हैं। वे अपना भाषण देकर चलते बने। लेकिन सरकाघाट एक ऐसी जगह है जहां किसी भी दूसरे डिपो की बसें नहीं आतीं ,प्राइवेट बसें भी बहुत कम चलती हैं। इसलिए हमें और बसें देनी चाहिए जिस प्रकार अन्य स्थानों पर दूसरे डिपो की बसें चलती हैं।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि एक चीज में इन्होंने बहुत तरक्की की है जो बहुत प्रशंसनीय है जिसमें 17% इन्क्रीज हुआ है वह है लीकर। जो लीकर की शॉप्स हैं उनका जो आपको राजस्व प्राप्त होता है उसमें 17% की वृद्धि हुई है।--(घण्टी)--यह क्या चीज है, आप मुझे बताइए।

सभापति महोदया, आपकी अनुमति से अन्त में, मैं भ्रष्टाचार के बारे में दो शब्द कहूंगा। जो सरकाघाट एन.ए.सी. है वहां गारबेज डिसपोजल के लिए तीन लाख रुपये का कॉन्ट्रेक्ट हुआ और जब मैं वहां देखने के लिए गया ,तो there is nothing there. Not even a single spade of earth was dug out or something. और तीन लाख रुपये डकार गए। यहां अधिकारी दीर्घा में मुख्य सचिव नहीं बैठे हैं। मैंने मुख्य सचिव को पर्सनली लिखकर कम्पलैंट की कि it is open loot of public money. मैंने सारे डॉक्युमैंट्स 11 मार्च, 2014 को दिए। On 13th March, 2014 he wrote a letter to Director-General of Police with a copy to me. Nothing has happened. He gave them one-month time to find out and let him know. But nothing happened and I went after two months to him with another application. उस पर ऐक्शन हुआ। सितम्बर में विजिलैंस, मण्डी को उन्होंने पत्र लिखा कि आप इस पर जांच कराइए and it becomes a clear-cut case of corruption. You take action. No action has been taken. I am the complainant. मैंने अपनी विटनेस दी है। I gave a witness in a separate room. But nothing has happened. What is this Government doing? आप भ्रष्टाचार

13/03/2015/1525/RG/JT/2

को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? एन.ए.सी., सरकाघाट में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है , आप उसका अन्दाजा नहीं लगा सकते। यही मेरी आपसे विनती है।

सभापति महोदया, अब मैं स्टाफ नर्सिस की बात करता हूं। 1700 डम्मीदवारों ने स्टाफ नर्सिस के लिए ऑन लाईन आवेदन दिए। एच.एल.एल. ने उनको शॉर्ट-लिस्ट किया ,माननीय मंत्री जी 410 ,शॉर्ट-लिस्ट किए गए। शॉर्ट-लिस्ट करने के क्या मापदण्ड रहे होंगे, that should be transparent. और इस शॉर्ट-लिस्टिंग में जो 410 की शॉट-लिस्ट बनी उसमें मण्डी सदर से 144 हैं। उसमें से कई कांस्टीटियूएन्सीज़ गायब हो गईं। I earnestly request you, Sir, to kindly look into this aspect. Let us have some value for the merit. और कांगड़ा के 79 हैं। मैं तो ऐसा समझता हूं कि this Government is like a rocking-horse. It is functioning like a rocking-horse जो हिलता तो नजर आता है ,लेकिन आगे नहीं जाता। You are just static where you are. बल्कि डिग्रेड हो रहे हैं ,प्रदेश को पीछे ले जा रहे हैं। Please get out of that rocking-horse and work on the ground. मंत्री लोग, जो माननीय मंत्री हैं, you are not for your own Constituency. मंत्री पूरे प्रदेश का होता है। 144 स्टाफ नर्सिस, सभी स्थानों की होनी चाहिए ,मण्डी की भी होनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे विनती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : मण्डी में तीन क्षेत्र हैं।

Shri Inder Singh: Only Mandi, Sir. अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि हम अपना सारा ध्यान स्कूलों में टीचर्स पैदा करने में लगा रहे हैं। आपको हैरानी होगी ,

Contd…ms/jt

13/3/2015/1530/MS/Jt/1

श्री इन्द्र सिंह जारी--------

आपको हैरानी होगी कि there are 67710 TGTs we have in our kitty. और आप साल में 500 भर्ती करते हैं और हजारों फिर नये साल में पैदा हो जाते हैं। आप इनका क्या करेंगे? What will you do with them? इसलिए जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो उनको प्रौपर एडवाइस देनी चाहिए, यह मेरी आपसे विनती है।

अन्त में आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के बारे में कहूंगा कि बच्चे का कैसे पालन-पोषण करना चाहिए। हरेक मदर को आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के बारे में समझाने की जरूरत है कि वह बच्चे को किस तरह से बड़ा करे। Art of parenting is totally missing in our concept. मेरी आपसे विनती है कि जो आपके आशा वर्कर्ज हैं, उनके माध्यम से भी गांव-गांव में जाकर आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की ट्रेनिंग दी जा सकती है। That is very important. यही मेरी आपसे विनती है। आपका जो यह पुलिंदा (राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति को दिखाते हुए) है, I am really thankful to the Governor that he did not waste his time on reading the entire part. He only gave you salutation in the first and thanked you in the last.

With these words , Madam, I am thankful to you for giving me time. Thank you very much.

13/3/2015/1530/MS/Jt/2

सभापति(श्रीमती आशा कुमारी): धन्यवाद माननीय सदस्य। अब चर्चा में कुलदीप कुमार जी भाग लेंगे।

श्री कुलदीप कुमार: सभापति महोदया ,जो यहां पर माननीय सदस्य श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है और जिसका अनुसमर्थन श्री बंबर ठाकुर जी ने किया है ,उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सब माननीय सदस्य जानते हैं कि यह एक परम्परा है। हर वर्ष महामहिम राज्यपाल महोदय सरकार की एक साल की जो कारगुजारी होती है, जो काम हुए होते हैं, उनको अपने अभिभाषण में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है। सभी माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ हैं और माननीय विपक्ष के नेता भी वरिष्ठ सदस्य हैं। आप लोग एक बात तो जरूर मान रहे हैं कि महामहिम ने अपना

अभिभाषण पढ़ा नहीं लेकिन उनका धन्यवाद किया है। लेकिन बीच में आप एक शब्द खा गए। उन्होंने यह कहा था कि इस अभिभाषण को "पढ़ा हुआ" समझा जाए। उस शब्द को आप खा रहे हैं। महामहिम के कहने पर सारा काम चलता है। उनकी बात का आदर होना चाहिए। कोई कारण रहा होगा कि वह अभिभाषण को पढ़ नहीं पाए। जब उन्होंने कह दिया कि पढ़ा हुआ समझा जाए तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने इसे पढ़ दिया और उसके बाद उस अभिभाषण पर विपक्ष के लोग बार-बार चर्चा भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि धन्यवाद प्रस्ताव ठीक है क्योंकि अभिभाषण पढ़ा हुआ है। इसीलिए बारी-बारी आप इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। इसलिए इस बात का कोई मतलब नहीं रहता कि अभिभाषण को पढ़ा जाए या पढ़ा हुआ समझा जाए क्योंकि महामहिम का एक बड़ा उच्च स्थान है। हम उनका मान-सम्मान करते हैं।

दूसरे, मुझे बड़ी चिन्ता हुई। मैं विपक्ष के नेता को वर्ष 1993 से जानता हूं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा---------

13.03.2015/1535/जेके/जेटी/1

श्री कुलदीप कुमारः-----**जारी**---

इनके साथ बड़ा लम्बा सफर किया है। हम इकट्ठे चले। लेकिन आज जो इन्होंने भाषण दिया उसमें कुछ फर्क देखने को मिला। पता नहीं उसके क्या कुछ कारण थे? पता नहीं क्या बात थी या कोई शैडो थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या शैडो थी? आज वह पैनापन नहीं था, जो पैनापन पहले हुआ करता था वह पैनापन आज नज़र नहीं आया। आपने कांग्रेस का मेनिफेस्टो भी पकड़ा लेकिन उसमें भी आपने रस्मी तौर पर जो-जो नहीं हुआ था उसको पढ़ लिया और जो हुआ है उसको छोड़ दिया। इसलिए आज मुझे यह चिन्ता हो रही थी कि आपका जो भाषण था उसमें कुछ पैनापन नहीं था। यहां पर कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मेनिफेस्टो को एक नीतिगत दस्तावेज़ बनाया हुआ है। उसमें आपने कहा कि उस मेनिफेस्टो में किये गये वायदे पूरे नहीं हुए हैं। इसमें यह कहा गया है कि अधिकांश वायदे पूरे किये गये हैं। यह नहीं कहा है कि सब वायदे पूरे किये गये हैं। जो वायदे नहीं हुए हैं वे आगे पूरे हो जाएंगे। सरकार के पास अभी काफी समय है उन वायदों को पूरा करने के लिए लेकिन जो

पार्टी के वायदे हैं उनको पूरा करने की कांग्रेस सरकार की एक नीति है। मैं सरकार का और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 में प्रदेश का ग्रोथ रेट 6.2 परसेंट है और राष्ट्रीय स्तर पर वह ग्रोथ रेट 4.9 परसेंट है। इसी के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश की पर-केपिटा इन्कम 92,300/-रूपये है, जो कि वर्ष 2012-13 में 83,899/-रूपये थी। इसमें भी तरक्की हुई है। मैं इसी साल के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पर-केपिटा इन्कम 74,920/-रूपये है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें भी ग्रोथ रेट व पर-केपिटा इन्कम की सराहना की गई है। उसके लिए मैं सरकार का और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा विधायकों की प्राथमिकता की जो स्कीमें हैं, जो आर.आई.डी.एफ. की हैं उसमें भी 500 से बढ़ाकर 765 करोड़ रूपया कर दिया है। आप लोगों को इसका तो धन्यवाद करना चाहिए। विधायकों की जो 100 प्राथमिकताओं की स्कीमें है उसमें पहले से अधिक मंजूर करवा दी है। आप सभी को इसका धन्यवाद

13.03.2015/1535/जेके/जेटी/2

करना चाहिए। यह प्रदेश की डवैल्प्मैंट का एक खाका है। इसके लिए आप लोगों को सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि कर्नल इन्द्र सिंह जी बहुत भोले-भाले हैं और मैं इन्हें शरीफ समझता था।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

/1540/13.03.2015एस0एस0/ए0जी0/1

श्री कुलदीप कुमार क्रमामतः

मैं इनको बड़ा शरीफ समझता था लेकिन इन्होंने भी एजुकेशन के ऊपर बोला। ये बहुत शरीफ आदमी हैं और मेरे साथी हैं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शिक्षा के क्षेत्र में इनके कोई स्कूल नहीं खुले होंगे तो उसकी वजह से इनको तकलीफ हो रही है या फिर ज्यादा स्कूल खुल रहे हैं उससे तकलीफ हो रहे हैं। आज इन्होंने कहा कि शिक्षा

मंत्री होना चाहिए। जो विभाग मुख्य मंत्री के पास हो, उस विभाग का तो सौभाग्य होता है कि उसका ज्यादा विकास होता है। उसमें ज्यादा काम होता है और मुख्य मंत्री उसी तरह उसमें काम कर रहे हैं। जैसे कि बताया गया, यहां पर नौकरियों की बात हुई। स्कूल तो सबने बताए कि कितने खुले। 100 नये प्राईमरी स्कूल खुल गए। 234 हाई स्कूल खुल गए। 225 प्लस-टू स्कूल खुल गए। 14नये स्कूल खुल गए हैं। स्टाफ में भी 788 पद पढ़ाई के लिए और 1260 अन्य पद सृजित किये गए हैं। पैरा टीचर, जिन्होंने 10 साल रेगुलर सर्विस की, उनको पक्का कर दिया गया है। 684 टी0जी0टी0 और 695 सी0एण्ड0वी0 को भर्ती किया गया है। पी0टी0ए0 वालों को भी अब कंट्रैक्ट में तबदील कर दिया गया है। आपको याद होगा कि ऊना जिला में हमारे स्वां का बड़ा भारी नुकसान हुआ करता था। किसानों का नुकसान हुआ करता था। खड्डों का नुकसान हुआ करता था। विशेषकर किसानों की फसलों का नुकसान हुआ करता था। जमीनों का नुकसान हुआ करता था। उससे सारे ऊना जिला के लोग परेशान थे। --(व्यवधान)--सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। इन्होंने मेरा काफी टाइम खराब कर दिया।

सभापतिः माननीय सदस्य, आपका टाइम पूरा हो गया है, आप वाइंड अप करें।

श्री कुलदीप कुमारः आज 922 करोड़ का प्रोजैक्ट जो है वह हिन्दुस्तान का सबसे पहला बड़ा प्रोजैक्ट है जोकि ऊना जिला में माननीय मुख्य मंत्री और हमारी सरकार ने दिया है। --(व्यवधान)--काम हम करते रहे और फट्टे आप लगाते रहे। हमने 106 करोड़ का फर्स्ट फेज का काम किया और फट्टा लगाने आप आ गए। सैकिण्ड फेज में भी आप फट्टा लगाने आ गए। --(व्यवधान)-- आप चिन्ता मत करें। --(व्यवधान)--

/1540/13.03.2015एस0एस0/ए0जी0/2

सभापतिः माननीय सदस्य, एक सैकिंड रूकिये। प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी कुछ कहना चाहते हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः सभापति महोदया, हम इसलिए थोड़ी देर के लिए गए थे कि ये कुछ ऐसा ही बोलेंगे। आपने स्वां चैनेलाइजेशन के लिए कौन-सा प्रोजैक्ट मंजूर करवाया था? 1998 में हमारी सरकार के टाइम 15 अप्रैल, 1999 को स्लोह में 106

करोड़ का मैंने शिलान्यास किया। पहले बात सुन लो। पैसा देकर काम शुरू किया। वह कम्प्लीट हुआ। आपने संतोखगढ़ से पंजाब तक का करवाया। पंजाब के साथ कोई समझौता नहीं किया। पंजाब की एग्रीमैंट नहीं हुई जो इंटरस्टेट था। वह काम चला नहीं। आपने संतोखगढ़ के पास जो नदी पर पुल बनना था, वह 715 मीटर की लम्बाई वाला था। सभापति महोदया, इन्होंने 415 मीटर की लम्बाई का नक्शा बना कर नाबार्ड को भेज दिया। नाबार्ड ने कहा कि 300 मीटर जब पानी का रहेगा तो वह हमारे पुल को वैसे ही ले जायेगा। वह एप्रूव नहीं हुआ। वह हमने बाद में करवाया। आपके चुनाव क्षेत्र गगरेट में जाकर मैंने 335करोड़ रुपये के सैकिंड फेज का 14 अप्रैल, 2008 को शिलान्यास किया। यह 922 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट हमने पास करवाया था। आप आ गए हैं इसलिए आप फट्टे लगा रहे हैं। तुम्हारे हिस्से वे फट्टे भी नहीं आ रहे, वे भी संतोखगढ़ में नीचे हडोली में जा कर लग रहे हैं।

सभापतिः माननीय सदस्य, श्री कुलदीप कुमार जी, आप बोलिये।

श्री कुलदीप कुमारः बड़ी अच्छी बात पूर्व मुख्य मंत्री जी ने कही। मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन बीच में सदस्य टोका-टाकी कर रहे थे। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी को पता होगा कि 1994 में फ्लड प्रोटैक्शन डिवीजन वहां पर खोला गया था।..

जारी श्रीमती के0एस0

/1545/13.03.2015केएस/एजी/1

श्री कुलदीप कुमार जारी---

वह इसी मकसद से खोला गया था कि जो वहां की स्वां है, उससे नुकसान होता है और उसने सारी डी.पी.आर. वगैरह, सारी फोर्मेलिटी वगैरह कम्पलीट की जब सारा प्रोजैक्ट अप्रूव हो गया, तब हमारी सरकार चली गई और शिलान्यास इन्होंने कर दिया। यही तो मैं कह रहा हूं और जो सैकिण्ड फेज़ का भी था, उसके शिलान्यास की भी हमारी सरकार ने डेट रखी हुई थी लेकिन उसके बाद हमारी सरकार चली गई, उसका भी शिलान्यास आपने रखा।--- (व्यवधान) ---मैंने कहां इन्कार किया।

श्रीमती आशा कुमारी, सभापतिः माननीय सदस्य, वाईंड अप करिए। आपस में चर्चा न करें, वाईंड अप करें।

श्री प्रेम कुमार धूमलः सभापति महोदया, ये गलत तथ्य बता रहे हैं। आपने जो प्रोपोज़ल बनाई थी उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश सरकार को नाबार्ड से कर्जा लेना था । हमने उसको पास करवाया AIBP में। उसमें 90 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार ने देना था और 10 प्रतिशत हमने देना था। अब आपको पता ही नहीं है कि क्या हुआ तो हमारी बात को माना करो।

श्री कुलदीप कुमारः मुझे सारा पता है। आप सैकिण्ड फेज़ की बात कर रहे हैं । सारी प्रोपोज़ल हमने दी थी। इसी से पहले पैसा ले रहे थे लेकिन उनकी कमीशन ज्यादा थी उसके बाद हमने कहा कि इनको नहीं देंगें क्योंकि हम इनको इतनी कमीशन नहीं दे सकते फिर नाबार्ड के लिए हमने अप्लाई किया। फिर आपकी सरकार आई उसके बाद आपने

/1545/13.03.2015केएस/एजी/2

शिलान्यास किया। अच्छी बात है, आपने शिलान्यास किया । मेरा इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है।

श्री प्रेम कुमार धूमलः हमने शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया धलेड़ा में।

श्रीमती आशा कुमारी, सभापति :माननीय सदस्य, कृपया वाईंड अप करें।

श्री कुलदीप कुमारः सभापति महोदया, इससे ऊना जिला के किसानों का बहुत फायदा हुआ है और 8904 एकड़ जमीन भी क्लेम हुई। अब उस जगह में किसान लोग आलू बीज रहे हैं, सब्जियां बीज रहे हैं और उनकी इन्कम का साधन बना है। आज स्वां जो कि एक river of sorrow होती थी वह आज river of happiness हो गई है। इसके अलावा और भी फायदा हुआ, जो खड्डे थीं, जिनकी वजह से कई बस्तियों की सड़कों तक अप्रोचिज़ नहीं थी, उनके ऊपर अब सड़कें बन गई है, जिन बस्तियों तक सड़क नहीं जा सकती थी वहां सड़क जा रही है। इस तरह से उस

प्रोजैक्ट से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवादी हूं। इसी तरह से छौंछ नदी में 180 करोड़ रुपये से चैनेलाईजेशन हो रही है। इसी के साथ-साथ मेरे क्षेत्र में, चिन्तपूरनी में 45 करोड़ रुपये के मल्टी प्रोजैक्ट का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया। वहां पर जो श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ रही है, उनको उससे फायदा होगा। इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदया, अभी राजीव बिन्दल जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने बेरोज़गारों को ठगा है। बिन्दली जी, अभी हाल ही में एक साल

/1545/13.03.2015केएस/एजी/3

पहले लोकसभा के इलैक्शन हुए। आपने लोगों से वायदा किया कि काला धन 100 दिन के अन्दर-अन्दर वापिस लाएंगें और 15-15 लाख रुपये हरेक आदमी के खाते में जाएगा। ---(व्यवधान)---

श्रीमती आशा कुमारी, सभापति :कृपया माननीय सदस्य को डिस्टर्ब न करें।

श्री कुलदीप कुमारः सभापति महोदया, 100 दिन बीत गए, 9 महीने भी बीत गए, 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है लेकिन आज तक वह 15 लाख क्या पांच हजार रुपये भी नहीं आए। --(व्यवधान)---- पांच पैसे भी नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि क्या आपके खाते में कुछ आया? अगर आया हो तो बता दें मगर हमारे खाते में तो कुछ नहीं आया। इसी तरह से एक जन-धन योजना चला दी । सारे भारतवासी खाता खुलवाने के लिए चल पड़े।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

13.3.2015/1550/ag/av/1

श्री कुलदीप कुमार ------ क्रमागत

एक जन-धन योजना चला दी और सारे भारतवासी अपना खाता खुलवाने चल पड़े कि 15 लाख रुपये आयेंगे। 15 लाख तो क्या उसमें आज तक एक पैसा नहीं आया। आपको हर समय सोनिया गांधी की तकलीफ लगी रहती है। अब आपका हाल देखो।

(---व्यवधान---) अब आप छेड़ते हैं। आपने कहा था कि देश को बिकने नहीं देंगे, देश को झुकने नहीं देंगे। केंद्र में आपकी सरकार आने के बाद बोर्डर पर कितनी बार गोलियां चली हैं। (---व्यवधान---) फौजी शहीद हुए, अफसर शहीद हुए। आपने मसरत आलम को छोड़ दिया। उसके ऊपर 120 आदमियों को मारने का आरोप है, उसको छोड़ दिया। आप क्या कर रहे हैं, एक ईमानदार आदमी (---व्यवधान---) आप छेड़ेंगे तो मैं कहूंगा। आप एक उग्रवादी को छोड़ रहे हैं। मगर पूर्व प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह, जिनको सारी दुनिया जानती है कि ऑनैस्ट आदमी है; भारतीय जनता पार्टी वाले भी जानते हैं। जापान की सरकार ने उनको हाइऐस्ट अवार्ड से सम्मानित किया। मगर आप क्या करने जा रहे हैं (---व्यवधान---) वह भी आपके पिंजरे का पंछी है। आप एक ईमानदार आदमी के ऊपर भी एलिगेशन लगा रहे हैं। आप ठगने की बात करते हैं, आपने तो पूरे हिन्दुस्तान को ठग दिया है।

सभापति महोदया, मैं ज्यादा न कहता हुआ अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

समाप्त

13.3.2015/1550/ag/av/2

श्रीमती आशा कुमारी, सभापति : अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2015 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **श्री सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक 13.3.2015 **सचिव।**